FOCUS NEWS
फोकस न्यूज

...आपका अपना अखबार

राष्ट्रीय संस्करण। नई दिल्ली। शुक्रवार 27 मार्च 2026। नवमी, चैत्र मास, कृष्ण पक्ष। 2083 विक्रम संवत । पेज – 12 । मूल्य 2 रु । वर्ष : 13। अंक : 254

उपराष्ट्रपति ने अक्षरधाम मंदिर में किया दर्शन, साझा किया आध्यात्मिक अनुभव

। कृष्णा अग्रवाल ।

नई दिल्ली, फोकस न्यूज, राष्ट्रीय राजधानी में स्थित स्वामीनारायण अक्षरधाम मंदिर में आज भारत के उपराष्ट्रपति ने पहुंचकर दर्शन–पूजन किया और भारतीय आध्यात्मिक परंपरा के प्रति अपनी श्रद्धा व्यक्त की। इस अवसर पर उन्होंने अपने आधिकारिक सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म 'एक्स' (पूर्व में ट्विटर) पर भी अपने अनुभव साझा किए, जो तेजी से वायरल हो रहे हैं। उपराष्ट्रपति ने अपने संदेश में अक्षरधाम मंदिर की भव्यता, शिल्पकला और आध्यात्मिक वातावरण की सराहना करते हुए इसे भारतीय संस्कृति और सनातन मूल्यों का अद्भुत प्रतीक बताया। उन्होंने मंदिर परिसर में बिताए गए समय को "शांति और आध्यात्मिक ऊर्जा से परिपूर्ण अनुभव" बताया। दौरे के दौरान उपराष्ट्रपति ने भगवान स्वामीनारायण के दर्शन किए तथा देश और विश्व में शांति, समृद्धि एवं मानव कल्याण की कामना की। मंदिर प्रशासन की ओर से उनका पारंपरिक स्वागत किया गया और उन्हें परिसर की सांस्कृतिक प्रदर्शनी, स्थापत्य कला और आध्यात्मिक संदेशों से अवगत कराया गया। अक्षरधाम मंदिर, जो भारतीय संस्कृति, वास्तुकला और आध्यात्मिक विरासत का वैश्विक प्रतीक है, समय–समय पर देश–विदेश के प्रमुख नेताओं और गणमान्य व्यक्तियों के आकर्षण का केंद्र रहा है। यहां आने वाले अतिथि मंदिर की भव्य संरचना, सूक्ष्म नक्काशी और आध्यात्मिक वातावरण से प्रभावित हुए (शेष पेज दो पर)

सीएम रेखा गुप्ता ने छात्राओं को साइकिलें वितरित कीं

नयी दिल्ली, फोकस न्यूज, दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने दुर्गा अष्टमी के अवसर पर शालीमार बाग विधानसभा क्षेत्र के एक सरकारी स्कूलों में इस वर्ष 10वीं कक्षा में प्रवेश लेने वाली 1100 छात्राओं को साइकिलें वितरित कीं। मुख्यमंत्री ने कहा कि इस पहल का उद्देश्य यह है कि छात्राओं को स्कूल आने–जाने में आसानी हो। इस कार्यक्रम के दौरान, गुप्ता ने छात्राओं को साइकिल सौंपते हुए उनसे बातचीत भी की। वह शालीमार बाग विधानसभा क्षेत्र से ही विधायक हैं। उन्होंने पत्रकारों से कहा, "हमने देखा है कि कभी–कभी लड़कियों को घर से स्कूल जाने में दिक्कतें आती हैं। अब साइकिल की मदद से लड़कियां बिना किसी परेशानी के अपने घर और स्कूल आ जा सकेंगी।" गुप्ता ने कहा कि इस पहल से बालिकाओं की शिक्षा में आने वाली बाधाओं को दूर करने में मदद मिलेगी। मुख्यमंत्री ने 'एक्स' पर कहा कि मां के रूप में इन कन्याओं का पूजन केवल एक परंपरा नहीं, बल्कि यह स्मरण है कि जहां बेटियों का सम्मान होता है, वहीं सच्ची समृद्धि का वास होता है। उन्होंने कहा, "इसी श्रद्धा और संकल्प के साथ आज 1100 बेटियों को साइकिलें प्रदान की गईं। इस वर्ष से हमारी सरकार ने बजट में दिल्ली के सरकारी स्कूलों में पढ़ने वाली नौवीं कक्षा में उत्तीर्ण 1,30,000 बेटियों को साइकिल प्रदान करने का प्रावधान किया है। इससे उन्हें आने–जाने में सुविधा होगी, पढ़ाई बीच में छोड़ने की दर कम होगी और माता–पिता की चिंता भी कम होगी।" मुख्यमंत्री ने कहा, ''दिल्ली का भविष्य इन बेटियों की उड़ान से ही (शेष पेज दो पर)

दिल्ली पीडब्ल्यूडी ने पीएनजी पाइपलाइन बिछाने का काम तेज करने के लिए सड़क मरम्मत शुल्क माफ किया

दिल्ली के लोक निर्माण विभाग (पीडब्ल्यूडी) ने पीएनजी पाइपलाइन बिछाने की प्रक्रिया तेज करने के लिए अब सड़क खोदने की अनुमति आवेदन मिलने के 24 घंटे के अंदर देने का फैसला किया है।

एशियाई खेलों में पदक जीतने के 'अधूरे काम' को पूरा करना चाहती हैं मीराबाई चानू

तोक्यो ओलंपिक की रजत पदक विजेता भारोत्तोलक मीराबाई चानू ने कहा कि एशियाई खेलों में पदक जीतना इस साल उनका सबसे बड़ा लक्ष्य है। पिछले एक दशक से अधिक समय से मीराबाई चानू भारतीय भारोत्तोलन का चेहरा रही हैं।

'पटना मरीन ड्राइव' बदलते बिहार की सुखद तस्वीर, देशभर से देखने आ रहे हैं लोग: सम्राट चौधरी

उपमुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने कहा कि पटना में बने 'मरीन ड्राइव' (जेपी गंगा पथ) को देखने के लिए देशभर से लोग आ रहे हैं और यह बदलते बिहार की सुखद तस्वीर है।

मोबाइल : जरूरत या जिंदगी

संचार के इस युग में सभी तीव्र गति से काम चाहते हैं । पलक झपकते ही सूचनाओं का अंबार खड़ा हो जाना, इस युग की बहुत बड़ी देन भी कहीं जा सकती है। मुख से बोलते ही जानकारी का खजाना हमारे सामने है।

सनी लियोन वाला किरदार निभाएंगी तमन्ना भाटिया

एकता कपूर की फिल्म 'रागिनी एमएमएस' के तीसरे पार्ट 'रागिनी एमएमएस 3' के लिए एक्ट्रेस तमन्ना भाटिया का नाम फायनल हो चुका है। सनी लियोन की तरह तमन्ना भी अब इस फिल्म के जरिए अपने हुस्न के जलवे दिखाने के लिए पूरी तरह तैयार हैं।

आखिर क्यों देश भर में निरंतर लोकप्रिय हो रहा है विकास का उत्तर प्रदेश मॉडल

समय की सजीव सरगम में जब विकास की धारा दिशाओं को द्रुत गति से बदलती है, तब कुछ प्रदेश ऐसे होते हैं जो परिवर्तन के प्रतीक बन जाते हैं। उत्तर प्रदेश आज उसी परिवर्तन, प्रगति और प्रबंधन का पर्याय बनकर उभर रहा है।

युद्ध से गोंद में और तेजी के आसार

देसी गोंद का उत्पादन इस बार कम हुआ है तथा ईरान इजरायल युद्ध से गोंद का आयात घट गया है। इसके अलावा ऊंचे भाव होने के साथ साथ माल आने में रिस्क होने से आयातक सौदे कम किए हैं।

मुख्यमंत्री सुक्खू ने 62वां जन्मदिन मनाया, समावेशी विकास पर ध्यान केंद्रित करने की बात दोहराई

शिमला, हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू का 62वां जन्मदिन उनके आधिकारिक आवास पर बड़े उत्साह और उमंग के साथ मनाया गया। समारोह के दौरान, सुक्खू ने राज्य के समावेशी विकास, समृद्धि और समग्र विकास को सुनिश्चित करने के लिए आने वाले महीनों में प्रगतिशील और प्रभावशाली निर्णय लेने की अपनी अटूट प्रतिबद्धता दोहराई। पार्टी कार्यकर्ताओं, मंत्रिमंडल के सहयोगियों, अधिकारियों और नागरिकों सहित विभिन्न क्षेत्रों के लोग बड़ी संख्या में एकत्रित हुए और सुक्खू को अच्छे स्वास्थ्य, दीर्घायु और निरंतर नेतृत्व के लिए अपनी शुभकामनाएं दीं। इस अवसर (शेष पेज दो पर)

उत्तर प्रदेश में पिछले नौ सालों में तीन गुना बढ़ी महिला श्रमशक्ति: मुख्यमंत्री

गोरखपुर (उप्र), फोकस न्यूज, उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने दावा किया कि उनके नौ साल के कार्यकाल में सरकारी तथा गैर सरकारी क्षेत्रों में महिला श्रम शक्ति में तीन गुना इजाफा हुआ है। मुख्यमंत्री ने गोरखपुर के मदन मोहन मालवीय प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय में पावरग्रिड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया द्वारा कॉर्पोरेट सामाजिक दायित्व कोष से 144 छात्राओं के लिए छात्रावास निर्माण के वास्ते भूमि पूजन तथा शिलान्यास एवं साइबर फॉरेंसिक अनुसंधान केंद्र का उद्घाटन करने के बाद आयोजित कार्यक्रम को संबोधित कर रहे थे। उन्होंने इस अवसर पर तीन शिक्षकों तथा दो छात्रों को उत्कृष्ट शोध के लिए सम्मानित भी किया। योगी आदित्यनाथ ने इस अवसर पर कहा कि वर्ष 2017 में उनकी सरकार बनने से पहले प्रदेश में महिलाओं की सुरक्षा एक (शेष पेज दो पर)

दुर्घटनाओं को रोकने के लिए रेल नेटवर्क पर सबवे का निर्माण करें: वैष्णव

नयी दिल्ली, फोकस न्यूज, रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने सभी रेलवे जोन के अधिकारियों के साथ एक कार्यशाला आयोजित की और उन्हें निर्देश दिया कि वे आवासीय क्षेत्रों के आसपास सबवे बनाने की योजना तैयार करें ताकि लोग सुरक्षित रूप से रेल पटरियों को पार कर सकें। एक आधिकारिक बयान के अनुसार, रेल मंत्रालय ने अगले पांच से छह वर्षों में देशभर में रेलवे पटरियों के आसपास के सभी आवासीय क्षेत्रों को शामिल करने की योजना बनाई है। वैष्णव ने अधिकारियों से सबवे को इस तरह से तैयार करने को कहा कि लोग इनका इस्तेमाल करने में सहज महसूस करें और बरसात के मौसम में इन सबवे में जलभराव की समस्या न हो। मंत्रालय ने बयान में कहा, ''ये सबवे उन बस्तियों के निकट बनाए जाएंगे जहां स्थानीय लोगों को अपनी दैनिक गतिविधियों के लिए अक्सर पटरियों को पार करना (शेष पेज दो पर)

कच्चे या भुने मेवे, सेहत के लिए क्या है बेस्ट?

मेवों का सेवन सेहत के लिए बहुत लाभकारी माना जाता है। इसमें फैट, प्रोटीन, फाइबर, विटामिन और मिनरल्स होते हैं। बाजार में मेवे दो तरह से बिकते नज़र आते हैं। पहला कच्चा और दूसरा भूना। लेकिन एक सवाल जो ज्यादातर लोगों के मन में रहता है वो है कि कच्चे मेवे या भुने मेवे, सेहत के लिए कौन सा ज्यादा फायदेमंद होता है। अगर आप भी इस सवाल का जवाब ढूंढ रहे हैं तो घबराने की जरूरत नहीं है। यहां हम आपको बताने जा रहे हैं कि कौन सा सेहत के लिए बेस्ट है।

कच्चे मेवे : ये मेवे बिना किसी प्रोसेसिंग के सीधे प्रकृति से आते हैं।

फायदे: इनमें प्राकृतिक विटामिन जैसे विटामिन म और एंटीऑक्सीडेंट्स पूरी तरह सुरक्षित रहते हैं, जो गर्मी के संपर्क में आने से नष्ट हो सकते हैं। इनमें अलग से तेल या नमक नहीं होता।

नुकसान: कच्चे मेवों में फाइटेट्स और लेक्टिन्स हो सकते हैं, जो शरीर के लिए पोषक तत्वों को सोखना थोड़ा मुश्किल बना देते हैं। साथ ही, नमी के कारण इनमें बैक्टीरिया जैसे साल्मोनेला का खतरा थोड़ा अधिक रहता है। (शेष पेज दो पर)

महानवमी के दिन प्रोफेशन के अनुसार करें दान, मां सिद्धिदात्री की कृपा से करियर में छुएंगे ऊंचाइयां

चैत्र नवरात्रि का पावन पर्व 27 मार्च के दिन सिद्धिदात्री माता की पूजा के साथ समाप्त हो जाएगा। नवरात्रि के आखिरी दिन पर माता सिद्धिदात्री की पूजा के साथ ही कई तरह के उपाय करना भी बेहद शुभ होता है। अगर आप अपने करियर क्षेत्र में उन्नति करना चाहते हैं तो नवरात्रि के आखिरी दिन यानि महानवमी पर कुछ चीजों का दान कर सकते हैं। इन चीजों का दान करने से आप उन्नति करते हैं और करियर क्षेत्र में आ रही हर परेशानी का आपको हल मिलता है।

महानवमी के दिन प्रोफेशन के अनुसार करें इन चीजों का दान– अगर आप डॉक्टर है या मेडिकल फील्ड से जुड़े है तो आज आपको चने या चने की दाल का दान करना चाहिए। अगर आप इंजीनियरिंग फिल्ड से जुड़े है (शेष पेज दो पर)

मां सिद्धिदात्री की कृपा पाने का सबसे शक्तिशाली दिन– पूजा विधि, शुभ मुहूर्त, मंत्र, आरती, कथा और कन्या पूजन का सम्पूर्ण मार्गदर्शन

नवरात्रि का अंतिम और सबसे दिव्य दिन महानवमी– शक्ति, सिद्धि और पूर्णता का प्रतीक माना जाता है। इस दिन मां सिद्धिदात्री की उपासना करने से न केवल मनोकामनाएं पूर्ण होती हैं, बल्कि जीवन में अद्भुत आध्यात्मिक और भौतिक सिद्धियों की प्राप्ति भी होती है। यही वह दिन है जब साधना अपने चरम पर पहुंचती है और मां का आशीर्वाद जीवन को नई दिशा देता है।

महानवमी की पूजा विधि : महानवमी के दिन पूजा पूरे विधि–विधान से करने पर इसका फल कई गुना बढ़ जाता है– प्रातः ब्रह्म मुहूर्त में उठकर स्नान करें और स्वच्छ, लाल या पीले वस्त्र धारण करें। पूजा स्थान को साफ करके गंगाजल का छिड़काव करें। मां सिद्धिदात्री की प्रतिमा या चित्र स्थापित करें। धूप–दीप प्रज्वलित करें और कुमकुम, रोली व अक्षत से तिलक करें। लाल फूल (विशेषकर गुड़हल) अर्पित करें। भोग में हलवा, पूरी, काले चने और खीर चढ़ाएं। (शेष पेज दो पर)

भुवनेश्वर में हजारों श्रद्धालुओं ने भगवान लिंगराज का 'रुकुना रथ' खींचा

भुवनेश्वर, फोकस न्यूज, ओडिशा की राजधानी भुवनेश्वर में कड़ी सुरक्षा के बीच हजारों श्रद्धालुओं ने भगवान लिंगराज की वार्षिक 'रुकुना रथ यात्रा' में भाग लिया। अशोकाष्टमी के अवसर पर हर साल ओल्ड टाउन क्षेत्र में लिंगराज मंदिर के सामने यह रथयात्रा ओजित की जाती है। बढ़ती गर्मी के बावजूद श्रद्धालु 11वीं शताब्दी के शिव मंदिर में रथ पर सवार भगवान की एक झलक पाने के लिए उमड़ पड़े। मंदिर प्रशासन ने रथ खींचने का समय पूर्वाह्न 2:30 बजे तय किया था, लेकिन लगभग 3:45 बजे इसकी शुरुआत हुई। एक पुजारी ने बताया कि कुछ ही मिनट में रथ की रस्सी टूट जाने के कारण रथयात्रा थोड़ी देर के लिए रुक गई। इस मौके पर मौजूद कानून मंत्री पृथ्वीराज हरिचंदन ने कहा, "दर्शन और रथ खींचने के लिए आवश्यक कदम उठाए जा रहे हैं।" राज्यपाल हरि बाबू कंभम्पति, मुख्यमंत्री मोहन चरण माझी, नेता प्रतिपक्ष नवीन पटनायक और कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष भक्त चरण दास ने अशोकाष्टमी के अवसर पर लोगों को बधाई दी। मुख्यमंत्री माझी ने 'एक्स' पर (शेष पेज दो पर)

उपराष्ट्रपति ने... (पेज एक का शेष) बिना नहीं रह पाते। उपराष्ट्रपति के इस दौरे को भारतीय सांस्कृतिक धरोहर के प्रचार–प्रसार और आध्यात्मिक पर्यटन को बढ़ावा देने की दिशा में महत्वपूर्ण माना जा रहा है। वहीं, सोशल मीडिया पर साझा किए गए उनके संदेश ने इस ऐतिहासिक स्थल के प्रति लोगों की उत्सुकता और आस्था को और अधिक प्रबल कर दिया है। इस दौरान मंदिर परिसर में सुरक्षा के व्यापक इंतजाम किए गए थे, जबकि श्रद्धालुओं के दर्शन की व्यवस्था भी सुचारु रूप से जारी रही। पूरे वातावरण में भक्ति और अनुशासन का संतुलित दृश्य देखने को मिला, जिसने इस अवसर को और अधिक विशेष बना दिया।

सीएम रेखा... (पेज एक का शेष) उज्ज्वल होगा और मां दुर्गा से यही प्रार्थना है, हर बेटी सशक्त बने, हर घर में सुख–समृद्धि आए और यह भक्ति और शक्ति का संगम सदैव बना रहे।'' मुख्यमंत्री कार्यालय द्वारा जारी बयान के मुताबिक, गुप्ता ने कहा कि जब उन्होंने छात्राओं से उनकी समस्याएं जानीं तो पता चला कि स्कूल आने–जाने में कठिनाई के कारण कई बार पढ़ाई प्रभावित होती है, यहां तक कि कुछ बच्चियों को स्कूल छोड़ना पड़ता है।उन्होंने कहा कि इसी समस्या के समाधान के लिए सरकार ने निर्णय लिया कि हर वर्ष नौवीं कक्षा में आने वाली प्रत्येक छात्रा को साइकिल दी जाएगी। इस वर्ष लगभग 1,30,000 छात्राओं को इसका लाभ मिलेगा। मुख्यमंत्री ने छात्राओं को प्रेरित करते हुए उनके साथ अपने पिता की सीख साझा की और कहा कि परिस्थितियों के अनुसार डटकर जवाब देना सीखें, डरें नहीं। उन्होंने भरोसा दिलाया कि दिल्ली सरकार उनकी सुरक्षा की पूरी जिम्मेदारी लेती है और हर बेटी को आगे बढ़ने का पूरा अवसर दिया जाएगा। मुख्यमंत्री ने आम आदमी पार्टी नेता सौरभ भारद्वाज की साइकिल योजना पर टिप्पणी को 'बेहद शर्मनाक' बताया। उन्होंने कहा, "हमारी बेटियां देवी हैं, उनके भविष्य के लिए बनाई गई योजना पर ऐसी बातें करना दुर्भाग्यपूर्ण है। ऐसी सोच पर उन्हें शर्म आती है।" बहरहाल, गुप्ता ने छात्राओं के बीच जाकर उनसे बातचीत भी की। इस दौरान मुख्यमंत्री ने छात्राओं से पूछा, 'साइकिल चलानी आती है ना? अगर नहीं आती तो वह सीख लें। अब आप अपनी पढ़ाई अपने दम पर पूरी करेंगी।' मुख्यमंत्री ने बताया कि हाल में प्रस्तुत दिल्ली के बजट में उन्होंने बेटियों, बहनों और महिलाओं के लिए अधिकतम योजनाएं शामिल करने का प्रयास किया है ताकि समाज का यह वर्ग सशक्त और आत्मनिर्भर बन सके। इसके अलावा मुख्यमंत्री ने महिलाओं के लिए उनकी सरकार द्वारा शुरू की गई योजनाओं को भी गिनाया जिसमें में 'लखपति बिटिया योजना' और 1000 महिलाओं को उनके नाम पर नए ऑटो परमिट देना शामिल है। दिल्ली सरकार ने 2026–27 के अपने बजट में नौवीं कक्षा की लगभग 1,30,000 छात्राओं को मुफ्त साइकिल उपलब्ध कराने के लिए 90 करोड़ रुपये आवंटित किए हैं।

मुख्यमंत्री सुक्खू... (पेज एक का शेष) पर मुख्यमंत्री ने आवास परिसर में चिनार का पौधा लगाया, जो पर्यावरण संरक्षण और सतत विकास का प्रतीक है। उनकी पत्नी कमलेश ठाकुर और परिवार के अन्य सदस्य भी समारोह में उपस्थित थे। इससे पहले दिन में, मुख्यमंत्री ने हिमाचल प्रदेश सचिवालय के कर्मचारियों द्वारा आयोजित मैराथन को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। सभा को संबोधित करते हुए मुख्यमंत्री ने दोहराया कि सरकार द्वारा प्रस्तुत राज्य बजट जन–केंद्रित है और इसका उद्देश्य आम आदमी के कल्याण और उत्थान को सुनिश्चित करना है।

उत्तर प्रदेश... (पेज एक का शेष) चुनौती थी, लेकिन वर्तमान में प्रदेश की बेटियां शहरों में पढ़ाई करने या काम करने के लिए जाती हैं तो उन्हें भय मुक्त वातावरण मिलता है। उन्होंने पिछले नौ वर्षों के दौरान महिला श्रम शक्ति में तीन गुना वृद्धि होने का दावा करते हुए कहा, ''विगत नौ वर्षों में उत्तर प्रदेश के सरकारी तथा गैर–सरकारी क्षेत्रों में महिला श्रम शक्ति 12 प्रतिशत से बढ़कर 36 प्रतिशत हो चुकी है।'' योगी आदित्यनाथ ने कहा, ''जब समाज, महिला–पुरुष के बीच भेदभाव तथा अभिभावक, बेटा–बेटी के बीच भेदभाव करना बन्द कर दें, तब देश के विकास की रफ्तार कई गुनी बढ़ जाएगी। हमें समाज में प्रत्येक स्तर पर भेदभाव को समाप्त करना है। इसके लिए सभी प्रकार की सुविधाएं भी देनी पड़ेगी।''

कच्चे या... (पेज एक का शेष) **भुने हुए मेवेः** इन्हें स्वाद और कुरकुरापन बढ़ाने के लिए सेका जाता है। **फायदेः** भूनने से मेवों का स्वाद बढ़ जाता है और वे आसानी से पच जाते हैं। गर्मी फाइटेट्स को कम करती है, जिससे मिनरल्स का अवशोषण बेहतर हो सकता है।

नुकसानः अगर मेवों को बहुत अधिक तापमान पर भुना जाए, तो उनके हेल्दी फैट्स ऑक्सीडाइज हो सकते हैं, जिससे वे शरीर के लिए हानिकारक हो सकते हैं। बाज़ार में मिलने वाले भुने मेवों में अक्सर ऑयल और बहुत अधिक नमक होता है।

सेहत के लिए सबसे बेस्ट क्या है?

अगर 'सेहत' की बात करें, तो कच्चे मेवे सबसे बेहतर माने जाते हैं क्योंकि उनमें कोई मिलावट नहीं होती। लेकिन, उन्हें सही तरीके से अपनी डाइट में शामिल करना जरूरी है।

भिगोकर खाएंः बादाम या अखरोट जैसे कच्चे मेवों को रात भर भिगोकर खाने से उनके हानिकारक एंजाइम निकल जाते हैं और वे पचने में आसान हो जाते हैं।

घर पर भूनेंः अगर आपको भुने हुए पसंद हैं, तो बाज़ार के 'सॉल्टेड' पैकेट खरीदने के बजाय कच्चे मेवे लाएं और उन्हें घर पर धीमी आंच पर बिना तेल के भूनें।

केंद्र ने राजस्थान को वाणिज्यिक रसोई गैस का आवंटन 10 प्रतिशत बढ़ाया

जयपुर, (भाषा) राजस्थान सरकार के अनुरोध पर केंद्र सरकार ने राज्य के लिए वाणिज्यिक रसोई गैस (एलपीजी) का आवंटन 10 प्रतिशत बढ़ा दिया है। अधिकारियों ने बृहस्पतिवार को यह जानकारी दी। अधिकारियों के अनुसार राज्य सरकार ने बढ़ती मांग को पूरा करने के लिए केंद्र से अतिरिक्त एलपीजी आवंटन का आग्रह किया था। एक अधिकारी ने बताया कि इस अनुरोध के बाद वाणिज्यिक गैस का आवंटन 10 प्रतिशत बढ़ा दिया गया। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने इस फैसले के लिए प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी के प्रति आभार व्यक्त किया। उन्होंने 'एक्स' पर पोस्ट किया, ''केंद्र सरकार ने राजस्थान के लिए 10 प्रतिशत अतिरिक्त वाणिज्यिक एलपीजी आवंटन को मंजूरी दी है। यह वृद्धि राज्य के व्यवसायों की ऊर्जा आवश्यकताओं को सुदृढ़ करने के साथ नई गति प्रदान करेगी।'' उन्होंने कहा कि राज्य सरकार द्वारा पेट्रोलियम एवं गैस क्षेत्र में किए गए महत्वपूर्ण सुधारों और समय पर दी गई मंजूरियों के परिणामस्वरूप केंद्र सरकार से यह अतिरिक्त आपूर्ति प्राप्त हुई है। शर्मा ने कहा,''प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी के कुशल मार्गदर्शन में हमारी सरकार हर नागरिक तक आवश्यक सेवाओं की निर्बाध, पारदर्शी और समय पर उपलब्धता सुनिश्चित करने हेतु निरंतर कार्यरत है।'' इस बीच, अधिकारियों ने बताया है कि राज्य में गैस, पेट्रोल या डीजल की कोई कमी नहीं है और पर्याप्त आपूर्ति बनाए रखी जा रही है। अधिकारी ने कहा, ''सरकार यह सुनिश्चित करने के लिए आवश्यक कदम उठा रही है कि जनता को किसी भी तरह की असुविधा का सामना न करना पड़े।''

कांग्रेस ने असम विधानसभा चुनाव के लिए छह पर्यवेक्षक नियुक्त किए

नयी दिल्ली, (भाषा) कांग्रेस ने असम विधानसभा चुनाव के लिए छह पर्यवेक्षकों की नियुक्ति की। एक बयान में इसकी जानकारी दी गयी है। पार्टी की ओर से जारी बयान के अनुसार, अशोक सिंह, विनोद वर्मा, अनिरुद्ध सिंह, वीरेंद्र राठौर, योगेश दीक्षित और आदित्य शर्मा को अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी का पर्यवेक्षक बनाया गया है। इससे पहले, सात जनवरी को छत्तीसगढ़ के पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल, कर्नाटक उप मुख्यमंत्री डीके शिवकुमार और झारखंड प्रदेश कांग्रेस के वरिष्ठ नेता बंधु तिर्की को असम के लिए वरिष्ठ पर्यवेक्षक नियुक्त किया गयगा है।

भुवनेश्वर में... (पेज एक का शेष) लिखा, "अशोकाष्टमी और भगवान श्री लिंगराज की रुकुना रथ यात्रा के अवसर पर सभी को हार्दिक बधाई और शुभकामनाएं। भगवान श्री लिंगराज का आशीर्वाद सभी के जीवन में खुशहाली, शांति और समृद्धि लाए।"

महानवमी के... (पेज एक का शेष) तो आज आपको बालों में लगाने वाली क्लिप दान करना चाहिए।

अगर आप प्रशासक है या आप किसी प्रशासनिक कार्य से जुड़े है तो आज आपको जुराब का दान करना चाहिए।

अगर आप आईटी प्रोफेशनल हैं तो आज आपको हेयर बैंड का दान करना चाहिए।

अगर आप आर्मी या किसी भी तरह की फोर्स में कार्यरत हैं तो आज आपको चुनरी या दुपट्टे का दान करना चाहिए।

अगर आप टेली कम्यूनिकेशन यानि दूर संचार से सम्बंधित कार्य करते है तो आज आपको परफ्यूम का दान करना चाहिए।

अगर आज कोरपोरेट जगत में कार्यरत हैं तो आज आपको जूते या चप्पल का दान करना चाहिए।

अगर आप मर्चेंट नेवी या पानी से जुड़े किसी कारोबार में है तो आज आपको दूध का दान करना चाहिए।

गुप्त दान करने से भी होगा लाभ

महानवमी के दिन गुप्त दान करना भी बेहद शुभ होता है। गुप्त रूप से किए गए दान से आपके मन में अहम भाव नहीं जागता और ईश्वर का आशीर्वाद भी आपको पूर्ण रूप से मिलता है। इसलिए नवरात्रि के आखिरी दिन गुप्त रूप से आपको धन, वस्त्र और अन्न का दान करने से भी माता का आशीर्वाद प्राप्त होता है और जीवन के हर क्षेत्र में आप प्रगति करते हैं।

दुर्घटनाओं को... (पेज एक का शेष) पड़ता है। रेलवे पटरियों को पार करते समय होने वाली दुर्घटनाओं को रोकने के लिए यह पहल की गई है।'' इसने कहा, ''मंत्रालय ने अगले पांच से छह वर्षों में देशभर में रेलवे पटरियों के आसपास के सभी बस्तियों को शामिल करने की योजना बनाई है। इसका निर्माण इस प्रकार किया जाएगा कि रेल यातायात को अवरुद्ध करने में केवल 12 घंटे लगेंगे।'' अधिकारियों ने बताया कि कई जगहों पर, रेल पटरियों के एक तरफ आवासीय क्षेत्र हैं और दूसरी तरफ खेत, स्कूल, श्मशान और दैनिक उपयोग के अन्य प्रतिष्ठान हैं। एक अधिकारी ने कहा, ''देश के विभिन्न हिस्सों से प्रतिदिन कई दुर्घटनाओं की खबरें आ रही हैं। इन सबवे से पटरियों को पार करते समय होने वाली दुर्घटनाओं को रोका जा सकेगा। ये सबवे देश की एक बड़ी आबादी के लिए वरदान साबित होंगे।''

मां सिद्धिदात्री... (पेज एक का शेष) दुर्गा चालीसा या दुर्गा सप्तशती का पाठ करें।

अंत में श्रद्धा से मां की आरती करें।

मां सिद्धिदात्री की पावन कथाः धार्मिक ग्रंथों के अनुसार, मां सिद्धिदात्री वही शक्ति हैं जिनकी कृपा से भगवान शिव को अष्ट सिद्धियों की प्राप्ति हुई।

इसी कारण शिव का आधा शरीर देवी का रूप बन गया और वे अर्द्धनारीश्वर कहलाए।

माता की कृपा से मिलने वाली अष्ट सिद्धियां हैंः

अणिमा, महिमा, गरिमा, लघिमा,

प्राप्ति, प्रकाम्य, ईशित्व और वशित्व।

कहा जाता है कि देवताओं, गंधर्वों, यक्षों और असुरों तक ने मां की उपासना कर सिद्धियां प्राप्त कीं।

यह दिन साधना और सफलता का सर्वोच्च प्रतीक है।

शक्तिशाली मंत्र :

प्रार्थना मंत्र

"सिद्ध गंधर्व यक्षाद्यैरसुरैरमरैरपि।

सेव्यमाना सदा भूयात् सिद्धिदा सिद्धिदायिनी॥"

स्तुति मंत्र

"या देवी सर्वभूतेषु सिद्धिदात्री रूपेण संस्थिता।

नमस्तस्यै नमस्तस्यै नमस्तस्यै नमो नमः॥"

कलश विसर्जन मंत्र

"गच्छ गच्छ सुरश्रेष्ठ, स्वस्थानं परमेश्वरी।

पूजाराधनकाले च पुनरागमनाय च॥"

भोग : मां सिद्धिदात्री को प्रसन्न करने के लिए–

हलवा

पूरी

काले चने

खीर

इनका भोग लगाना अत्यंत शुभ माना जाता है।

कन्या पूजन विधि :

महानवमी का सबसे महत्वपूर्ण अनुष्ठान– कन्या पूजन

9 कन्याओं को घर बुलाएं (नवदुर्गा का स्वरूप मानकर)

उनके चरण धोएं और आसन पर बैठाएं

हलवा, पूरी, चना और खीर का प्रसाद खिलाएं

उपहार और दक्षिणा दें

अंत में उनके चरण स्पर्श कर आशीर्वाद लें

मान्यता है कि बिना कन्या पूजन के नवरात्रि पूजा अधूरी मानी जाती है।

मां सिद्धिदात्री की आरती

जय सिद्धिदात्री तू सिद्धि की दाता,

तू भक्तों की रक्षक, तू दासों की माता।

तेरा नाम लेते ही मिलती है सिद्धि,

तेरे नाम से मन की होती है शुद्धि॥

कठिन काम सिद्ध कराती हो तुम,

जब भी हाथ सेवक के सिर धरती हो तुम॥

विशेष उपाय : महानवमी के दिन शिवलिंग पर लौंग का एक जोड़ा अर्पित करें। इससे धन–धान्य और आर्थिक समृद्धि का मार्ग खुलता है

महानवमी सिर्फ एक पर्व नहीं, बल्कि साधना की पूर्णता का दिन है।

इस दिन मां सिद्धिदात्री की सच्चे मन से पूजा करने पर–

जीवन में सफलता

मानसिक शांति

आध्यात्मिक उन्नति

और हर इच्छा की पूर्ति संभव होती है

जय माता दी

Although every possible care and caution has been taken to avoid errors or omissions, this publication is being sold on the condition and understanding that information given in this publication is merely for reference and must not be taken as having the authority of or binding in any way on the writers, editors, publishers, and printers and sellers who do not owe any responsibility for any damage or loss to any person, a purchaser of this publication or not for the result of any action taken on the basis of this work. All disputes are subject to the exclusive jurisdiction of competent court and forums in Delhi/New Delhi only

Published, Printed, Edited and Owned by Krishna Aggarwal Published from New Delhi, Tel- 011-43560023 E-mail- info@focusnews.co.in, focusnews9@gmail.com
RNI NUMBER - DELBIL/2013/56173, Printed from Vibha Publication Pvt Ltd- D-160 B, Noida Phase - I, Uttar Pradesh - 201301

नवरात्र के दौरान वैष्णो देवी मंदिर में श्रद्धालुओं की भारी भीड़ उमड़ी

जम्मू, जम्मू–कश्मीर के रियासी जिले में स्थित माता वैष्णो देवी मंदिर में चैत्र नवरात्र के दौरान श्रद्धालुओं की भारी भीड़ उमड़ी, इस दौरान 2.69 लाख से अधिक श्रद्धालुओं ने गुफा मंदिर में प्रार्थना की। माता वैष्णो देवी श्राइन बोर्ड के एक वरिष्ठ अधिकारी ने 'पीटीआई–भाषा' को बताया, "25 मार्च तक 2,69,716 श्रद्धालु मंदिर में दर्शन कर चुके हैं। मंदिर में श्रद्धालुओं की भारी भीड़ है। हालांकि, यात्रा सुचारू रूप से चल रही है।" चैत्र नवरात्र 19 मार्च से 27 मार्च तक मनाए जा रहे हैं। नवरात्र देवी नवदुर्गा की पूजा के लिए समर्पित है और माता वैष्णो देवी मंदिर में इसका विशेष महत्व है, जहां इस अवधि के दौरान श्रद्धालुओं की सबसे अधिक भीड़ होती है। आंकड़ों के अनुसार, नवरात्र के पहले दिन 19 मार्च को 31,815 श्रद्धालुओं ने मंदिर में दर्शन किए, जबकि 20 मार्च को 34,805, 21 मार्च को 41,078, 22 मार्च को 43,482, 23 मार्च को 45,478, 24 मार्च को 38,158 और 25 मार्च को 34,900 श्रद्धालुओं ने मंदिर का दौरा किया। उन्होंने बताया कि श्रद्धालुओं की भारी भीड़ को नियंत्रित करने के लिए उनका पंजीकरण दो बार थोड़े समय के लिए निलंबित किया गया था। अधिकारियों ने कटरा बेस कैंप और तीर्थस्थल तक जाने वाले मार्ग पर बहुस्तरीय सुरक्षा व्यवस्था की है ताकि यात्रा सुरक्षित हो सके। उन्होंने बताया कि बोर्ड ने श्रद्धालुओं का मार्गदर्शन करने, संभावित भीड़ को संभालने और 13 किलोमीटर लंबे यात्रा मार्ग पर सुचारू आवागमन सुनिश्चित करने के लिए स्वयंसेवकों को तैनात किया है।

गुजरातः रंगारंग शोभा यात्राओं और रचनात्मक तरीकों से मनायी गयी राम नवमी

अहमदाबाद, (भाषा) गुजरात में रंगारंग शोभा यात्राओं से लेकर युवाओं द्वारा आयोजित अभिनव कार्यक्रमों के साथ भक्तों ने बृहस्पतिवार को राम नवमी को पूरे उत्साह के साथ मनाया। शहरों में 'जय श्री राम' के उद्घोष की गूंज सुनाई दी। भगवान राम की जयंती के उपलक्ष्य में राजकोट और वडोदरा सहित राज्य के कई शहरों में शोभा यात्राएं निकाली गयीं। सड़कें रंगारंग प्रस्तुतियों, भक्ति गीतों और सामुदायिक भागीदारी से गुलजार हो उठीं। अहमदाबाद स्थित इस्कॉन मंदिर में सुबह 'श्री राम दरबार अभिषेक' और पारंपरिक '56 भोग' अर्पण के साथ एक भव्य समारोह का आयोजन किया गया। संस्था ने सोशल मीडिया पर कहा, "मंदिर में शाम को पालकी यात्रा निकाली जाएगी और राम कथा का आयोजन भी किया जाएगा, जिसमें बड़ी संख्या में श्रद्धालु शामिल होंगे।" इस बीच, युवा उत्सव मनाने के लिए नए–नए तरीके अपना रहे थे। एक इवेंट बुकिंग वेबसाइट के अनुसार, अडालज में शाम को भजन–कीर्तन का आयोजन किया जाएगा, जहां एक लाइव फ्यूजन बैंड पारंपरिक भक्ति संगीत को समकालीन धुनों के साथ मिलाकर आध्यात्मिक अभिव्यक्ति का आधुनिक रूप प्रस्तुत करेगा। उधर, लगभग 90 बाइकर्स सूरत में डाभरी बीच पहुंचे, जहां 65 मोटरसाइकिलों को इस तरह व्यवस्थित किया गया कि उनसे 'राम' शब्द लिखे होने का आभास हो सके। समूह के संस्थापक पिनांक मशरूवाला ने 'पीटीआई–भाषा' को बताया, "हर राम भक्त का प्रेम व्यक्त करने का अपना तरीका होता है। कुछ लोग शोभा यात्रा, भंडारा और आरती का आयोजन करते हैं। यह हमारा उत्सव मनाने का तरीका है, जिसमें हम अपनी पसंदीदा बाइकों के माध्यम से 'राम' के नाम को दर्शाते हैं।"

यात्री संघों ने वैष्णव से धन वापसी के नये नियमों पर पुनर्विचार करने का आग्रह किया

नयी दिल्ली, (भाषा) विभिन्न यात्री संगठनों ने रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव से आग्रह किया कि सरकार धन वापसी (रिफंड) के नये नियमों को लागू न करें, जिनके तहत यात्रियों को ट्रेन के प्रस्थान से आठ घंटे पहले तक कन्फर्म टिकट रद्द कराने पर कोई पैसा वापस नहीं मिलेगा। वैष्णव ने मंगलवार को रेल क्षेत्र में सुधारों की घोषणा करते हुए कहा था कि इस वर्ष एक से 15 अप्रैल के बीच एक नया नियम लागू किया जाएगा, जिसके तहत यात्रियों को ट्रेन के प्रस्थान से आठ घंटे पहले तक टिकट रद्द करने पर कोई पैसा वापस नहीं मिलेगा जबकि वर्तमान नियम के अनुसार यह अवधि चार घंटे है। वैष्णव ने कहा था कि कालाबाजारी और एजेंटों द्वारा अंतिम समय में टिकटों की बिक्री को रोकने के लिए मौजूदा रिफंड नियम में संशोधन किया जा रहा है। उन्होंने अन्य रिफंड स्लैब में संशोधन की भी घोषणा की, जिसके अनुसार 24 से आठ घंटे पहले रद्द करने पर टिकट की कीमत में 50 प्रतिशत की कटौती होगी जबकि वर्तमान में यह कटौती 12 से चार घंटे पहले तक ही होती है। इसी प्रकार, रेलवे प्रस्थान से 72 से 24 घंटे पहले रद्द करने पर टिकट की कीमत में 25 प्रतिशत की कटौती करेगा। ट्रेन के प्रस्थान से 72 घंटे से अधिक पहले रद्द करने पर प्रति यात्री मामूली रद्दीकरण शुल्क को छोड़कर पूरी राशि वापस कर दी जाएगी। वर्तमान नीति के तहत, 48 से 12 घंटे पहले रद्द करने पर टिकट की कीमत में 25 प्रतिशत की कटौती होती है जबकि 48 घंटे से अधिक पहले रद्द करने पर पूरी राशि वापस कर दी जाती है। यात्री संघों का कहना है कि धन वापसी के नए नियम से यात्रियों पर भारी वित्तीय बोझ पड़ेगा। उनका दावा है कि रेलवे रद्द हुई बर्थ को अन्य यात्रियों को देकर दोगुनी कमाई करेगा। कोयंबटूर जिला रेलवे यात्री कल्याण संघ के अध्यक्ष एम. जमील अहमद ने कहा, "मैं रेल मंत्री से आग्रह करता हूं कि वे धन वापसी के नए नियमों को लागू न करें। इससे यात्रियों पर अनावश्यक वित्तीय बोझ पड़ेगा।" उन्होंने कहा, "रेलवे को धन वापसी के नियमों में संशोधन कर पैसा कमाने के बारे में नहीं सोचना चाहिए। माल परिवहन में कई अन्य तरीके हैं जिनसे उन्हें राजस्व प्राप्त करने में मदद मिल सकती है।" जमील ने कहा कि अगर पांच या छह लोगों के परिवार को अगले दिन की ट्रेन में कंफर्म सीट मिल जाती है और किसी कारणवश उन्हें ट्रेन छूटने से आठ घंटे के भीतर सभी टिकट रद्द करने पड़ते हैं, तो उन्हें कोई पैसा वापस नहीं मिलेगा। उन्होंने कहा, "रेलवे उन सीट को दूसरे यात्रियों को देकर मुनाफा कमाएगा। यह अन्याय है।" मंत्रालय ने स्पष्ट किया कि धन वापसी के नियमों से किसी भी तरह का वित्तीय बोझ नहीं पड़ेगा।

भाजपा सांसद ने जनसंख्या नीति पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को लिखा पत्र, संतुलित विकास पर जोर दिया

नयी दिल्ली, (भाषा) भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) के सांसद प्रवीण खंडेलवाल ने बृहस्पतिवार को केंद्र से सतत, समावेशी और संतुलित विकास सुनिश्चित करने के लिए शिक्षा, परिवार नियोजन और क्षेत्र–विशिष्ट रणनीतियों पर आधारित राष्ट्रीय जनसंख्या प्रबंधन नीति बनाने का आग्रह किया। दिल्ली के चांदनी चौक निर्वाचन क्षेत्र के सांसद खंडेलवाल ने इस संबंध में प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी को एक पत्र लिखा है। भाजपा सांसद ने पत्र में लिखा है कि 1.4 अरब से अधिक आबादी वाला यह देश एक महत्वपूर्ण जनसांख्यिकीय मोड़ पर खड़ा है। खंडेलवाल ने कहा कि यह एक बहुमूल्य संपत्ति और विशाल मानव संसाधन का स्रोत होने के साथ–साथ प्राकृतिक संसाधनों, बुनियादी ढांचे, रोजगार के अवसरों और स्वास्थ्य सेवा एवं शिक्षा जैसी सार्वजनिक सेवाओं पर भी लगातार दबाव बढ़ा रहा है। उन्होंने कहा कि तेजी से बढ़ती जनसंख्या शहरी भीड़भाड़ और बेरोजगारी को बढ़ा रही है तथा पर्यावरण और आवश्यक सेवाओं पर दबाव डाल रही है। भाजपा सांसद ने पत्र में लिखा है, ''यदि एक सुनियोजित नीतिगत ढांचे के माध्यम से इन चुनौतियों का समाधान नहीं किया गया, तो ये चुनौतियां एक विकसित राष्ट्र बनने की हमारी यात्रा में बाधा बन सकती हैं।'' उन्होंने कहा, ''ऐसी नीति जागरूकता, शिक्षा और स्वैच्छिक भागीदारी पर आधारित होनी चाहिए। साथ ही, परिवार नियोजन सेवाओं तक सार्वभौमिक पहुंच सुनिश्चित करने और महिला सशक्तीकरण को बढ़ावा देने पर भी जोर देना चाहिए। इसमें विभिन्न राज्यों में जनसंख्या वृद्धि के अलग–अलग रुझानों से निपटने के लिए क्षेत्र–विशिष्ट रणनीतियां भी अपनाई जानी चाहिए।''

ओडिशा सरकार ने विधायकों का वेतन बढ़ाने के प्रावधान वाले विधेयकों को वापस लेने की प्रक्रिया शुरू की

भुवनेश्वर, (भाषा) ओडिशा सरकार ने विधानसभा से पारित उन चार विधेयकों को व्यापक जनाक्रोश के बीच बृहस्पतिवार को वापस लेने की प्रक्रिया शुरू कर दी जिनमें विधायकों, मंत्रियों, मुख्यमंत्री, विधानसभा अध्यक्ष और उपाध्यक्ष के वेतन, भत्ते व पेंशन में तीन गुना वृद्धि का प्रस्ताव है। ये विधेयक राज्यपाल की स्वीकृति के लिए लंबित थे। ओडिशा विधानसभा सचिवालय ने सभी विधायकों को लिखे पत्र में बताया कि संसदीय मामलों के मंत्री मुकेश महालिंग ने चार संशोधन विधेयकों को वापस लेने के लिए अनुमति लेने का नोटिस दिया है। चारों विधेयक नौ दिसंबर 2025 को शीतकालीन सत्र के अंतिम दिन सर्वसम्मति से पारित किए गए थे। पत्र में कहा गया है कि यदि विधानसभा अनुमति देती है, तो ये विधेयक वापस ले लिए जाएंगे, जिससे वेतन और भत्तों में प्रस्तावित वृद्धि पर फिलहाल रोक लग जाएगी। इन विधेयकों में विधायक का मासिक वेतन और भत्ते तीन गुना बढ़ाकर 1.11 लाख रुपये से 3.45 लाख रुपये प्रति माह करने का प्रावधान है।

दिल्ली पीडब्ल्यूडी ने पीएनजी पाइपलाइन बिछाने का काम तेज करने के लिए सड़क मरम्मत शुल्क माफ किया

नयी दिल्ली, (भाषा) दिल्ली के लोक निर्माण विभाग (पीडब्ल्यूडी) ने पीएनजी पाइपलाइन बिछाने की प्रक्रिया तेज करने के लिए अब सड़क खोदने की अनुमति आवेदन मिलने के 24 घंटे के अंदर देने का फैसला किया है। बृहस्पतिवार को एक आदेश में यह जानकारी दी गई। आदेश के अनुसार पीडब्ल्यूडी ने सड़क मरम्मत शुल्क भी तीन महीने के लिए माफ कर दिया है। आदेश में कहा गया है कि इंद्रप्रस्थ गैस लिमिटेड की पाइपलाइन बिछाने के लिए सड़क खोदने की अनुमति पूर्ण आवेदन मिलने के 24 घंटे के अंदर दे दी जाएगी और काम तुरंत शुरू करने के निर्देश जारी किए जाएंगे। आदेश में कहा गया है कि आईजीएल द्वारा पीएनजी कनेक्शन के लिए पाइपलाइन बिछाने पर लगने वाला सड़क मरम्मत शुल्क 30 जून 2026 तक के लिए माफ किया गया है। यह शुल्क आमतौर पर वह एजेंसी वसूलती है जो सड़क या फुटपाथ को खोदने की अनुमति देती है। आदेश में कहा गया है कि वर्तमान परिस्थितियों और जनहित को देखते हुए यह कदम उठाया गया है, ताकि आईजीएल उपभोक्ताओं को तेजी से पीएनजी कनेक्शन उपलब्ध करा सके। आईजीएल को निर्देश दिया गया है कि वह पर्याप्त संसाधनों और कर्मचारियों के साथ इस काम को प्राथमिकता के आधार पर पूरा करे। साथ ही यह भी सुनिश्चित करने को कहा गया है कि खोदे गए स्थानों को तुरंत भरकर सुरक्षित किया जाए, ताकि लोगों को कोई असुविधा या सुरक्षा खतरा न हो।

प्रमुख पर्यटन स्थल आबू राज को स्वच्छता में रोल मॉडल बनाकर मुख्यमंत्री के संकल्प को पूरा करेंगे : के के गुप्ता

नीति गोपेन्द्र भट्ट

जयपुर/आबू राज। स्वच्छ भारत मिशन (शहर) स्वायत्त शासन विभाग, राजस्थान सरकार द्वारा नियुक्त प्रदेश स्वच्छता ब्रांड एंबेसडर के के गुप्ता द्वारा नगर पालिका आबू राज में स्वच्छता कार्यशाला को संबोधित किया गया। कार्यशाला को संबोधित करते हुए ब्रांड एंबेसडर श्री गुप्ता ने कहा कि राजस्थान के साथ गुजरात के प्रमुख पर्यटन स्थल आबू राज को स्वच्छता में रोल मॉडल बनाकर प्रदेश के मुख्यमंत्री भजन लाल शर्मा के संकल्प को पूरा किया जाएगा । मुख्यमंत्री स्वच्छता ब्रांड एंबेसडर नियुक्त करके मुझ पर जो विश्वास जताया है उसे दृढ़ संकल्पित होकर पूरा किया जाएगा। उन्होने कहा कि मुख्यमंत्री द्वारा स्वच्छता कार्यशालाओं और बैठकों के संबंध में प्रत्येक सप्ताह मुझसे व्यक्तिगत संपर्क करके जानकारी ली जा रही है और मुख्यमंत्री के सख्त आदेश है कि स्वच्छता के साथ किसी भी प्रकार का समझौता बर्दाश्त नहीं होगा और कार्य में लापरवाही रखने वाले अधिकारी और कर्मचारियों के विरुद्ध कड़ी कार्यवाही की जाएगी। ब्रांड एंबेसडर गुप्ता ने कहा कि स्वच्छ भारत मिशन अभियान एक साधारण सरकारी अभियान नहीं है बल्कि यह देश के 142 करोड़ लोगों के साथ प्रत्यक्ष रूप से जुड़ा हुआ विषय है। देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी द्वारा वर्ष 2014 में इस महत्वाकांक्षी अभियान का आगाज किया गया था तब किसी को यह अंदेशा नहीं था कि इसके कितने दूरगामी सकारात्मक परिणाम प्राप्त होंगे। गुप्ता ने कहा कि इसी अभियान के अंतर्गत देश में 12 करोड़ शौचालय का निर्माण किया गया जो लोगों के निजी मकान में उपयोग हेतु बने और वैश्विक महामारी कोरोना के समय जब देश को बचाने के लिए भारत सरकार द्वारा लॉकडाउन लगाया गया तब यही शौचालय उपयोग में आए क्योंकि घर से बाहर निकलने पर पूर्ण रूप से प्रतिबंध था। ऐसे में हम कल्पना भी नहीं कर सकते हैं कि ग्रामीण अंचल में हमारी माता बहनों की स्थिति क्या हो सकती थी? स्वच्छता की बदौलत हम एक स्वच्छ और सुंदर वातावरण का भी निर्माण करते हैं जिस कारण लोग बीमार नहीं होते हैं।

श्रीनगर के रघुनाथ मंदिर में 36 साल बाद राम नवमी पूजा, हिंदू–मुस्लिम एकता की मिसाल

श्रीनगर, (भाषा) श्रीनगर के हब्बा कदल इलाके में स्थित रघुनाथ मंदिर बृहस्पतिवार को एक ऐतिहासिक पल का गवाह बना, जब 36 वर्ष बाद इस सौ साल पुराने मंदिर में राम नवमी की पहली पूजा आयोजित की। इस खास अवसर पर न सिर्फ हिंदू श्रद्धालु जुटे, बल्कि उनके मुस्लिम पड़ोसी भी साथ खड़े नजर आए, जिससे माहौल भाईचारे और सौहार्द से भर उठा। हालांकि, मंदिर में अभी मरम्मत और पुनर्निर्माण का काम जारी है, फिर भी मंदिर प्रबंधन समिति ने इस ऐतिहासिक अवसर का जश्न मनाने के लिए पूजा का आयोजन किया। समिति के महासचिव सुनील कुमार ने बताया, ''36 साल बाद यहां राम नवमी की पूजा हो रही है। हममें से कुछ लोग जम्मू से आए हैं, लेकिन देश–विदेश से कई लोगों ने दान देकर मंदिर के पुनर्निर्माण में सहयोग किया है।'' उन्होंने यह भी बताया कि निर्माण कार्य अधूरा होने के कारण अभी ''मूर्ति स्थापना'' नहीं हो सकी है। कश्मीरी पंडितों की घाटी में वापसी के सवाल पर सुनील कुमार ने कहा कि यह तब तक संभव नहीं है, जब तक कश्मीरी मुस्लिम समुदाय का सहयोग न मिले। उन्होंने कहा, ''सरकार हमें एक साल में बसाकर पुनर्वास कर सकती है, लेकिन हमारी वापसी के लिए कश्मीरी मुसलमानों का साथ जरूरी है।'' इस अवसर पर स्थानीय मुस्लिम निवासी गुलाम हसन भी मंदिर पहुंचे और उत्सव में शामिल हुए। उन्होंने कहा, ''कश्मीरी पंडित और मुसलमान भाई–भाई हैं। हम दशकों से साथ रहते आए हैं।'' राम नवमी के अवसर पर शहर के अन्य मंदिरों, जैसे शंकराचार्य मंदिर में भी विशेष पूजा–अर्चना की गई। इस दौरान पर्यटकों और सुरक्षा बलों ने भी स्थानीय हिंदू समुदाय के साथ मिलकर उत्सव में भाग लिया।

प्रत्येक विधायक को आईपीएल मैच के चार वीआईपी टिकट दिये जाने चाहिएः कर्नाटक विधानसभा अध्यक्ष

बेंगलुरु, (भाषा) कर्नाटक विधानसभा अध्यक्ष यू. टी. खादर ने बृहस्पतिवार को राज्य सरकार को यह सुनिश्चित करने का निर्देश दिया कि बेंगलुरु के चिन्नास्वामी स्टेडियम में क्रिकेट मैचों के दौरान प्रत्येक विधायक को वीआईपी कोटे से चार टिकट दिये जाएं। विधानसभा अध्यक्ष ने यह निर्देश, विपक्ष के नेता आर अशोक समेत कई विधायकों द्वारा यह दावा किये जाने के बाद जारी किया कि उन्हें मैचों के दौरान सिर्फ एक टिकट दिया गया और बैठने की उचित व्यवस्था नहीं की गई। कुछ विधायकों ने स्टेडियम में अपने लिए अलग लाउंज की भी मांग की। यह घटनाक्रम ऐसे समय में हुआ है, जब 28 मार्च को बेंगलुरु में इंडियन प्रीमियर लीग (आईपीएल) 2026 का उद्घाटन मुकाबला पिछले साल के विजेता रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु और सनराइजर्स हैदराबाद के बीच होना है। विधानसभा अध्यक्ष के निर्देश के बाद उपमुख्यमंत्री डी. के. शिवकुमार ने कहा कि वह कर्नाटक राज्य क्रिकेट एसोसिएशन (केएससीए) के अधिकारियों से बात करेंगे और विधानसभा के अगले सत्र के दौरान सदन को सूचित करेंगे। इस पर, खादर और कुछ विधायकों ने उल्लेख किया कि आईपीएल मैच 28 मार्च से शुरू हो रहे हैं। इसके बाद, शिवकुमार ने कहा कि वह तुरंत केएससीए अधिकारियों से बात करेंगे। उन्होंने कहा, ''मैं वहां के अध्यक्ष को व्यक्तिगत रूप से जानता हूं। मैं केएससीए का सदस्य होने के नाते उनके चुनावों में वोट भी देता हूं। विधायकों द्वारा यह मांग करने में कुछ भी गलत नहीं है। उन्हें यह सुविधा मांगने का पूरा अधिकार है। मैं उनसे बात करूंगा।'' यह मुद्दा एक चर्चा के दौरान उस वक्त उठा, जब मंत्री के. जे. जॉर्ज ने बेंगलुरु के विकास पर हो रही चर्चा में हस्तक्षेप करते हुए कहा कि उन्होंने पहले सुझाव दिया था कि अगर विरासत विमानन संस्थान 'जक्कूर फ्लाइंग ट्रेनिंग स्कूल' को उसके वर्तमान स्थल से स्थानांतरित किया जाता है तो एक नया खेल मैदान या स्टेडियम बनाने पर विचार किया जाना चाहिए। उन्होंने कहा कि मंत्री कृष्णा बायरे गौड़ा ने इस प्रस्ताव का विरोध किया और आरोप लगाया कि सरकार 'बिल्डर्स' को फायदा पहुंचाने की कोशिश कर रही है। मुख्यमंत्री सिद्धरमैया ने बाद में इस मुद्दे को स्थगित कर दिया, और कोई निर्णय नहीं लिया गया। भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) के विधायक सी. एन. अश्वथ नारायण ने इस मुद्दे पर प्रतिक्रिया देते हुए, सवाल किया कि क्या बेंगलुरु में क्रिकेट के एक नये मैदान के लिए जमीन की कमी है? उन्होंने कहा, ''क्या उन्हें सरकारी जमीन की जरूरत है? उन्हें केवल सरकारी अनुमति की जरूरत है।'' आर. अशोक ने कहा, ''वे (केएससीए) मैचों के दौरान हमें उपयुक्त रूप से टिकट नहीं देते हैं, फिर भी सरकार उन्हें स्टेडियम के लिए जमीन देना चाहती है।''

कृत्रिम मेधा आधारित शिक्षा : परिवर्तन का दौर और शिक्षक की नई भूमिका

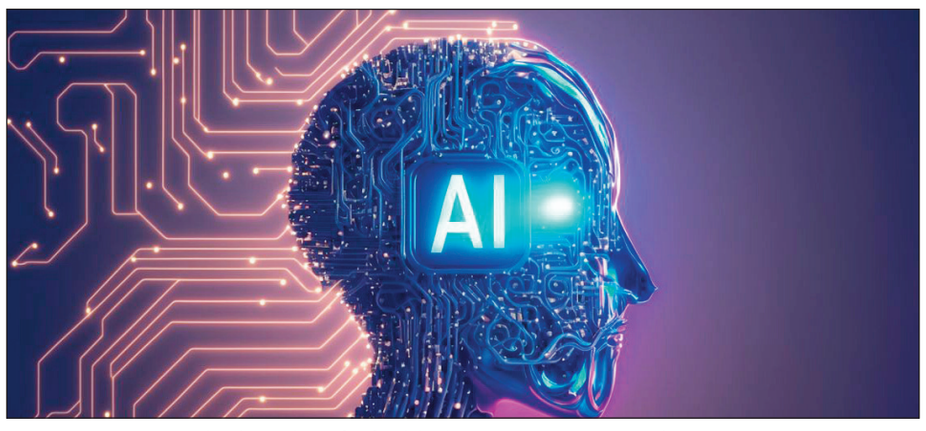

समय की धारा जब सभ्यता के साथ आगे बढ़ती है, तो शिक्षा उस प्रवाह को दिशा देने वाली शक्ति बनती है। आज यही शिक्षा कृत्रिम मेधा के प्रभाव से एक नए युग में प्रवेश कर चुकी है। कक्षाओं से लेकर शोध तक, हर स्तर पर एआई का विस्तार दिखाई दे रहा है। यह बदलाव केवल तकनीकी नहीं है, बल्कि शिक्षा की संरचना, पद्धति और उद्देश्य को भी नए सिरे से परिभाषित कर रहा है। ऐसे समय में यह प्रश्न स्वाभाविक है कि क्या एआई के बढ़ते प्रभाव से शिक्षक की भूमिका समाप्त हो जाएगी या वह एक नए, अधिक प्रभावशाली स्वरूप में सामने आएगा। यदि समकालीन शोध और वैश्विक अनुभवों के आधार पर इस विषय को समझा जाए, तो यह स्पष्ट होता है कि एआई शिक्षा को बदल रहा है, लेकिन शिक्षक की आवश्यकता को समाप्त नहीं कर रहा। एआई का मूल उद्देश्य शिक्षकों को प्रतिस्थापित करना नहीं, बल्कि उनके कार्य को अधिक प्रभावी और सशक्त बनाना है। यह तकनीक शिक्षा को अधिक सुलभ, लचीला और व्यक्तिगत बनाने में सहायक सिद्ध हो रही है। आज विश्वभर में विद्यार्थी तेजी से एआई आधारित उपकरणों को अपनाते जा रहे हैं। अध्ययन सामग्री की खोज, जटिल विषयों की व्याख्या और शोध कार्यों में एआई का उपयोग आम हो चुका है। भारत में भी यह प्रवृत्ति तेजी से बढ़ रही है, जहाँ बड़ी संख्या में छात्र अपनी पढ़ाई में एआई का सहारा ले रहे हैं। यह स्थिति इस बात का संकेत है कि एआई अब शिक्षा का पूरक नहीं, बल्कि उसका अभिन्न अंग बन चुका है। एआई का सबसे बड़ा प्रभाव व्यक्तिगत शिक्षण के रूप में सामने आया है। पारंपरिक व्यवस्था में एक ही कक्षा में सभी छात्रों को समान तरीके से पढ़ाया जाता था, जिससे कई विद्यार्थी अपनी गति के अनुसार सीख नहीं पाते थे। लेकिन एआई आधारित प्रणालियाँ प्रत्येक छात्र की क्षमता, रुचि और सीखने की गति के अनुसार सामग्री प्रस्तुत करती हैं। इससे शिक्षा अधिक प्रभावी और समावेशी बनती है। अब छात्र अपनी आवश्यकताओं के अनुसार सीख सकते हैं, जिससे उनकी समझ और आत्मविश्वास दोनों बढ़ते हैं। इसके साथ ही एआई ने शिक्षकों के कार्यभार को भी कम करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। उत्तर पुस्तिकाओं का मूल्यांकन, पाठ योजनाओं का निर्माण और डेटा विश्लेषण जैसे कार्य अब अधिक तेजी और सटीकता से किए जा सकते हैं। इससे शिक्षकों को छात्रों के साथ अधिक संवाद करने, उनकी समस्याओं को समझने और उन्हें मार्गदर्शन देने के लिए समय मिल पाता है। इस प्रकार एआई शिक्षक के लिए एक सहयोगी उपकरण के रूप में कार्य कर रहा है। भारत में भी शिक्षा व्यवस्था में एआई को शामिल करने की दिशा में ठोस प्रयास किए जा रहे हैं। प्रारंभिक कक्षाओं से ही तकनीकी शिक्षा को बढ़ावा देने की पहल इस बात का संकेत है कि भविष्य की पीढ़ी को डिजिटल युग के अनुरूप तैयार किया जा रहा है। नई शिक्षा नीतियाँ भी इस दिशा में मार्गदर्शन प्रदान कर रही हैं, जिससे छात्र न केवल ज्ञान अर्जित करें, बल्कि बदलती दुनिया के साथ तालमेल भी बैठा सकें। हालाँकि इस परिवर्तन के साथ कुछ चुनौतियाँ भी सामने आई हैं। सबसे बड़ी चिंता छात्रों की रचनात्मकता और स्वतंत्र सोच पर पड़ने वाले प्रभाव की है। जब विद्यार्थी अत्यधिक रूप से एआई पर निर्भर हो जाते हैं, तो उनकी स्वयं सोचने और विश्लेषण करने की क्षमता प्रभावित हो सकती है। शिक्षा का मूल उद्देश्य केवल जानकारी प्राप्त करना नहीं, बल्कि विचार करना और समझ विकसित करना है, जिसे बनाए रखना आवश्यक है। दूसरी चुनौती शैक्षणिक ईमानदारी से जुड़ी है। एआई के माध्यम से तैयार सामग्री का उपयोग कई बार बिना उचित संदर्भ के किया जाता है, जिससे नकल और मौलिकता के प्रश्न उठते हैं। इस स्थिति में संस्थानों को स्पष्ट दिशा–निर्देश और नैतिक मानदंड स्थापित करने की आवश्यकता है, ताकि तकनीक का उपयोग जिम्मेदारी के साथ किया जा सके। तीसरी महत्वपूर्ण समस्या डिजिटल असमानता की है। सभी छात्रों के पास समान तकनीकी संसाधन उपलब्ध नहीं हैं। ऐसे में एआई आधारित शिक्षा उन छात्रों के लिए अधिक लाभकारी हो सकती है जिनके पास बेहतर सुविधाएँ हैं, जबकि अन्य पीछे रह सकते हैं। इस अंतर को कम करने के लिए बुनियादी ढांचे, इंटरनेट सुविधा और शिक्षक प्रशिक्षण पर विशेष ध्यान देना आवश्यक है। इन सभी पहलुओं के बीच शिक्षक की भूमिका सबसे महत्वपूर्ण बनी रहती है। एआई जानकारी प्रदान कर सकता है, लेकिन वह मानवीय संवेदनाएँ, प्रेरणा और नैतिक मार्गदर्शन नहीं दे सकता। शिक्षा केवल तथ्यों का आदान–प्रदान नहीं है, बल्कि व्यक्तित्व निर्माण की प्रक्रिया है, जिसमें शिक्षक की भूमिका अनिवार्य है। आज शिक्षक की भूमिका ज्ञान देने वाले व्यक्ति से बदलकर मार्गदर्शक और सहायक की हो गई है। वह अब केवल पाठ नहीं पढ़ाता, बल्कि छात्रों को सीखने की प्रक्रिया को समझने और सही दिशा में आगे बढ़ने के लिए प्रेरित करता है। एआई के इस युग में शिक्षक का कार्य और भी महत्वपूर्ण हो गया है, क्योंकि उसे छात्रों को यह सिखाना है कि तकनीक का उपयोग कैसे किया जाए और उसकी सीमाओं को कैसे समझा जाए। इसके लिए शिक्षकों का प्रशिक्षण भी अत्यंत आवश्यक है। नई तकनीकों के साथ तालमेल बिठाने और उन्हें प्रभावी रूप से उपयोग करने के लिए शिक्षकों को निरंतर सीखते रहना होगा। जब शिक्षक तकनीकी रूप से सक्षम होंगे, तभी वे छात्रों को सही दिशा में मार्गदर्शन दे पाएंगे। समग्र रूप से देखा जाए तो एआई शिक्षा को अधिक उन्नत, सुलभ और प्रभावी बना रहा है, लेकिन इसके साथ नई चुनौतियाँ भी उत्पन्न हो रही हैं। यह एक ऐसा दौर है जहाँ अवसर और जोखिम दोनों साथ–साथ मौजूद हैं। इसलिए आवश्यक है कि इस परिवर्तन को संतुलित दृष्टिकोण के साथ स्वीकार किया जाए। निष्कर्षतः यह स्पष्ट है कि कृत्रिम मेधा आधारित शिक्षा शिक्षक की भूमिका को समाप्त नहीं कर रही, बल्कि उसे नए रूप में स्थापित कर रही है। यह परिवर्तन माध्यम का है, उद्देश्य का नहीं। शिक्षक आज भी शिक्षा का केंद्र है और रहेगा, क्योंकि वही छात्रों के भीतर मूल्य, संवेदनशीलता और सोचने की क्षमता विकसित करता है। भविष्य की शिक्षा वही होगी जहाँ एआई और शिक्षक एक–दूसरे के सहयोगी बनकर कार्य करेंगे। जब तकनीक की गति और शिक्षक की संवेदना एक साथ आएंगी, तब एक ऐसी शिक्षा प्रणाली का निर्माण होगा जो न केवल ज्ञान प्रदान करेगी, बल्कि एक सशक्त और जागरूक समाज की नींव भी रखेगी।

कर्नाटक ने 'खेलो इंडिया जनजातीय खेलों' के पहले दिन दबदबा कायम किया

रायपुर, (भाषा) कर्नाटक ने तैराकी में अपना दबदबा दिखाते हुए बुधवार से यहां शुरू हुए पहले 'खेलो इंडिया जनजातीय खेलों (केआईटीजी)' के शुरुआती दिन छह में से पांच स्वर्ण पदक जीते, जिसमें पुरुषों की 200 मीटर फ्रीस्टाइल स्पर्धा में धोनीश एन ने शानदार प्रदर्शन किया। धोनीश ने 2:03.55 सेकंड का समय निकाला, जो दूसरे स्थान पर रहे उनके ही राज्य के कीर्तन शरत (2:10.99 सेकंड) से लगभग सात सेकंड बेहतर था। महाराष्ट्र के भक्तिश कुमरे (2:14.73 सेकंड) ने कांस्य पदक जीता। पहले दिन के मुकाबलों के बाद कर्नाटक सात पदकों (पांच स्वर्ण सहित) के साथ तालिका में शीर्ष पर रहा, जबकि ओडिशा चार पदकों (एक स्वर्ण सहित) के साथ दूसरे स्थान पर है। मेजबान छत्तीसगढ़ दो पदकों के साथ चौथे स्थान पर है। ओडिशा की अंजलि मुंडा ने भी महिला 200 मीटर फ्रीस्टाइल में शानदार प्रदर्शन करते हुए 2:39.02 सेकंड के समय के साथ स्वर्ण पदक जीता। यह मुकाबला बेहद करीबी रहा, जिसमें कर्नाटक की निधि एस (2:39.09 सेकंड) ने रजत पदक हासिल किया, जबकि ओडिशा की श्रिया पडियामी (2:49.04 सेकंड) तीसरे स्थान पर रहीं। कर्नाटक ने लगभग हर स्पर्धा में वर्चस्व बनाए रखा, जहां मणिकांत एल और मेहांजली ने दो–दो स्वर्ण पदक अपने नाम किए। मणिकांत ने पुरुषों की 100 मीटर ब्रेस्टस्ट्रोक (1:07.41 सेकंड) और 50 मीटर बटरफ्लाई (27.06 सेकंड) में शीर्ष स्थान हासिल किया तो वहीं मेहांजली ने 100 मीटर ब्रेस्टस्ट्रोक (1:25.81 सेकंड) और 50 मीटर बटरफ्लाई में (34.67 सेकंड) में अपना प्रभुत्व कायम किया। केआईटीजी में कुल 30 राज्य और केंद्रशासित प्रदेश भाग ले रहे हैं। इसमें लगभग 3,800 खिलाड़ी नौ खेलों में प्रतिस्पर्धा कर रहे हैं। इन खेलों में तीरंदाजी, एथलेटिक्स, फुटबॉल, हॉकी, तैराकी, भारोत्तोलन और कुश्ती में कुल 106 स्वर्ण पदक दांव पर होंगे, जबकि मल्लखंब और कबड्डी जैसे पारंपरिक खेल प्रदर्शन स्पर्धाओं के रूप में शामिल किए गए हैं।

कार्यभार प्रबंधन के तहत ज़ोरावर को टीम से बाहर रखा गया है: ट्रैप कोच पीटर विल्सन

नयी दिल्ली, (भाषा) भारत के विदेशी ट्रैप कोच पीटर विल्सन ने कहा कि देश के शीर्ष ट्रैप निशानेबाज जोरावर सिंह संधू को कार्यभार प्रबंधन के तहत सत्र के पहले आईएसएसएफ शॉटगन विश्व कप के लिए टीम में नहीं चुना गया है।। भारत ने मोरक्को के टैंजियर में होने वाले विश्व कप के लिए 12 सदस्यीय टीम भेजी है, लेकिन जोरावर की अनुपस्थिति स्पष्ट रूप से ध्यान आकर्षित कर रही है। जोरावर विश्व चैंपियनशिप में कांस्य पदक विजेता रहे थे और पिछले साल इस बड़े मंच पर पदक जीतने वाले तीसरे भारतीय ट्रैप निशानेबाज बने थे। लंदन ओलंपिक के स्वर्ण पदक विजेता विल्सन ने टैंजियर रवाना होने से पहले पीटीआई को बताया कि 46 वर्षीय दिग्गज जोरावर 'शत प्रतिशत' टीम में वापसी करेंगे, क्योंकि अगला साल भारतीय निशानेबाजी के लिए महत्वपूर्ण है। इस साल 2028 में लॉस एंजिलिस में होने वाले ओलंपिक खेलों के लिए क्वालीफाइंग प्रतियोगिताएं शुरू होगी। जोरावर वर्तमान में विश्व रैंकिंग में चौथे स्थान पर हैं और उनकी रैंकिंग को देखते हुए उन्हें भारत के लिए सबसे अच्छा विकल्प माना जाना चाहिए था। विल्सन ने कहा, ''जोरावर चाहे विश्व में पहले, दूसरे या फिर आखिरी स्थान पर क्यों ना हो हमें उनका कार्यभार प्रबंधन करना है। आप उनसे प्रत्येक प्रतियोगिता में भाग लेने की उम्मीद नहीं कर सकते हैं।'' उन्होंने कहा, ''हमारे पास अच्छे खिलाड़ी हैं और मैं चाहता हूं कि उन सभी को विश्व स्तर पर खेलने का मौका मिले। जहां तक जोरावर का सवाल है तो सबसे अच्छा यही होगा कि आप भारतीय राष्ट्रीय राइफल संघ से संपर्क करें।'' दिलचस्प बात यह है कि अगले महीने कजाकिस्तान के अल्माटी में होने वाले आईएसएसएफ शॉटगन विश्व कप में भी जोरावर का नाम शामिल नहीं है। विल्सन ने कहा कि इस साल के लिए उनकी योजना खिलाड़ियों पर प्रतियोगिताओं का अत्यधिक व्यस्त कार्यक्रम थोपने से बचना है। उन्होंने कहा, ''इस साल के लिए मेरी योजना है कि मैं खिलाड़ियों को बहुत अधिक व्यस्त नहीं रखूं। मैं नहीं चाहता कि भारतीय निशानेबाज पिछले वर्षों की तरह साल के आखिर तक पूरी तरह थक जाएं। हम खिलाड़ियों के कार्यभार का अच्छी तरह से प्रबंधन करेंगे।''

भारतीय टीम इस प्रकार है: ट्रैप : पुरुष: पृथ्वीराज टोंडाइमन, किनान चेनाई, भौनीश मेंदीरत्ता। **महिला:** कीर्ति गुप्ता, राजेश्वरी कुमारी, आशिमा अहलावत। **स्कीट: पुरुष:** मान सिंह, ज्योतिरादित्य सिंह सिसौदिया, परमपाल सिंह। महिला: यशस्वी राठौड़, दर्शना राठौड़, माहेश्वरी चौहान। **मिश्रित टीम:** पृथ्वीराज टोंडाइमन और कीर्ति गुप्ता; किनान चेनाई और राजेश्वरी कुमारी।

वनडे विश्व कप खिताब ने हमें दुनिया में कहीं भी जीतने का आत्मविश्वास दिया: हरमनप्रीत

नयी दिल्ली, (भाषा) भारतीय महिला क्रिकेट टीम की कप्तान हरमनप्रीत कौर ने बुधवार को कहा कि पिछले साल घरेलू मैदान पर वनडे विश्व कप जीतने से टीम को दुनिया में कहीं भी और खिताब जीतने के लिए बहुत जरूरी आत्मविश्वास मिला। भारतीय महिला टीम ने पिछले साल नवंबर में नवी मुंबई में दक्षिण अफ्रीका को हराकर अपना पहला आईसीसी खिताब जीता था। हरमनप्रीत को उम्मीद है कि 12 जून से पांच जुलाई तक ब्रिटेन में होने वाले महिला टी20 विश्व कप में भी टीम यह कारनामा दोहराने में सफल रहेगी।द्वारका के ओमेक्स स्टेडियम में उनके सम्मान में बने स्टैंड के नामकरण समारोह के दौरान हरमनप्रीत ने कहा, ''मेरा मानना है कि किसी भी क्षेत्र में आपको कुछ खास करना होता है। आपको कोई खिताब जीतना होता है, तभी आपको पहचान मिलती है। ऐसा न होने पर मानो लगता है कि सारी मेहनत बेकार चली गई।'' उन्होंने कहा, ''हमारी टीम ही नहीं हमसे पहले की सभी महिला क्रिकेटरों ने कड़ी मेहनत की। उन्हें तो अक्सर अपनी जेब से भी पैसे खर्च करने पड़े थे। इसलिए खिताब जीतना बहुत महत्वपूर्ण था। खिताब हासिल करने के बाद भारतीय प्रशंसकों, मीडिया और बाकी सभी से जो प्रतिक्रिया हमें मिल रही है, वह हमारे लिए बहुत मायने रखती है।'' इस साल के टी20 विश्व कप में वनडे विश्व कप का प्रदर्शन दोहराने की उम्मीद के बारे में हरमनप्रीत ने कहा, ''हम टी20 विश्व कप जीतने के लिए अपना सर्वश्रेष्ठ प्रयास करेंगे। वनडे विश्व कप ने हमें जरूरी आत्मविश्वास दिया है और अब हमें विश्वास है कि हम दुनिया में कहीं भी विश्व कप जीत सकते हैं।'' भारत ने हाल ही में ऑस्ट्रेलिया का दौरा किया, जहां उसने कई प्रारूपों की श्रृंखला खेली, जिसमें तीन टी20 अंतरराष्ट्रीय मैच, इतने ही वनडे मैच और एक गुलाबी गेंद का टेस्ट मैच शामिल था। भारत यह श्रृंखला अंकों के आधार पर 4–12 से हार गया लेकिन हरमनप्रीत ने कहा कि इससे उनकी टीम को काफी कुछ सीखने को मिला। उन्होंने कहा, '' इस तरह की बहु प्रारूप वाली श्रृंखला होनी चाहिए क्योंकि इससे आपको नयी चुनौतियों का सामना करने को मिलता है। एक सप्ताह के बाद आपको दूसरे प्रारूप में खेलना होता है इसलिए मुझे लगता है कि यह बिल्कुल अलग तरह का अनुभव है।'' हरमनप्रीत ने कहा, "क्रिकेटर के तौर पर हमने कभी ऐसा अनुभव नहीं किया था। पहले हम अधिकतर टी20 या वनडे खेलते थे, लेकिन एक श्रृंखला में तीनों प्रारूप में खेलना थोड़ा चुनौती पूर्ण था।'' हरमनप्रीत ने इसके साथ ही कहा कि इस स्टेडियम में एक स्टैंड का नाम उनके नाम पर रखे जाने से वह भावुक है।

आईपीएल का दूसरे चरण 13 अप्रैल से 24 मई तक चलेगा: बीसीसीआई

नयी दिल्ली, (भाषा) भारतीय क्रिकेट बोर्ड (बीसीसीआई) ने बृहस्पतिवार को आईपीएल 2026 के लीग चरण का कार्यक्रम जारी करते हुए बताया कि टूर्नामेंट का दूसरा चरण 13 अप्रैल से 24 मई तक होगा। शुरुआती चरण 28 मार्च से 12 अप्रैल तक चलेगा और इसके कार्यक्रम पहले ही जारी कर दिये गये हैं। इसका आगाज शनिवार को एम. चिन्नास्वामी स्टेडियम में मौजूदा चैंपियन रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु और सनराइजर्स हैदराबाद की भिड़ंत से होगा। फाइनल 31 मई को बेंगलुरु में खेला जाएगा। बीसीसीआई सचिव देवाजित सैकिया ने कहा, " लीग चरण के दूसरे हिस्से में 50 मैच खेले जायेंगे। इसका आयोजन 13 अप्रैल से 24 मई 2026 तक भारत के 12 स्थलों पर होगा। इस चरण में मुकाबले बेंगलुरु, मुंबई, चेन्नई, कोलकाता, दिल्ली, अहमदाबाद, हैदराबाद, लखनऊ, जयपुर, धर्मशाला, रायपुर और न्यू चंडीगढ़ में होंगे।" उन्होंने कहा कि टूर्नामेंट के इस अहम चरण में टीमें प्लेऑफ में जगह बनाने के लिए भिड़ेंगी जिससे मुकाबले और अधिक प्रतिस्पर्धी होंगे। दूसरे चरण का पहला मैच 13 अप्रैल को हैदराबाद में सनराइजर्स हैदराबाद और राजस्थान रॉयल्स के बीच खेला जाएगा। इस चरण में आठ 'डबल–हेडर' (एक दिन में दो मुकाबले) होंगे। पंजाब किंग्स की टीम अपने घरेलू मैच न्यू चंडीगढ़ और धर्मशाला में खेलेगी, जिसमें धर्मशाला में तीन मैच होंगे। राजस्थान रॉयल्स की टीम अपने चार घरेलू मुकाबले जयपुर में खेलेगी। रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु तीन मैच बेंगलुरु और दो मैच रायपुर में खेलेगी। प्लेऑफ के लिए मैचों के स्थानों की घोषणा बाद में की जाएगी।

जम्मू में पहले हाफ मैराथन के लिए 3600 प्रतिभागियों ने किया पंजीकरण

जम्मू, (भाषा) पर्यटन को बढ़ावा देने और फिटनेस गतिविधियों में जनता की भागीदारी को प्रोत्साहित करने के उद्देश्य से पहले जम्मू हाफ मैराथन का आयोजन रविवार को होगा। इस मैराथन में 21 किलोमीटर, 10 किलोमीटर और पांच किलोमीटर की दौड़ स्पर्धाएं आयोजित की जाएगी। मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला ने 'जम्मू मैराथन एक्सपो' के उद्घाटन के मौके पर कहा कि सरकार का प्रयास पर्यटन और स्वस्थ जीवनशैली को बढ़ावा देना है। उन्होंने कहा, "इस दृष्टि से यह हमारे लिए बहुत खुशी की बात है कि रविवार को हम जम्मू हाफ मैराथन के पहले आयोजन में 10 किलोमीटर और पांच किलोमीटर दौड़ स्पर्धा भी आयोजित कर रहे हैं।" अब्दुल्ला ने बताया कि इस आयोजन को केन्द्र शासित प्रदेश और उसके बाहर से उत्साहजनक प्रतिक्रिया मिली है। उन्होंने कहा, "800 से अधिक प्रतिभागी जम्मू एवं कश्मीर के बाहर से आ रहे हैं, जबकि केन्द्र शासित प्रदेश से लगभग 2,800 पंजीकरण हुए हैं। विदेशी धावकों की भागीदारी ने आयोजन की लोकप्रियता और बढ़ा दी है।" अधिकारियों ने बताया कि कुल 3,558 घरेलू और 90 अंतरराष्ट्रीय प्रतिभागी इस मैराथन में भाग लेंगे। उन्होंने इसे उत्साहजनक भागीदारी करार देते हुए उम्मीद जताई कि भविष्य में यह आयोजन और बड़े पैमाने पर लोकप्रिय होगा।

एशियाई खेलों में पदक जीतने के 'अधूरे काम' को पूरा करना चाहती हैं मीराबाई चानू

रायपुर, (भाषा) तोक्यो ओलंपिक की रजत पदक विजेता भारोत्तोलक मीराबाई चानू ने कहा कि एशियाई खेलों में पदक जीतना इस साल उनका सबसे बड़ा लक्ष्य है। पिछले एक दशक से अधिक समय से मीराबाई चानू भारतीय भारोत्तोलन का चेहरा रही हैं। उनके शानदार करियर में एशियाई खेलों का पदक ही एकमात्र ऐसी उपलब्धि है, जो अभी तक उनके खाते में नहीं जुड़ पाई है। उनके पास तोक्यो ओलंपिक का रजत, विश्व चैंपियनशिप के तीन पदक और राष्ट्रमंडल खेलों में भी तीन पदक हैं। चानू ने यहां खेलो इंडिया जनजातीय खेलों (केआईटीजी) के उद्घाटन समारोह के बाद संवाददाता सम्मेलन में कहा, "एशियाई खेल मेरे लिए व्यक्तिगत रूप से बहुत महत्वपूर्ण हैं क्योंकि वहां मेरा काम पूरा नहीं हुआ है। एशियाई खेलों में प्रतिस्पर्धा का स्तर बहुत ऊंचा होता है, जिससे यह और चुनौतीपूर्ण और रोमांचक बन जाता है।" एशियाई खेलों में चानू का सफर उतार–चढ़ाव भरा रहा है। उन्होंने 2014 एशियाई खेलों में पदार्पण करते हुए नौवां स्थान हासिल किया था, जबकि पीठ की चोट के कारण उन्हें 2018 संस्करण से बाहर रहना पड़ा। वह 2022 एशियाई खेलों में पदक के सबसे करीब पहुंची थीं, लेकिन कूल्हे की चोट के कारण अहम समय पर उनका अभियान प्रभावित हुआ और वह पदक से मामूली अंतर से चूक गईं। अब 31 वर्षीय चानू महाद्वीपीय प्रतियोगिता में संभवतः अपने अंतिम प्रयास की तैयारी कर रही हैं और उनका लक्ष्य अपने शानदार करियर में इस एकमात्र कमी को पूरा करना है। इस साल जुलाई–अगस्त में होने वाले राष्ट्रमंडल खेलों और 19 सितंबर से शुरू होने वाले एशियाई खेलों के बीच वजन संतुलन बनाना उनके लिए बड़ी चुनौती होगा। वह राष्ट्रमंडल खेलों में 48 किग्रा वर्ग में हिस्सा लेंगी, जबकि एशियाई खेलों के लिए फिर से 49 किग्रा वर्ग में वापसी करेंगी। उन्होंने कहा, "मैं राष्ट्रमंडल खेलों तक अपना वजन 48 किग्रा के भीतर रखूंगी, लेकिन इसके दो महीने बाद ही एशियाई खेल हैं जो 49 किग्रा वर्ग में हैं, इसलिए मुझे फिर से बदलाव करना होगा।" चानू ने खेलो इंडिया जनजातीय खेलों की शुरुआत की सराहना करते हुए इसे दूरदराज के इलाकों के खिलाड़ियों के लिए महत्वपूर्ण मंच बताया। उन्होंने कहा, "एक खिलाड़ी के तौर पर मेरे लिए यह गर्व का क्षण है कि सरकार केआईटीजी जैसी पहल को प्राथमिकता दे रही है। यह प्रतियोगिता दूरदराज के क्षेत्रों से आने वाले खिलाड़ियों को अपनी प्रतिभा दिखाने का मंच देगी।" उन्होंने कहा, "मैंने देशभर में, खासकर पूर्वोत्तर और अन्य जनजातीय क्षेत्रों में ऐसे कई उदाहरण देखे हैं, जहां प्रतिभा तो है लेकिन ऐसे मंचों की कमी के कारण वह निखर नहीं पाती।"

मांडविया चाहते हैं कि ओलंपिक के लिए क्वालीफाई करें भारतीय लैक्रोस टीम

नयी दिल्ली, (भाषा) खेल मंत्री मनसुख मांडविया ने हाल में एशियाई प्रतियोगिता में स्वर्ण पदक जीतने वाली भारतीय पुरुष और महिला लैक्रोस टीमों को बुधवार को यहां सम्मानित किया और वह चाहते हैं कि ये टीमें 2028 में लॉस एंजिलिस में होने वाले ओलंपिक खेलों के लिए क्वालीफाई करे। लैक्रोस कम प्रचलित खेल है और यह खेल 100 वर्ष से भी अधिक समय के बाद ओलंपिक में वापसी करेगा। यह मूल रूप से अमेरिकी खेल है जिसमें जालीदार सिरे वाली लंबी छड़ी का उपयोग करके रबर की गेंद को पकड़ा जाता है, पास दिया जाता है और प्रतिद्वंद्वी के गोल में फेंका जाता है। इस खेल ने 1904 में एक पदक स्पर्धा के रूप में ओलंपिक में पदार्पण किया था। इसके चार साल बाद फिर से यह ओलंपिक का हिस्सा बना। इसके बाद 1928, 1932 और 1948 में प्रदर्शनी खेल बना रहा। मांडविया ने दोनों टीमों से कहा, ''लैक्रोस भारत में अपनी जड़ें जमा रहा है। यह आपका पहला बड़ा अंतरराष्ट्रीय अनुभव था और आप पहले ही पदक जीत चुके हैं। अब आपका ध्यान और अधिक मेहनत करने, अधिक अनुभव प्राप्त करने और ओलंपिक 2028 के लिए क्वालीफाई करके देश को गौरवान्वित करने पर होना चाहिए।'' भारत ने फरवरी में सऊदी अरब के रियाद में आयोजित एशियाई लैक्रोस खेलों में शानदार प्रदर्शन किया। भारत ने छह खिलाड़ियों वाले प्रारूप में पुरुष और महिला दोनों वर्ग में स्वर्ण पदक जीते। ओलंपिक 2028 में इसी प्रारूप में स्पर्धाएं होगी। भारत की पुरुष टीम ने फाइनल में इराक जबकि महिला टीम ने पाकिस्तान को हराया। इन दोनों टीमों में राजस्थान, महाराष्ट्र, हरियाणा, गुजरात, तमिलनाडु, ओडिशा, असम, जम्मू और कश्मीर, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना और उत्तर प्रदेश सहित देश के सभी हिस्सों के खिलाड़ी शामिल हैं। भारतीय टीम अब चीन के चेंगडू में अप्रैल में तीसरे एशियाई लैक्रोस खेलों में भाग लेंगी जिसके बाद अक्टूबर में आस्ट्रेलिया में एशिया पेसीफिक सिक्सेस लैक्रोस चैम्पियनशिप खेली जानी है जो लॉस एंजिलिस ओलंपिक 2028 का क्वालीफायर भी होगी ।

हॉकी इंडिया सालाना पुरस्कारों में दोहरे नामांकन से खुद पर भरोसा मजबूत हुआ : गोलकीपर प्रिंस दीप

नयी दिल्ली, (भाषा) अभी तक सीनियर टीम में पदार्पण नहीं करने के बावजूद हॉकी इंडिया सालाना पुरस्कारों में दो नामांकन पाने वाले युवा गोलकीपर प्रिंस दीप सिंह ने कहा कि इससे उनका खुद पर भरोसा मजबूत हुआ है । सीनियर पुरूष राष्ट्रीय शिविर में अभ्यास कर रहे 21 वर्ष के प्रिंस दीप को हॉकी इंडिया बलजीत सिंह वर्ष 2025 के सर्वश्रेष्ठ गोलकीपर और हॉकी इंडिया जुगराज सिंह वर्ष 2025 के सर्वश्रेष्ठ उदीयमान खिलाड़ी के पुरस्कार के लिये नामांकन मिला है । ये पुरस्कार शुक्रवार को यहां दिये जायेंगे । प्रिंस दीप ने कहा ,'' मैं बहुत खुश हूं और गर्व महसूस कर रहा है । ऐसे पुरस्कारों के लिये नामांकन पाने में समय लगता है लेकिन मुझे जल्दी मिल गया । टूर्नामेंटों में अच्छे प्रदर्शन और शीर्ष गोलकीपरों के साथ अपना नाम देखकर काफी प्रेरणा मिल रही है ।'' उन्होंने कहा ,'' भारत के पास बेहतरीन गोलकीपर हैं । उनके बीच नामांकन पाना और वह भी सीनियर टीम में पदार्पण से पहले , खास है । इससे मुझे आत्मविश्वास मिला है कि मैं सही रास्ते पर हूं ।'' उन्होंने कहा ,''यह इस सम्मान से मिला सबसे बड़ा तोहफा है । इससे खुद पर संशय नहीं रह गया और आगे अच्छा करने की प्रेरणा मिली है । अब मुझे पता है कि मैं सही राह पर हूं और लगातार सुधार करता रहूंगा ।'' प्रिंस दीप 2024 एफआईएच जूनियर एशिया कप में स्वर्ण, जोहोर कप 2025 में रजत और पिछले साल चेन्नई में एफआईएच जूनियर विश्व कप में कांस्य पदक जीत चुके हैं । पठानकोट के रहने वाले प्रिंस दीप ने शुरूआत फुल बैक के रूप में बटाला की चीमा हॉकी अकादमी में की थी । उन्होंने बताया ,'' मैं फुटबॉल में गोलकीपर के रूप में खेलता था और कुछ अच्छे गोल बचाये । मेरे कोचों ने मेरा कद देखकर हॉकी में गोलकीपिंग का सुझाव दिया । वहीं से शुरूआत हुई ।''

एशिया कप चरण एक क्वालीफायर में भारत ने दबदबा कायम किया

बैंकॉक, (भाषा) एशिया कप विश्व रैंकिंग टूर्नामेंट के चरण एक में मंगलवार को भारत के युवा रीकर्व तीरंदाजों ने जहां शानदार प्रदर्शन करते हुए अपनी क्षमता का परिचय दिया, वहीं अनुभवी कंपाउंड तीरंदाजों ने दबदबा कायम रखा। भारत ने छह स्पर्धाओं में क्वालिफिकेशन में शीर्ष स्थान हासिल करते हुए नए अंतरराष्ट्रीय सत्र की मजबूत शुरुआत की। भारत ने कई प्रमुख खिलाड़ियों की अनुपस्थिति में अपनी 'दूसरे दर्जे' की टीम उतारी थी, बावजूद इसके टीम ने पुरुष कंपाउंड व्यक्तिगत और टीम, पुरुष रीकर्व टीम, महिला कंपाउंड टीम तथा रीकर्व और कंपाउंड मिक्स्ड टीम स्पर्धाओं में शीर्ष स्थान हासिल किया। देवांग गुप्ता (663), सुखचैन सिंह (657) और जुयेल सरकार (654) की रीकर्व पुरुष तिकड़ी ने शानदार प्रदर्शन करते हुए भारत को टीम स्पर्धा में शीर्ष वरीयता दिलाई और क्वार्टर फाइनल में सीधा प्रवेश दिलाया, जहां उनका मुकाबला भूटान (नंबर नौ) और मंगोलिया (नंबर आठ) के बीच होने वाले मुकाबले के विजेता से होगा। चीन और कजाकिस्तान क्रमशः दूसरे और तीसरे स्थान पर रहे। महिला रीकर्व वर्ग में रूमा विश्वास ने शानदार प्रदर्शन करते हुए 650 अंकों के साथ दूसरा स्थान हासिल किया, जबकि वह सिंगापुर की शीर्ष तीरंदाज से मात्र तीन अंक पीछे रहीं। कीर्ति (10वां स्थान) और रिद्धि (17वां स्थान) अन्य प्रमुख भारतीय प्रदर्शनकर्ता रहीं। टीम ने मलेशिया और वियतनाम के बाद तीसरा स्थान हासिल किया। कंपाउंड वर्ग में अनुभवी भारतीय तीरंदाजों ने पूरी तरह दबदबा बनाया और व्यक्तिगत क्वालिफिकेशन में शीर्ष चार स्थान अपने नाम किए। रजत चौहान ने 720 में से 712 अंक लेकर पहला स्थान हासिल किया। उनके बाद रिषभ यादव, प्रथमेश जावकर और उदय कंबोज क्रमशः दूसरे, तीसरे और चौथे स्थान पर रहे। महिला कंपाउंड वर्ग में 20 वर्षीय चिकिता तनिपार्थी ने 697 अंकों के साथ चौथा स्थान हासिल कर भारतीय चुनौती का नेतृत्व किया। उनके बाद राज कौर और तेजल साल्वे रहीं, जिन्होंने टीम को शीर्ष वरीयता दिलाने में अहम भूमिका निभाई। भारत ने रीकर्व और कंपाउंड दोनों मिक्स्ड टीम स्पर्धाओं में भी शीर्ष स्थान हासिल कर अपनी समग्र ताकत का परिचय दिया।

मेरी यात्रा यहीं समाप्त होती है: रियो ओलंपिक चैंपियन शटलर कैरोलिना मारिन ने संन्यास की घोषणा की

नयी दिल्ली, (भाषा) बैडमिंटन की दिग्गज खिलाड़ी कैरोलिना मारिन ने घुटने की चोट से लंबे समय तक परेशान रहने के बाद बृहस्पतिवार को अपने पेशेवर करियर से संन्यास लेने की घोषणा की। उनके करियर में ओलंपिक स्वर्ण पदक और तीन विश्व चैंपियनशिप खिताब शामिल हैं। मारिन ने सोशल मीडिया पर वीडियो संदेश साझा कर कहा, "मेरा सफर यहीं समाप्त होता है।" उन्होंने बताया कि चोट के कारण उन्होंने अपने स्वास्थ्य को प्राथमिकता देते हुए प्रतियोगिता से दूर रहने का कठिन निर्णय लिया। उन्होंने कहा, "मैं चाहती थी कि हम आखिरी बार ट्रैक पर मिलें, लेकिन मैं अपने शरीर को जोखिम में नहीं डालना चाहती।" इस 32 साल की खिलाड़ी ने भारत की दो बार की ओलंपिक पदक विजेता पी.वी. सिंधू के साथ कई यादगार मुकाबले खेले। उन्होंने रियो 2016 ओलंपिक और 2018 विश्व चैंपियनशिप के फाइनल में सिंधू को हराया था। उनके करियर में 2014, 2015 और 2018 में विश्व चैंपियनशिप, सात यूरोपीय खिताब और 2016 ओलंपिक स्वर्ण पदक शामिल हैं। मारिन का अंतिम प्रतिस्पर्धी प्रदर्शन पेरिस 2024 ओलंपिक में हुआ, जो दो गंभीर एसीएल चोटों के बाद उनकी शानदार वापसी थी। वह हुएल्वा में आयोजित होने वाले आगामी यूरोपीय चैंपियनशिप में प्रतिस्पर्धा नहीं करेंगी, लेकिन अपने शहर के सम्मान में वहां उपस्थित रहेंगी। उन्होंने कहा, "मैं हुएल्वा में रैकेट हाथ में नहीं लूंगी, लेकिन अपनी ऊर्जा शहर को लौटाते हुए संन्यास लूंगी।" मारिन ने अपने खेल जीवन पर गर्व जताते हुए कहा, "मुझे खेल जगत में अपनी सभी उपलब्धियों पर बहुत गर्व है। न केवल खिताबों के लिए, बल्कि मैदान के अंदर और बाहर दोनों जगह सम्मान अर्जित करने के लिए भी।"

गुवाहाटी में भी होगा बॉर्डर–गावस्कर श्रृंखला का मैच, स्वदेश में नौ वनडे खेल सकते हैं रोहित कोहली

नयी दिल्ली, (भाषा) पिछले साल नवंबर में दक्षिण अफ्रीका के खिलाफ टेस्ट मैच की मेजबानी करने के बाद अब गुवाहाटी का बारसपारा स्टेडियम 2027 में भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच होने वाली बॉर्डर गावस्कर ट्रॉफी के पांच में से एक मैच की मेजबानी करेगा। भारतीय क्रिकेट बोर्ड (बीसीसीआई) ने बृहस्पतिवार को सीनियर पुरुष टीम के घरेलू सत्र का कैलेंडर जारी किया जिसमें पांच टेस्ट, नौ वनडे और आठ टी20 मैच शामिल हैं। वनडे मैचों पर निश्चित रूप से सबकी नजर रहेगी क्योंकि विराट कोहली और रोहित शर्मा की दिग्गज जोड़ी के उन सभी मैचों में खेलने की उम्मीद है। यह दोनों स्टार बल्लेबाज अब केवल वनडे प्रारूप में ही खेलते हैं। ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ श्रृंखला जनवरी, फरवरी और मार्च 2027 में खेली जाएगी। इसकी शुरुआत 21 जनवरी को नागपुर में होगी। इसके बाद दूसरा टेस्ट मैच चेन्नई में (29 जनवरी से दो फरवरी) और आठ दिन के अंतराल के बाद तीसरा टेस्ट 11 से 15 फरवरी तक गुवाहाटी में खेला जाएगा। रांची में चौथा टेस्ट 19 से 23 फरवरी के बीच खेला जाएगा, जबकि अहमदाबाद में अंतिम टेस्ट 27 फरवरी से शुरू होगा। पांच स्थानों में से नागपुर (जहां आखिरी बार 2023 में ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ टेस्ट मैच हुआ था), चेन्नई (जहां आखिरी बार 2024 में बांग्लादेश के खिलाफ टेस्ट मैच हुआ था), रांची (जहां आखिरी बार 2024 में इंग्लैंड के खिलाफ टेस्ट मैच हुआ था) और अहमदाबाद (जहां आखिरी बार अक्टूबर 2025 में वेस्टइंडीज के खिलाफ टेस्ट मैच हुआ था) को रोटेशन नीति के अनुसार मेजबानी मिली है। लेकिन यह स्पष्ट नहीं हो पाया कि गुवाहाटी को फिर से मेजबानी कैसे मिली जबकि उसने नवंबर 2025 में दक्षिण अफ्रीका के खिलाफ एक टेस्ट मैच आयोजित किया था। गौर करने वाली बात यह है कि मुंबई और कोलकाता इस महत्वपूर्ण श्रृंखला का हिस्सा नहीं हैं। यह पता नहीं चल पाया कि बंगाल क्रिकेट संघ या मुंबई क्रिकेट संघ ने ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ टेस्ट मैच की मेजबानी करने में असमर्थता व्यक्त की थी या नहीं। भारत के घरेलू सत्र में ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ पांच टेस्ट मैच की श्रृंखला आकर्षण का मुख्य केंद्र होगी।

रंगमंच को संवारने के संकल्प का दिन

नाटक दर्शकों को प्रेम, रहस्य, रोमांच, हर्ष, खुशी, आत्मीयता और सौंदर्य की उस ऊंचाई पर ले जाता है जहां वे कल्पना लोक में विचरण कर रहे होते हैं जो खुरदुरे पठारी यथार्थ से परे एक अलग दुनिया होती है। नाटक के मंचन से उद्भूत रस प्रेक्षागृह में उपस्थित दर्शकों को आत्मानंद की प्राप्ति कराने में समर्थ होता है, इसीलिए नाट्य रस को परमानंद सहोदर कहा गया है। नाटक संस्कृत वांग्मय के शीर्ष आर्ष ग्रंथ वेदों की पंक्ति में पंचम वेद की संज्ञा से विभूषित हो लोक में समादृत हुआ है। ब्रह्मा जी ने ऋग्वेद से पाठ्य, सामवेद से गायन कला, यजुर्वेद से अभिनय और अथर्ववेद से रस लेकर नाट्यवेद की रचना की है। संस्कृत साहित्य में नाट्य लेखन एवं मंचन की समृद्ध परम्परा रही है जो इस्लाम के आगमन तक फलती–फूलती रही पर इस्लामी आक्रमणों एवं राज्याश्रय न मिलने के कारण नाट्य–संस्कृति की यह पुण्यबेल निर्जीव–रसहीन हो मृतप्राय हो गयी। हालांकि 18वीं सदी से ब्रज, अवधी, छत्तीसगढ़ी में हिंदी नाटकों का लेखन मंचन गतिमान हुआ लेकिन 20वीं शती के उत्तरार्ध काल में संचार और तकनीकी के क्षेत्र में हो रहे नित नवल अनुसंधानों एवं सुविधाओं के कारण जन मनोरंजन के तमाम सुगम संसाधनों की उपलब्धता से रंगमंच पर दुष्प्रभाव पड़ा है। दर्शकों की अनुपलब्धता से नाट्य मंडलियां काम के अभाव में बंद हुईं और रंगमंच को समर्पित संस्थान भी आभाहीन हुए। तो 1948 में पेरिस में स्थापित इंटरनेशनल थियेटर इन्स्टीट्यूट ने रंगमंच के प्रति जागरूकता के प्रसार, रंगमंचीय संस्कृति एवं मूल्यों से आमजन को परिचित कराने, नाटकों के आनंद को परस्पर साझा करने और रंगमंच की पुनर्स्थापना की दृष्टि से 1961 में विश्व रंगमंच दिवस मनाने का संकल्प लिया और पहली बार 27 मार्च, 1962 को यह दिवस मनाया गया। इसमें वैश्विक शांति के लिए रंगमंच एवं संस्कृति पर आधारित किसी प्रसिद्ध एवं समर्पित रंगमंचीय कला साधक के आमंत्रित संदेश का 50 भाषाओं में अनुवाद प्रकाशित कर सभी देशों में प्रसारित किया जाता है ताकि लोग रंगमंच के महत्व से अवगत हों। पहला रंगमंच संदेश 1962 में फ्रांसीसी थिएटर कलाकार जॉन काक्त्यू ने दिया था। भारत के किसी कला साधक को यह सम्मान पहली बार 2002 में गिरीश कर्नाड को मिला। प्रत्येक वर्ष एक थीम का निश्चय कर तदनुरूप आयोजन किये जाते हैं। वर्ष 2025 की थीम थी रंगमंच और शांति की संस्कृति। भारत में रंगमंच की समृद्ध एवं गौरवशाली परम्परा अति प्राचीन काल से ही रही है। सर्वप्रथम ऋग्वेद में यम और यमी तथा पुरुरवा एवं उर्वशी के बीच हुए संवाद के दृश्य दिखायी देते हैं। भरत मुनि का नाट्यशास्त्र रंगकर्म का सर्वोत्कृष्ट ग्रंथ है जिसमें नाट्य लेखन, पात्र चयन, अभिनय, मंचन, प्रेक्षागृह, रंगमंडप, नेपथ्य और रंगपीठ पर विशद विश्लेषण परक सामग्री है। साथ ही कथानक, संवाद कथन, ध्वनि एवं प्रकाश, साज–सज्जा, पात्र, रंग शिल्प, रस एवं दर्शक आदि पर भी विस्तार से विचार किया है। भारत के प्राचीन नाट्य मंचन स्थानों में रामगढ़ (छत्तीसगढ़), सीता गुफा, फुलमुई गुफा (नासिक, महाराष्ट्र) उल्लेखनीय है। ये सभी नाटक मंचन के स्थान अंशतरू प्राकृतिक हैं पर पहाड़ काट कर मंचीय बनाये गये हैं। भारत के नाट्य मंचन स्थान गुफा जैसी बंद जगहों पर निर्मित किये गये जबकि पाश्चात्य देशों में नाटक खेलने हेतु खुले स्थानों को वरीयता दी गयी जहां दर्शकों के बैठने हेतु सीढ़ीदार गोल चबूतरे बनाये जाते रहे हैं। उसी आधार पर अब भारत में भी मुक्ताकाशी मंच बनाये जाने लगे हैं।

इन पंक्तियों के लेखक को 2018 में भारत के प्राचीन नाट्य स्थल रामगढ़ को देखने का अवसर मिला था। अंबिकापुर जिले में स्थित यह स्थान रामगढ़ नामक पहाड़ी पर कालिदास द्वारा निर्मित किया गया है। पास ही विशाल हाथी गुफा भी है। रामगढ़ नाट्य मंच में सामने दर्शकों के बैठने हेतु विस्तृत शिला हैं। मंचन हेतु पहाड़ को काटकर एक मंच तैयार किया गया है जो लगभग 6 फीट ऊंचा है। मंच के बाईं और पात्रों की साज–सज्जा और पर्दा खींचने वाले के लिए जगह बनी है तो दायीं ओर नाटक के निर्देशक और नाटक से सम्बंधित कुछ अन्य व्यक्तियों तथा लेखक आदि के बैठने के लिए स्थान नियत है। यह गुफा प्राकृतिक नहीं मानव निर्मित है, ऐसा वहां देखने पर समझ में आता है। अब प्रत्येक वर्ष वहां कालिदास समारोह में तमाम नाट्य प्रस्तुतियों की पुष्पांजलि देकर महान नाटककार कालिदास के योगदान के प्रति श्रद्धा प्रकट की जाती है। संस्कृत में बहुत सारे नाटक केवल मंचन की दृष्टि से ही लिखे गये। अभिज्ञान शाकुन्तलम्, वेणीसंहार, मृच्छकटिकम्, स्वप्नवासवदत्तम्, उत्तररामचरितम्, मालविकाग्निमित्रम्, विक्रमोर्वशीयम, प्रतिमानाटकम और उरुभंग श्रेष्ठ नाटकों में गण्य हैं। दशरूपक और साहित्य दर्पण ग्रंथों में भी नाट्य विधा का सम्यक विवेचन दृष्टव्य है। हिंदी में नाटक भले ही गद्य की श्रेणी में शामिल है पर संस्कृत भाषा में नाटक को दृश्य काव्य के अंतर्गत रखा गया है। नाटक रस प्रधान होता है। काव्यात्मक सौंदर्य की विलक्षण रसपूर्ण सृष्टि की रचना ही नाटक का ध्येय है। काव्येषु नाटकम् रम्यम् कह कर नाटक के सौंदर्य का रेखांकन किया गया है। बौद्ध ग्रंथों में भी नाट्य परंपरा का उल्लेख मिलता है।

भारत में मुस्लिम आक्रांताओं के कारण नाटक मंचन एवं लेखन को विराम लग गया। पर कालांतर में 18वीं शताब्दी में नाटक खेलने के उदाहरण मिलते हैं। संस्कृत की नाट्य धारा से प्रेरित होकर हिंदी में भी सुंदर मनोहरी आनंद प्रधान नाटकों की रचना हुई है जिसका श्रेय भारतेंदु हरिश्चंद्र को दिया जाता है। नाटक लेखन एवं मंचन को बढ़ावा देने में पारसी थियेटर की भूमिका की अनदेखी नहीं की जा सकती है। वर्ष 1871 में स्थापित अल्फ्रेड नाटक मंडली को सही मायने में नाटकों के मंचन और जनसामान्य तक उसकी पहुंच एवं प्रसिद्धि दिलाने का श्रेय जाता है। इस मंडली द्वारा भारतेंदु हरिश्चंद्र और राधा कृष्ण दास के कई नाटकों का मंचन किया गया जिन्हें पर्याप्त सराहना मिली। अन्य नाटक मंडली और थिएटर की बात करूं तो मॉडर्न थिएटर कोलकाता, बलिया नाट्य समाज, बनारस थियेटर, आर्य नाट्य सभा प्रयाग और भारतीय कला मंदिर कानपुर का उल्लेख करना आवश्यक हो जाता है। वर्ष 1884 में नेशनल थियेटर कंपनी ने भारतेंदु के नाटक अंधेर नगरी का सर्वप्रथम मंचन किया था। अन्य नाटकों में सत्य हरिश्चंद्र चंद्रगुप्त, नीलदेव, स्कंद गुप्त, सुभद्रा हरण एवं ध्रुवस्वामिनी आदि का अंकन उचित होगा। ध्यातव्य है कि तत्कालीन नाटकों में स्त्री पात्रों का अभिनय भी पुरुष पात्रों द्वारा ही किया जाता था जिसे विराम दिया 1939 में काशी हिंदू विश्वविद्यालय में स्थापित विक्रम परिषद ने। पहली बार उसके द्वारा स्त्री पात्रों का अभिनय स्त्रियों के द्वारा ही कराने की पहल की गई जिसे अन्य मंडलियों ने भी स्वीकार कर आगे बढ़ाया। इस प्रवाह में लोकभाषा बोली में भी नाटकों की एक वेगवती धारा शामिल थी। नौटंकी, जात्रा, तमाशा, ख्याल, नाच, बिदेसिया, यक्षगान, स्वांग, रासलीला और रामलीला आदि से लोकजीवन आनंदित हैं। वास्तव में नाट्य मंचन में संवाद संप्रेषण, भावाभिव्यंजना और रसास्वादन साथ–साथ चलते हैं। यहां सिनेमा की भांति रिटेक के लिए कोई जगह और अवसर नहीं होता। पात्र का सीधा संबंध दर्शकों से होता है। आज एक कला प्रेमी नागरिक के रूप में हमें यह संकल्प लेना आवश्यक है कि हम रंगमंच के महत्व को समझ उसकी वापसी हेतु संकल्पबद्ध हों। स्कूली स्तर पर भी रंगमंच को पाठ्यक्रम में शामिल कर सार्थक पहल सम्भव है। **प्रमोद दीक्षित मलय**

'पटना मरीन ड्राइव' बदलते बिहार की सुखद तस्वीर, देशभर से देखने आ रहें हैं लोगः सम्राट चौधरी

पटना, फोकस न्यूज, बिहार के उपमुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने बृहस्पतिवार को कहा कि पटना में बने 'मरीन ड्राइव' (जेपी गंगा पथ) को देखने के लिए देशभर से लोग आ रहे हैं और यह बदलते बिहार की सुखद तस्वीर है। उन्होंने कहा कि दीघा से कोइलवर और मुंगेर से भागलपुर तक लगभग 125 किलोमीटर लंबा 'मरीन ड्राइव' बनाने का काम तेजी से चल रहा है तथा इसके पूरा होने के बाद पर्यटन और रोजगार को नया आयाम मिलेगा। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की 'समृद्धि यात्रा' के समापन अवसर पर यहां बापू सभागार में एक सभा को संबोधित करते हुए चौधरी ने कहा कि न्याय यात्रा, परिवर्तन यात्रा, विकास यात्रा, प्रगति यात्रा और अब समृद्धि यात्रा के माध्यम से राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन (राजग) सरकार ने बिहार में विकास की मजबूत नींव रखी है। उन्होंने कहा कि आज सम्राट अशोक की जयंती है जिन्होंने भारत को स्वर्णिम काल दिया और अखंड भारत की कल्पना को साकार किया। उन्होंने कहा कि बिहार सरकार ने सम्राट अशोक की विरासत को सम्मान देने के लिए बापू सभागार, ज्ञान भवन और सभ्यता द्वार को सम्राट अशोक कन्वेंशन सेंटर का नाम दिया है। चौधरी ने कहा कि ये केवल भवन नहीं, बल्कि बिहार के गौरव के प्रतीक हैं। उपमुख्यमंत्री ने कहा कि 2005 से पहले बिहार में सड़क, बिजली, स्वास्थ्य और शिक्षा जैसी बुनियादी सुविधाओं का घोर अभाव था, उस समय राज्य में केवल छह हजार किलोमीटर सड़कें थीं, जो अब बढ़कर करीब एक लाख 40 हजार किलोमीटर हो चुकी हैं। उन्होंने बिजली के क्षेत्र में भी बड़ा सुधार होने का दावा करते हुए कहा कि पहले जहां केवल 17 लाख उपभोक्ता थे, अब उनकी संख्या बढ़कर दो करोड़ 16 लाख हो गई है और 23 से 24 घंटे बिजली की आपूर्ति हो रही है। उन्होंने कहा कि 125 यूनिट तक मुफ्त बिजली देने की योजना से लगभग 88 प्रतिशत परिवारों का बिजली बिल शून्य आ रहा है। उन्होंने कहा कि महिलाओं के सशक्तीकरण के लिए साइकिल, पोशाक और छात्रवृत्ति जैसी योजनाएं चलाई जा रही हैं। उन्होंने कहा कि पंचायत चुनाव में 50 प्रतिशत आरक्षण दिया गया है और एक करोड़ 81 लाख महिलाओं के खातों में 10 हजार रुपये भेजकर उन्हें आत्मनिर्भर बनाया गया है। उन्होंने कहा कि आज जीविका समूहों से जुड़ी महिलाएं एक लाख 21 हजार करोड़ रुपये का कारोबार कर रही हैं। उपमुख्यमंत्री ने कहा कि राज्य में पलायन रोकने के लिए उद्योगों को बढ़ावा दिया जा रहा है तथा पिछले पांच वर्षों में 50 लाख से अधिक लोगों को नौकरी और रोजगार दिया गया है और आने वाले पांच वर्षों में एक करोड़ रोजगार सृजन का लक्ष्य है। उन्होंने कहा कि 'फोरलेन', 'सिक्स लेन' और एक्सप्रेस–वे के निर्माण के बाद अब सरकार हवाई कनेक्टिविटी को मजबूत करने के लिए काम कर रही है तथा पटना, गया, दरभंगा और पूर्णिया में हवाई अड्डों के विकास के बाद राज्य के अन्य हिस्सों में भी हवाई सेवाओं के विस्तार की दिशा में काम हो रहा है। उन्होंने कहा कि बिहटा, सोनपुर, भागलपुर, मुजफ्फरपुर, मुंगेर, सुल्तानगंज, बीरपुर, वाल्मीकिनगर और रक्सौल में भी हवाई अड्डों के निर्माण की दिशा में लगातार प्रयास किए जा रहे हैं।

मध्यप्रदेश के पन्ना और धार में किया गया ट्रेनों का परीक्षण परिचालन

पन्ना/धार (मध्यप्रदेश), (भाषा) रेलवे ने पूर्ण सेवा शुरू होने से पहले मध्यप्रदेश के पन्ना और धार को जोड़ने वाले रेल मार्ग पर ट्रेनों का परीक्षण परिचालन किया। अधिकारियों ने बृहस्पतिवार को यह जानकारी दी। उन्होंने कहा कि सोमवार को धार में और मंगलवार को पन्ना में आयोजित परीक्षण परिचालन से क्षेत्र में एक खुशी की लहर दौड़ गई, लोगों ने इस दौरान मार्ग पर कतार में खड़े होकर और तालियां बजाकर ट्रेनों का स्वागत किया तथा स्टेशनों पर पहुंचने के साथ ही इंजन पर फूल बरसाकर अपनी खुशी का इजहार किया। पन्ना जिले के नागौद और फुलवारी के बीच परीक्षण परिचालन रेलवे सुरक्षा आयुक्त की उपस्थिति में आयोजित किया गया। अधिकारी ने कहा कि 74 किलोमीटर लंबी सतना–पन्ना रेलवे लाइन पन्ना के लिए 'गेम चेंजर' साबित होगी। उन्होंने कहा कि यह महत्वाकांक्षी ललितपुर–सिंगरौली लाइन का हिस्सा है, जो व्यापार, पर्यटन और स्थानीय आर्थिक गतिविधियों को बढ़ावा देगी। पश्चिम मध्य रेलवे (डब्ल्यूसीआर) के मुख्य जनसंपर्क अधिकारी हर्षित श्रीवास्तव ने कहा कि परीक्षण के बारे में रेलवे सुरक्षा आयुक्त की रिपोर्ट आने की उम्मीद है। डब्ल्यूसीआर के कार्यकारी अभियंता पी के सिंह ने 'पीटीआई–भाषा' को बताया कि परीक्षण डीजल इंजन से किया गया लेकिन भविष्य में ट्रैक का विद्युतीकरण किया जाएगा। धार में भी इसी तरह के खुशी के नजारे देखने को मिले। केंद्रीय मंत्री सावित्री ठाकुर, पूर्व केंद्रीय मंत्री विक्रम वर्मा, धार विधायक नीना वर्मा और भाजपा नेता महंत नीलेश भारती ने पीथमपुर से धार तक ट्रेन के इंजन से यात्रा की। इस दौरान भाजपा कार्यकर्ताओं ने उनका जोरदार स्वागत किया। ठाकुर ने पत्रकारों से कहा, ''धार जिले में लंबे समय से चली आ रही मांग अब पूरी हो जाएगी। आज लोगों के सपने सच हो गए हैं। हमारे आदिवासी क्षेत्र में यह पहली ट्रेन है।'' रेल लाओ महा समिति के अध्यक्ष पवन जैन गंगवाल ने ट्रेन के इंजन का फूलों से स्वागत किया और आतिशबाजी भी की। उन्होंने कहा कि लोग खुशी से झूम रहे हैं। एक अधिकारी ने बताया कि 2008 में मंजूर इंदौर–दाहोद रेल परियोजना तेजी से आगे बढ़ रही है और पीथमपुर–धार का परीक्षण परिचालन इस महत्वपूर्ण कार्य का हिस्सा था। उन्होंने बताया कि पीथमपुर से सागर होते हुए 38 किलोमीटर दूर धार तक रेलवे का इंजन पहुंचा। हालांकि, लोगों ने कहा कि इस क्षेत्र के लिए अधिक लाभ के लिए मार्ग को अंततः मुंबई से जोड़ा जाना चाहिए।

भाजपा के सत्ता में लौटने पर पांच लाख बीघा भूमि को अतिक्रमण से मुक्त कराया जाएगा : हिमंत शर्मा

पाठशाला (असम), (भाषा) असम के मुख्यमंत्री हिमंत विश्व शर्मा ने बृहस्पतिवार को कहा कि अगर भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) की सरकार नौ अप्रैल को होने वाले विधानसभा चुनावों के बाद सत्ता में वापस आती है, तो वह पांच लाख बीघा जमीन से अतिक्रमणकारियों को हटा देगी। बजाली विधानसभा क्षेत्र में एक चुनावी रैली को संबोधित करते हुए शर्मा ने कहा कि अतिक्रमणकारियों को पिछले पांच वर्षों में सबक सिखाया गया है और स्वदेशी समुदायों पर उनका प्रभुत्व 'काफी हद तक कम' हो गया है। उन्होंने इन अतिक्रमकारियों में से अधिकांश को 'मिया' (बांग्ला भाषी प्रवासी मुस्लिमों के लिए अपमानजनक माने जाने वाला शब्द) बताया। उन्होंने कहा, ''पिछले पांच वर्षों में हमने 1.5 लाख बीघा जमीन को अतिक्रमण मुक्त कराया है, लेकिन अगले पांच वर्षों के लिए हमारा लक्ष्य पांच लाख बीघा सरकारी जमीन को अतिक्रमण मुक्त कराना होगा।'' शर्मा ने कहा कि असम में भूमि पर केवल स्वदेशी लोगों का ही अधिकार होगा। उन्होंने कहा, ''भाजपा 'जाति, माटी और भेटी' (लोग, भूमि और आधार) की रक्षा के लिए प्रतिबद्ध है और हम किसी को भी इसके विरुद्ध काम नहीं करने देंगे। मूल आबादी के अस्तित्व के लिए अवैध प्रवासियों से सख्ती से निपटना आवश्यक है और हम इस पर कोई समझौता नहीं करेंगे।'' कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष गौरव गोगोई पर हमला करते हुए शर्मा ने कहा कि नए ग्रेटर असम की उनकी अवधारणा अस्वीकार्य है क्योंकि वह (गोगोई) अप्रत्यक्ष रूप से यह सुझाव दे रहे हैं कि बांग्लादेशियों और राज्य के लोगों को एक साथ रहना होगा। शर्मा ने आरोप लगाया कि गोगोई और कांग्रेस ने हमेशा मूल असमिया लोगों की तुलना में 'मिया' समुदाय को अधिक महत्व देने की कोशिश की है। उन्होंने मतदाताओं से असम गण परिषद (अगप) के धर्मेश्वर रॉय का समर्थन करने का आग्रह किया और भाजपा के साथ पार्टी के गठबंधन को अविभाज्य बताया। उन्होंने पड़ोसी बारपेटा निर्वाचन क्षेत्र में अगप उम्मीदवार दीपक कुमार दास के लिए भी प्रचार किया, जहां कांग्रेस उम्मीदवार महानंदा सरकार का नामांकन खारिज कर दिया गया। असम में 126 सदस्यीय विधानसभा के लिए चुनाव नौ अप्रैल को होंगे और मतगणना चार मई को होगी।

अन्नामलाई को तमिलनाडु चुनाव लड़ना चाहिए : भाजपा नेता वानति श्रीनिवासन

चेन्नई, (भाषा) भाजपा महिला मोर्चा की अध्यक्ष वानति श्रीनिवासन ने कहा कि पार्टी नेता के. अन्नामलाई को तमिलनाडु विधानसभा चुनाव लड़ना चाहिए और पार्टी विधायक के रूप में सदन में जाना चाहिए। अन्नामलाई को 2021 के चुनाव में अरवाकुरिची निर्वाचन क्षेत्र से हार का सामना करना पड़ा था। भाजपा की तमिलनाडु इकाई के पूर्व अध्यक्ष अन्नामलाई ने हाल ही में कहा था कि वह 2026 का चुनाव लड़ने के इच्छुक नहीं हैं और इसके बजाय चुनाव संबंधी कार्यों में पार्टी पदाधिकारी के रूप में अपने कर्तव्यों का निर्वहन करेंगे। पिछले महीने, अन्नामलाई ने अपने पिता के स्वास्थ्य का हवाला देते हुए छह विधानसभा क्षेत्रों के चुनाव प्रभारी की अपनी जिम्मेदारी छोड़ने की बात कही थी।

हजारों 'फ्रेंड्स' के बावजूद इंसान अकेलाः एआई–मित्रता की दुनिया में मानवीय संबंध का भविष्य

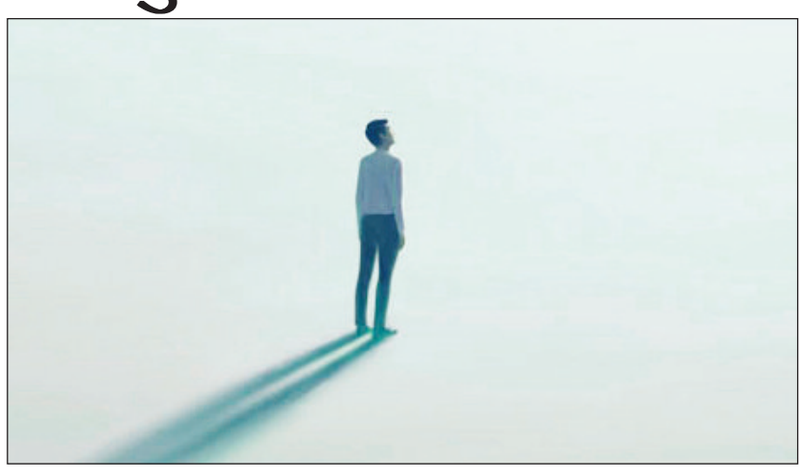

इक्कीसवीं सदी के इस तीव्रगामी, तकनीक– चालित युग में मनुष्य ने संवाद के ऐसे साधन विकसित कर लिए हैं, जिनकी कल्पना भी पूर्ववर्ती पीढ़ियाँ नहीं कर सकती थीं। एक क्लिक में महाद्वीपों की दूरी सिमट जाती है, एक संदेश में सैकड़ों लोगों तक विचार पहुँच जाता है, और एक प्रोफाइल में व्यक्ति की पूरी सामाजिक उपस्थिति दर्ज हो जाती है। फिर भी, इस समूचे संचार–सामर्थ्य के बीच एक गहरी विडंबना जन्म ले चुकी हैकृमनुष्य जितना अधिक 'जुड़ा' है, उतना ही अधिक 'अकेला' भी। यह विरोधाभास केवल भावनात्मक अनुभव नहीं, बल्कि एक गंभीर सामाजिक और मनोवैज्ञानिक संकट के रूप में उभर रहा है, जिसे आज "डिजिटल अकेलापन" कहा जा रहा है। यह अकेलापन केवल उन लोगों तक सीमित नहीं है, जिनके पास मित्र या परिवार नहीं हैं, बल्कि यह उन लोगों में भी दिखाई देता है, जिनके पास हजारों आभासी संबंध हैं। सामाजिक माध्यमों पर सक्रियता, निरंतर ऑनलाइन उपस्थिति और सतत संचार के बावजूद व्यक्ति अपने भीतर एक रिक्तता, एक अनकही पीड़ा और एक अव्यक्त अलगाव का अनुभव करता है। इसी रिक्तता को भरने के लिए एआई आधारित संवाद प्लेटफॉर्म सामने आए हैं, जिन्होंने मनुष्य को एक ऐसा 'सुनने वाला साथी' प्रदान किया है, जो हर समय उपलब्ध है, जो कभी थकता नहीं, और जो बिना किसी निर्णय के केवल सुनता और उत्तर देता है। विश्व स्वास्थ्य संगठन ने वर्ष 2023 में अकेलेपन को वैश्विक सार्वजनिक स्वास्थ्य की प्राथमिकता घोषित किया, जो इस समस्या की व्यापकता और गंभीरता को दर्शाता है। इसी क्रम में अमेरिका के सर्जन जनरल द्वारा अकेलेपन को "महामारी" की संज्ञा दी गई और यह बताया गया कि इसका प्रभाव स्वास्थ्य पर उतना ही घातक हो सकता है जितना धूम्रपान का। सिग्ना की 2024 की वैश्विक रिपोर्ट के अनुसार लगभग 58 प्रतिशत वयस्क किसी न किसी स्तर पर अकेलेपन का अनुभव करते हैं। यह आँकड़ा केवल एक संख्या नहीं, बल्कि आधुनिक समाज की संरचना में आई उस दरार का संकेत है, जो धीरे–धीरे गहरी होती जा रही है।

सबसे अधिक चिंता का विषय यह है कि यह संकट युवाओं में अधिक गहरा है। 18 से 24 वर्ष की आयु वर्ग, जो तकनीकी रूप से सबसे अधिक सक्रिय है, वही सबसे अधिक अकेलापन महसूस करता है। यह वह पीढ़ी है, जो 'लाइक्स' और 'फॉलोअर्स' के माध्यम से अपने अस्तित्व को मापती है, लेकिन वास्तविक संबंधों की गहराई से वंचित रह जाती है। यह स्थिति इस बात का प्रमाण है कि डिजिटल जुड़ाव और भावनात्मक जुड़ाव एक ही बात नहीं हैं। भारत में यह समस्या धीरे–धीरे उभर रही है। पारंपरिक रूप से भारतीय समाज परिवार और समुदाय पर आधारित रहा है, जहाँ संयुक्त परिवार, पड़ोस और सामाजिक संबंध व्यक्ति को भावनात्मक सुरक्षा प्रदान करते थे। लेकिन तीव्र शहरीकरण, रोजगार के लिए प्रवास और एकल परिवारों के बढ़ते चलन ने इस सामाजिक संरचना को कमजोर किया है। स्वास्थ्य मंत्रालय की 2024 की मानसिक स्वास्थ्य रिपोर्ट के अनुसार भारत में लगभग 150 मिलियन लोगों को मानसिक स्वास्थ्य सहायता की आवश्यकता है, लेकिन केवल लगभग 20 प्रतिशत लोगों तक ही यह सहायता पहुँच पाती है।

विशेष रूप से महानगरों में रहने वाले युवा पेशेवर, जो अपने परिवारों से दूर रहते हैं, इस संकट के सबसे बड़े शिकार बन रहे हैं। बंगलुरु स्थित राष्ट्रीय मानसिक स्वास्थ्य संस्थान के एक अध्ययन में पाया गया कि आईटी क्षेत्र में कार्यरत लगभग 40 प्रतिशत कर्मचारियों में सामाजिक अलगाव के लक्षण दिखाई देते हैं। यह वही वर्ग है, जो तकनीक के सबसे अधिक संपर्क में है और इसलिए एआई आधारित संवाद प्लेटफॉर्म का सबसे अधिक उपयोग करता है। एआई आधारित संवाद प्लेटफॉर्म, जैसे कि वर्चुअल चौटबॉट और डिजिटल सहायक, इस अकेलेपन को कम करने के एक साधन के रूप में उभरे हैं। इन प्लेटफॉर्मों की विशेषता यह है कि वे व्यक्ति को एक सुरक्षित, निजी और बिना निर्णय वाला वातावरण प्रदान करते हैं, जहाँ वह अपने विचार, भावनाएँ और अनुभव साझा कर सकता है। कई लोग इन प्लेटफॉर्मों को अपना 'मित्र' या 'सहचर' मानने लगे हैं, और उनके साथ गहरे भावनात्मक संबंध विकसित कर रहे हैं। इन प्लेटफॉर्मों के सकारात्मक पहलुओं को नकारा नहीं जा सकता। सामाजिक चिंता से ग्रस्त व्यक्ति, जो वास्तविक जीवन में संवाद करने में असहज महसूस करते हैं, उनके लिए यह एक प्रारंभिक अभ्यास का माध्यम बन सकता है। मानसिक स्वास्थ्य सहायता की कमी वाले क्षेत्रों में यह एक अस्थायी सहारा प्रदान कर सकता है। इसके अतिरिक्त, यह उन लोगों के लिए भी उपयोगी हो सकता है, जो अत्यधिक अकेलेपन की स्थिति में हैं और किसी से संवाद करने का कोई अन्य माध्यम नहीं रखते। लेकिन इन सकारात्मक पहलुओं के साथ कुछ गंभीर चिंताएँ भी जुड़ी हुई हैं। सबसे पहली चिंता हैकृवास्तविक संबंधों का प्रतिस्थापन। जब व्यक्ति एआई के साथ अधिक समय बिताने लगता है, तो वह वास्तविक मनुष्यों के साथ संवाद करने में असहज महसूस करने लगता है। एक अंतरराष्ट्रीय शोध में यह पाया गया कि जो लोग एआई आधारित संवाद पर अत्यधिक निर्भर हो जाते हैं, उनकी सामाजिक कौशल क्षमता में कमी आती है और वे वास्तविक संबंधों में तनाव अनुभव करते हैं। मनोविज्ञान के दृष्टिकोण से देखें तो मनुष्य को 'सुरक्षित संबंध' की आवश्यकता होती है, जिसमें पारस्परिकता, संवेदना और वास्तविकता होती है। एआई संवाद में यह तत्व अनुपस्थित होते हैं। एआई कभी थकता नहीं, कभी असहमति नहीं जताता और कभी संबंध में जटिलता नहीं लाता। यह एक 'आदर्श साथी' का भ्रम उत्पन्न करता है, जो वास्तविक जीवन में संभव नहीं है। परिणामस्वरूप व्यक्ति वास्तविक संबंधों की जटिलताओं को स्वीकार करने की क्षमता खो सकता है। इसके अतिरिक्त, एआई संवाद एक प्रकार के 'एकतरफा संबंध' का निर्माण करता है, जिसमें उपयोगकर्ता अपनी भावनाएँ व्यक्त करता है, लेकिन सामने वाला कोई वास्तविक अनुभव नहीं रखता। यह संबंध सतही संतुष्टि प्रदान करता है, लेकिन गहराई से व्यक्ति को और अधिक अकेला बना सकता है। नैतिक दृष्टि से भी यह विषय अत्यंत संवेदनशील है। जब उपयोगकर्ता अपने व्यक्तिगत और गहरे भावनात्मक अनुभव इन प्लेटफॉर्मों के साथ साझा करते हैं, तो यह डेटा कंपनियों के पास संग्रहीत होता है। यह प्रश्न उठता है कि इस डेटा का उपयोग कैसे किया जाएगा, और क्या यह उपयोगकर्ता की गोपनीयता का उल्लंघन नहीं है। इसके अतिरिक्त, एआई को इस प्रकार डिजाइन किया जाता है कि वह उपयोगकर्ता को संतुष्ट रखे। इसका अर्थ है कि वह उपयोगकर्ता के विचारों का विरोध नहीं करेगा, बल्कि उनसे सहमत होगा। यह स्थिति एक 'प्रतिध्वनि कक्ष' का निर्माण करती है, जहाँ व्यक्ति केवल अपने ही विचारों की पुष्टि सुनता है, जिससे उसके विचारों का विकास रुक सकता है।

इस समस्या के समाधान के लिए बहुआयामी दृष्टिकोण आवश्यक है। सबसे पहले, समाज में डिजिटल साक्षरता को बढ़ावा देना होगा, ताकि लोग यह समझ सकें कि आभासी और वास्तविक संबंधों में क्या अंतर है। शिक्षा प्रणाली में इस विषय को शामिल करना आवश्यक है, ताकि युवा पीढ़ी तकनीक का संतुलित उपयोग कर सके। सरकार को भी इस दिशा में सक्रिय भूमिका निभानी होगी। एआई आधारित संवाद प्लेटफॉर्मों के लिए स्पष्ट दिशा–निर्देश और मानक निर्धारित किए जाने चाहिए, ताकि उपयोगकर्ताओं की सुरक्षा और गोपनीयता सुनिश्चित की जा सके। मानसिक स्वास्थ्य सेवाओं की उपलब्धता बढ़ाना भी अत्यंत आवश्यक है, ताकि लोग वास्तविक सहायता प्राप्त कर सकें। अंततः यह समझना आवश्यक है कि एआई संवाद एक साधन है, समाधान नहीं। यह अकेलेपन को अस्थायी रूप से कम कर सकता है, लेकिन उसका स्थायी समाधान नहीं है। वास्तविक समाधान हैकृमानवीय संबंध, समुदाय और संवाद। मनुष्य एक सामाजिक प्राणी है, जिसकी आत्मा को उस ऊष्मा की आवश्यकता होती है, जो केवल किसी अन्य मनुष्य की उपस्थिति से मिलती है। वह उपस्थिति केवल शब्दों में नहीं, बल्कि दृष्टि, स्पर्श और अनुभव में होती है। इसलिए, इस डिजिटल युग में सबसे बड़ी चुनौती यह नहीं है कि हम तकनीक का उपयोग कैसे करें, बल्कि यह है कि हम अपने मानवीय संबंधों को कैसे सुरक्षित रखें। यदि हम इस संतुलन को बनाए रखने में सफल होते हैं, तो तकनीक हमारे जीवन को समृद्ध करेगीय अन्यथा, यह हमें और अधिक अकेला बना सकती है। अंत में यही कहा जा सकता है कि डिजिटल संवाद की दुनिया में वास्तविक संबंधों की आवश्यकता और भी बढ़ जाती है। तकनीक हमारी यात्रा को आसान बना सकती है, लेकिन मंजिल तक पहुँचाने का कार्य केवल मानव ही कर सकता है। यही इस युग की सबसे बड़ी सच्चाई है, और यही उसका सबसे बड़ा सबक भी। **डॉ. शैलेश शुक्ला**

संपादकीय

मां सिद्धिदात्री की कृपाः आस्था, साधना और सिद्धि का अंतिम शिखर

नवरात्रि का नवम दिवस केवल एक धार्मिक अनुष्ठान भर नहीं, बल्कि साधना की पराकाष्ठा और आध्यात्मिक उन्नति का वह दिव्य क्षण है, जब भक्त और शक्ति के बीच की दूरी लगभग समाप्त हो जाती है। यह दिन मां सिद्धिदात्री को समर्पित है, जो नवदुर्गा का नवम स्वरूप मानी जाती हैं और समस्त सिद्धियों की दात्री हैं। भारतीय आध्यात्मिक परंपरा में सिद्धि केवल चमत्कारिक शक्तियों का प्रतीक नहीं, बल्कि आत्म–विकास, आत्म–नियंत्रण और परम चेतना से जुड़ने का माध्यम भी है। मां सिद्धिदात्री की आराधना व्यक्ति को इसी उच्चतम अवस्था तक पहुंचाने का मार्ग प्रशस्त करती है। मां सिद्धिदात्री का स्वरूप अत्यंत शांत, सौम्य और दिव्य है। वे कमल के आसन पर विराजमान रहती हैं और चार भुजाओं में चक्र, गदा, शंख और कमल धारण करती हैं। उनका यह रूप दर्शाता है कि शक्ति केवल उग्रता का प्रतीक नहीं, बल्कि संतुलन, ज्ञान और करुणा का भी स्वरूप है। यही कारण है कि जब साधक मां की उपासना करता है, तो उसे केवल भौतिक लाभ ही नहीं, बल्कि मानसिक शांति और आध्यात्मिक संतुलन भी प्राप्त होता है। धार्मिक ग्रंथों में वर्णित है कि मां सिद्धिदात्री की कृपा से ही भगवान शिव को अष्ट सिद्धियों की प्राप्ति हुई थी। इसी प्रभाव के कारण शिव का आधा शरीर देवी स्वरूप में परिवर्तित हो गया और वे अर्द्धनारीश्वर कहलाए। यह कथा केवल एक पौराणिक प्रसंग नहीं, बल्कि इस सत्य का प्रतीक है कि जब पुरुष और शक्ति का संतुलन स्थापित होता है, तभी पूर्णता प्राप्त होती है। मां सिद्धिदात्री की साधना इस संतुलन को स्थापित करने का माध्यम है। अष्ट सिद्धियांकृअणिमा, महिमा, गरिमा, लघिमा, प्राप्ति, प्रकाम्य, ईशित्व और वशित्वकृइनका उल्लेख सुनते ही मन में अलौकिक शक्तियों की कल्पना जागृत होती है, लेकिन इनका वास्तविक अर्थ इससे कहीं अधिक गहरा है। अणिमा का अर्थ है सूक्ष्मता, अर्थात अपने अहंकार को समाप्त कर विनम्रता को अपनाना। महिमा का अर्थ है आत्म–विशालता, अपने भीतर के गुणों का विस्तार। गरिमा स्थिरता का प्रतीक है, लघिमा हल्केपन और मानसिक बोझ से मुक्ति का संकेत देती है। प्राप्ति और प्रकाम्य इच्छाओं की पूर्ति से जुड़ी हैं, लेकिन यह पूर्ति तभी सार्थक होती है जब वह धर्म और नैतिकता के मार्ग पर आधारित हो। ईशित्व और वशित्व आत्म–नियंत्रण और नेतृत्व की उच्चतम अवस्था को दर्शाते हैं। इस प्रकार, मां सिद्धिदात्री की उपासना केवल बाहरी सिद्धियों की प्राप्ति नहीं, बल्कि आंतरिक परिपक्वता का भी मार्ग है। मां सिद्धिदात्री को प्रसन्न करने के लिए भक्ति में शुद्धता और निष्ठा का होना अत्यंत आवश्यक है। पूजा की विधि जितनी महत्वपूर्ण है, उससे कहीं अधिक महत्वपूर्ण है भावना की पवित्रता। प्रातःकाल ब्रह्म मुहूर्त में उठकर स्नान करना, स्वच्छ वस्त्र धारण करना और पूजा स्थल को शुद्ध करना, यह सब केवल बाहरी प्रक्रियाएं नहीं हैं, बल्कि यह मन को भी पवित्र और एकाग्र करने का साधन हैं। जब साधक मां की प्रतिमा या चित्र के सामने बैठता है और धूप–दीप प्रज्वलित करता है, तो वह अपने भीतर के अज्ञान के अंधकार को दूर करने का संकल्प भी लेता है।

मंत्र जाप मां सिद्धिदात्री की आराधना का अत्यंत प्रभावी माध्यम है। जब साधक "या देवी सर्वभूतेषु सिद्धिदात्री रूपेण संस्थिता" जैसे मंत्रों का उच्चारण करता है, तो वह अपने भीतर छिपी दिव्यता को जागृत करता है। मंत्रों की ध्वनि केवल शब्द नहीं होती, बल्कि वह ऊर्जा का स्रोत होती है, जो साधक के मन और आत्मा को एक विशेष कंपन से जोड़ती है। यही कंपन धीरे–धीरे साधक को उस अवस्था तक ले जाता है, जहां उसे आत्मिक शांति और संतोष की अनुभूति होती है। भोग अर्पित करने की परंपरा भी केवल एक रस्म नहीं है। जब भक्त हलवा, पूरी, चना और खीर जैसे व्यंजन मां को अर्पित करता है, तो वह अपने श्रम और समर्पण का प्रतीक प्रस्तुत करता है। यह प्रक्रिया हमें सिखाती है कि जीवन में जो कुछ भी हमें प्राप्त हुआ है, वह ईश्वर की कृपा का परिणाम है और उसे साझा करना ही सच्ची भक्ति है। महानवमी के दिन कन्या पूजन का विशेष महत्व है। नौ कन्याओं को नवदुर्गा का स्वरूप मानकर उनकी पूजा करना, उनके चरण धोना, उन्हें भोजन कराना और उपहार देनाकृ यह सब केवल परंपरा नहीं, बल्कि नारी शक्ति के प्रति सम्मान का प्रतीक है। यह अनुष्ठान हमें यह संदेश देता है कि शक्ति का वास्तविक रूप हमारे आसपास ही विद्यमान है और उसका सम्मान करना ही सच्ची साधना है। मां सिद्धिदात्री की कृपा प्राप्त करने के लिए केवल एक दिन की पूजा पर्याप्त नहीं होती, बल्कि इसके लिए निरंतर साधना और आत्म–अनुशासन आवश्यक है। जीवन में सकारात्मकता बनाए रखना, दूसरों के प्रति करुणा और सहानुभूति रखना, सत्य और धर्म के मार्ग पर चलनाकृये सभी गुण मां की कृपा प्राप्त करने के लिए आवश्यक हैं। जब व्यक्ति अपने विचारों और कर्मों में शुद्धता लाता है, तभी वह वास्तविक सिद्धियों के योग्य बनता है। आधुनिक जीवन की भागदौड़ में जहां तनाव, असंतुलन और असंतोष बढ़ता जा रहा है, वहां मां सिद्धिदात्री की उपासना एक प्रकाश स्तंभ की तरह है, जो हमें सही दिशा दिखाती है। यह हमें सिखाती है कि वास्तविक शक्ति बाहरी संसाधनों में नहीं, बल्कि हमारे भीतर की चेतना में निहित है। जब हम अपने भीतर की इस शक्ति को पहचान लेते हैं, तो जीवन की हर चुनौती का सामना सहजता से कर सकते हैं। मां सिद्धिदात्री की आराधना हमें यह भी सिखाती है कि सिद्धि केवल प्राप्त करने की वस्तु नहीं, बल्कि उसे सही दिशा में उपयोग करने की जिम्मेदारी भी है। यदि शक्ति का उपयोग केवल स्वार्थ के लिए किया जाए, तो वह विनाश का कारण बन सकती है, लेकिन यदि उसका उपयोग समाज और मानवता के कल्याण के लिए किया जाए, तो वह सृजन का माध्यम बन जाती है। यही मां का वास्तविक संदेश है। अंततः, महानवमी का यह पावन अवसर हमें अपने भीतर झांकने और अपने जीवन को एक नई दिशा देने का अवसर प्रदान करता है। मां सिद्धिदात्री की कृपा से हम न केवल अपनी इच्छाओं को पूर्ण कर सकते हैं, बल्कि एक संतुलित, सफल और सार्थक जीवन भी जी सकते हैं। जब भक्ति में सच्चाई, साधना में निरंतरता और कर्म में पवित्रता होती है, तब मां की कृपा अवश्य प्राप्त होती है और जीवन में अष्ट सिद्धियों का प्रकाश स्वयं प्रकट होने लगता है। यही इस पावन दिवस का वास्तविक सार और संदेश है।

जय माता दी।

कृष्णा अग्रवाल
focusnews9@gmail.com

राजाओं को राजनीति सिखाने के लिए अवतरित हुए थे प्रभु श्रीराम

दुनिया में ईश्वर के बहुत से अवतार हुए, वैष्णव परम्परा में अभी तक तेईस अवतार हो चुके हैं लेकिन सिर्फ श्रीराम को ही राजा राम कहा गया और आज भी उन्हें एक आदर्श राजा माना जाता है और किसी भी अच्छी राज व्यवस्था को रामराज कहा जाता है। असल में श्रीराम का अवतार ही राजाओं को राजनीति सिखाने के लिए हुआ था । एक आदर्श राजा कैसा होता है या राजा कैसा होना चाहिए यह श्री राम ने ही बताया अपने विचारों से भी और जीवन से भी। श्री राम ने अपने जीवन काल में आम इंसान के अपराध को भले ही क्षमा कर भी दिया हो लेकिन उन्होंने राजाओं के अपराध को कभी क्षमा नहीं किया। वे राजा और राजपरिवार के महत्व को बहुत अच्छे से जानते थे इसलिए राजा और राजपरिवार को मर्यादा और गरिमा बनाए रखने की शिक्षा देते रहे। इस क्रम में वे स्वयं अपनी पत्नी और लक्ष्मण जैसे भाई का त्याग करने से भी नहीं चूके। वे जानते थे यदि राजा और राजपरिवार नियम से नहीं चलेगा तो प्रजा भी अनुशासित नहीं रह सकेगी। इसीलिए निष्पाप होने के बाद भी उन्होंने सीता जी का त्याग किया ताकि प्रजा में स्त्रियां दूषित न हो जाएँ ,एक सबसे कमजोर और निचले तबके के अकेले व्यक्ति द्वारा जताए अविश्वास को भी उन्होंने इतनी गंभीरता से लिया जितना आज सारी जनता के आरोप को भी नेता लोग गंभीरता से नहीं लेते और भ्रष्ट होने के बाद भी अपने मंत्री या पार्टी पदाधिकारियों को पद से नहीं हटाते। आम तौर पर सीता जी के त्याग की आलोचना बहुत होती है लेकिन श्री राम के लिए प्रजा का विश्वास ज्यादा महत्वपूर्ण था, उनका मानना था कि प्रजा में एक व्यक्ति भी यदि राजा से असंतुष्ट है तो राजा को राजा के पद पर रहने का अधिकार नहीं है,इसीलिए जब उन्हें गुप्तचर सूचना देते हैं कि प्रजा सीता माता को वापस लाने पर सहमत हो गई है अतः आप उनको वापस बुला लें तब श्रीराम एक सवाल गुप्तचर से पूछते हैं कि सारी प्रजा सहमत है? तब गुप्तचर कहता है कि सिर्फ तीन चार व्यक्ति सहमत नहीं हैं तब श्रीराम कहते हैं कि यदि एक भी व्यक्ति असहमत है तो भी इसको प्रजा का समर्थन नहीं माना जा सकता,जब तक अंतिम व्यक्ति की सहमति नहीं मिल जाती तब तक महारानी सीता को वन में ही रहना होगा। इतना कठोर आदर्श किसी राजा ने कभी पालन नहीं किया लेकिन श्रीराम का काम ही राजाओं को शिक्षा देना था। श्रीराम के जीवन से पता चलता है कि प्रजा को सिर्फ दंड देकर अनुशासित करने से बेहतर है कि राजा खुद उच्च आदर्श स्थापित करें तब प्रजा ज्यादा प्रभावित होती है। चित्रकूट में भरत जी जब श्रीराम से वापस चलने का आग्रह करते हैं तब उनसे भी श्रीराम कहते हैं कि ष्तुम एक राजा होकर ऐसा सोच भी कैसे सकते हो ? यदि पिता के वचन का पालन हम ही नहीं करेंगे तो फिर हमारी प्रजा पर क्या असर पड़ेगा। चित्रकूट में ही श्रीराम भरत जी से पूछते हैं कि तुम्हारे राज्य में प्रजा संतुष्ट तो है न ? और पड़ोसी राज्यों के राजा तुमसे भयभीत रहते हैं न ? और तुम्हारे कर्मचारियों को वेतन नियमित रूप से दिया जाता है न ? उनका मत है कि राजा का प्रथम कर्तव्य है प्रजा को हर तरह से संतुष्ट रखे ताकि प्रजा विद्रोह न करे। दूसरा कर्तव्य है कि पड़ोसी राजा भयभीत रहे ताकि अनावश्यक हमला नहीं करे और कर्मचारियों को नियमित वेतन मिलता रहे ताकि वे भ्रष्टाचार और बेईमानी न करें। बालि वध के समय भी जब घायल बालि श्रीराम से कहता है कि मेरी आपसे कोई लड़ाई नहीं फिर आपने मुझे कैसे मार दिया? तब श्रीराम का जवाब है कि यह हमारा ही राज्य है भरत हमारे राजा हैं इसलिए मुझे पापी को दंड देने का पूरा अधिकार है , तुमने एक राजा होकर भी अपने भाई के साथ अन्याय किया है, उसकी पत्नी के साथ अनाचार किया है इसलिए तुम्हें राज पद पर रहने का कोई अधिकार नहीं है। राजा राम के जीवन की सबसे बड़ी विशेषता यही रही कि राजा होकर कभी भी नीति विरुद्ध बात नहीं की और ना ही किसी अन्य राजा को करने दी। उन्होंने आक्रमण भी सिर्फ उन्हीं राज्यों पर किया जहां की जनता ने अपने राजा की शिकायत श्रीराम से पास आकर की फिर चाहे किष्किंधा हो, मथुरा हो या गंधर्व देश हो ,यहां के राजा नीति विरुद्ध आचरण कर रहे थे, जनता पीड़ित थी इसलिए श्रीराम ने इन राज्यों के राजाओं को हटाकर सुग्रीव, शत्रुघ्न और भरत को राजा बनाया और सारे देश में एक संविधान लागू किया। असल में महाराज दशरथ ने जब चारों पुत्रों में कार्य विभाजन किया था तब उन्होंने भरत को वित्त विभाग, लक्ष्मण को रक्षा, शत्रुघ्न को कृषि और वाणिज्य विभाग सौंपे थे और श्रीराम को सबसे महत्पूर्ण कानून व्यवस्था का जिम्मा दिया था इसीलिए श्रीराम का जनता से सीधा संवाद था और वे कानून का बहुत सख्ती और ईमानदारी से पालन करते थे और करवाते थे। इस कारण वे जनता में बहुत लोकप्रिय हो गए। उन्होंने जनता की समस्याओं को बहुत करीब से देखा था इसलिए उन्होंने ऐसे नियम बनाए जो जन हितैषी हों फिर उसके लिए राजाओं को चाहे कितना भी कष्ट उठाना पड़े। श्रीराम ने जो नियम बनाए आगे चलकर समस्त दुनिया के संविधान उसी आधार पर बने और वही नियम आज तक कायम हैं। आज भी दुनिया में जो कर प्रणाली है वो श्रीराम की ही देन है, कृषि व्यवस्था और कानून व्यवस्था के नियम श्रीराम द्वारा ही निर्धारित किए थे जिन्हें उनके बाद भी सभी राजाओं ने अपनाया और पीढ़ी दर पीढ़ी वही नियम थोड़े ऊपर नीचे होकर लागू होते रहे। अपराधियों के साथ बहुत सख्ती से पेश आने के नियम सबसे पहले राजा राम ने ही निर्धारित किए जिनका असर आज भी मध्य एशिया के अनेक देशों में दिखाई देता है। भारत में भी सल्तनत काल से पहले मनु स्मृति के नियम ही चलते थे लेकिन बाद में खिलजी,मुगल और ब्रिटिश ने अपने नियम थोपे और आजादी के बाद भी हमारा संविधान दूसरे देशों से लिया गया । बहरहाल दुनिया और भारत के संविधानों में कितना भी बदलाव हुआ हो लेकिन उन पर राजा राम का प्रभाव कहीं ना कहीं तो रहेगा कि क्योंकि श्रीराम शाश्वत राजा हैं जैसे शेर एक नैसर्गिक राजा होता है उसी तरह श्रीराम ईश्वर के राजावतार हैं तभी उनको सारी दुनिया राजा राम कहती है स रघुपति राघव राजा राम... **मुकेश कबीर**

मोबाइल : जरूरत या जिंदगी

संचार के इस युग में सभी तीव्र गति से काम चाहते हैं । पलक झपकते ही सूचनाओं का अंबार खड़ा हो जाना, इस युग की बहुत बड़ी देन भी कहीं जा सकती है। मुख से बोलते ही जानकारी का खजाना हमारे सामने है। क्या ठीक है और क्या गलत है, इसका निर्णय अब हमें स्वयं लेना होता है। साधन साधक के रूप में कार्य करने लगे हैं, ऐसा भी कई बार लगता है। इंटरनेट ने इस पूरे सूचना तंत्र को पंख लगा दिए हैं। पहले कंप्यूटर, फिर लेपटॉप और अब मोबाइल इसका सबसे सुचारू साधन बनकर उभरा है। मोबाइल केवल बातचीत करने का माध्यम ही नहीं रहा बल्कि इंटरनेट के चलते इसने कितनी ही साधन–सुविधाओं को अपने अंदर समाहित कर लिया है, कितने ही साधनों को यह निगल गया है और इसने कितने ही लोगों से दूरियां भी बना दी है। 'मोबाइल एक सुविधा अनेक' का यह मंत्र और साधन सभी की जेब में अपना स्थान बनाए हुए हैं। बातचीत के सफर से लेकर आज हर एक सुविधा इस यंत्र में धीरे–धीरे जुड़ती चली गई है। कभी पूरे गांव में एक टेलीविजन होता था. फिर घर–घर में टेलीविजन आया. अब टेलीविजन की उपयोगिता कितनी रह गई है, आप स्वयं से ही जान सकते हैं। मोबाइल के छोटे से स्क्रीन पर लोग घंटों–घंटों फिल्म, वीडियो, रील आदि देखते रहते हैं। हाथ पर बांधने वाली घड़ी को मोबाइल ने अपने अंदर समेट लिया, कैलेंडर और महत्वपूर्ण तारीखों को इसने अपने अंदर ले लिया। डायरी लेखन का काम भी इसमें अपने अंदर समाहित कर लिया। बढ़ती अर्थव्यवस्था में अब बैंक, एटीएम मशीन, शेयर बाजार का उतार चढ़ाव आदि की जगह मोबाइल ने ही ले ली है। मोबाइल में ही पैसे के लेनदेन का बहुत ही सरल तरीका हो गया है। अब व्यक्ति समाज में बैठे या ना बैठे लेकिन सोशल मीडिया अकाउंट के माध्यम से देश–दुनिया में हो रहे व्यक्ति की हर पल की जानकारी यहां चल रही है, स्वयं भी वहीं खड़ा हुआ व्यक्ति अपनी जानकारी साझा कर रहा है। शादी के रिश्ते अब इंटरनेट अर्थात वेबसाइट के माध्यम से हो रहे हैं। लोगों का आमने–सामने का संवाद खत्म ही हो रहा है। देश की राजनीति सोशल मीडिया का आधार बनती जा रही है। हर तरफ इसी का बोलबाला है। बच्चे मैदान में काम मोबाइल गेम्स में अधिक व्यस्त दिखाई देते हैं। पढ़ने का सारा मसाला इस छोटे से यंत्र में कहीं ना कहीं से मिल ही जाता है। अच्छा देखना है या बुरा देखना है सभी इसकी परिधि में आ जाते हैं। सरकार बहुत सी साइट और कार्यों पर रोक लगा चुकी है फिर भी कोई ना कोई रास्ता निकल ही रहा है। ऑनलाइन ठगी और डिजिटल अरेस्ट ने तो नाक में दम कर रखा है। लोग एक लाइक के चक्कर में अपनी जान पर खेल जाते हैं। कितनी ही बार जान भी चली जाती है। लोग रील या अन्य वीडियो बनाने के चक्कर में अपनी जान जोखिम में डाल देते हैं। सोशल मीडिया ने लोगों को भ्रमित कर दिया है, बाह्य दुनिया से दूर अब हम इस मोबाइल के अंदर की दुनिया में ही डूबे रहना चाहते हैं। छोटे–छोटे बच्चे मोबाइल की लत लगा चुके हैं। हर जगह व्यक्ति को मोबाइल के साथ जोड़ दिया गया है। सरकारें ऑन लाईन शिक्षा अर्थात विद्यालय–विश्वविद्यालय चलाने की बात कर रही हैं। ऑन लाईन कोविड के समय मजबूरी में चलाई गई शिक्षा थी, लेकिन इसे सफल साधन–सुविधा मानकर चलाया जा रहा है। इसके दुष्परिणाम भी सामने हैं कि बच्चों की आँखें, मस्तिष्क, शारीरिक बनावट सभी कुछ खराब हो रहे हैं। फिर भी सरकारें इस ओर क्यों जा रही है, यह भी तो सोचने की बात है। एक कहावत है कि बाजार लुटने के बाद सजग होना कहां की बुद्धिमानी है। जब देश का भविष्य ही खराब हो जायेगा अर्थात युवा तो आप क्या हासिल कर पाओगे। सरकारें, माता–पिता और समाज के जागरूक लोग कह रहे हैं कि बच्चों को कैसे मोबाइल की लत से दूर किया जाए। जब मोबाइल हर क्षेत्र की जरूरत हो चुका है तो फिर इससे लोगों को कैसे दूर किया जाए। यह एक बड़ा प्रश्न है? मोबाइल से हमें स्वयं दूरी बनानी होगी, फिर बच्चों से कहकर उसे दूरी बनवानी होगी। स्वयं के उदाहरण से ही आप दूसरे को शिक्षा दे सकते हैं।मोबाइल का प्रयोग एक निश्चित समय और सुविधाओं के लिए ही होना चाहिए। सभी चीजों को इसके साथ जोड़ने के चलते अब बहुत सी समस्याएं खड़ी हो रही हैं।

अत्यंत गंभीर है कृत्रिम मेधा के विकास में भारतीय भाषाओं के डाटा की कमी का मामला

इक्कीसवीं सदी के तीसरे दशक में कृत्रिम मेधा या आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस विश्व की सबसे प्रभावशाली तकनीकों में से एक बन चुकी है। स्वास्थ्य, शिक्षा, उद्योग, मीडिया, प्रशासन और व्यापार जैसे अनेक क्षेत्रों में इसका उपयोग तेजी से बढ़ रहा है। इस तकनीक की सफलता का एक महत्वपूर्ण आधार विशाल मात्रा में उपलब्ध डिजिटल डेटा होता है। कृत्रिम मेधा के मॉडल उसी भाषा और विषय को बेहतर समझ पाते हैं जिसके बारे में पर्याप्त और गुणवत्तापूर्ण डेटा उपलब्ध हो। यही कारण है कि विश्व स्तर पर एआई तकनीक अंग्रेजी जैसी भाषाओं में अधिक प्रभावी दिखाई देती है, जबकि अनेक अन्य भाषाएँ तकनीकी विकास की इस दौड़ में पीछे रह जाती हैं। भारत जैसे बहुभाषी देश में यह स्थिति एक गंभीर चुनौती के रूप में सामने आ रही है, क्योंकि यहाँ भाषाई विविधता अत्यंत व्यापक है लेकिन भारतीय भाषाओं के लिए उपलब्ध डिजिटल डेटा अभी भी सीमित है। यही कारण है कि विशेषज्ञ लगातार यह चेतावनी दे रहे हैं कि यदि भारतीय भाषाओं के लिए पर्याप्त डेटा का विकास नहीं किया गया तो एआई तकनीक के लाभ समाज के बड़े हिस्से तक नहीं पहुँच पाएँगे। भारत की भाषाई विविधता को समझना इस समस्या की गंभीरता को स्पष्ट करता है। भारत की 2011 की जनगणना के अनुसार देश में 19,500 से अधिक मातृभाषाएँ और बोलियाँ दर्ज की गई थीं। इनमें से लगभग 121 भाषाएँ ऐसी हैं जिनके बोलने वालों की संख्या 10,000 से अधिक है। भारतीय संविधान की आठवीं अनुसूची में 22 भाषाओं को आधिकारिक मान्यता प्राप्त है, जिनमें हिंदी, बंगाली, तमिल, तेलुगु, मराठी, गुजराती, कन्नड़, मलयालम, उर्दू, पंजाबी, असमिया और ओड़िया जैसी प्रमुख भाषाएँ शामिल हैं। इन भाषाओं को करोड़ों लोग बोलते हैं और इनके साहित्य, संस्कृति और सामाजिक जीवन की समृद्ध परंपरा रही है। इसके बावजूद डिजिटल दुनिया में इन भाषाओं की उपस्थिति अपेक्षाकृत कम है। इंटरनेट पर उपलब्ध सामग्री का अधिकांश भाग अभी भी अंग्रेजी भाषा में है। विभिन्न अंतरराष्ट्रीय अध्ययनों के अनुसार वैश्विक वेब सामग्री का एक बड़ा हिस्सा अंग्रेजी में उपलब्ध है, जबकि अनेक भाषाओं की डिजिटल उपस्थिति सीमित है। यही असंतुलन कृत्रिम मेधा के विकास में भी दिखाई देता है। कृत्रिम मेधा के आधुनिक मॉडल, विशेष रूप से भाषा आधारित प्रणालियाँ, विशाल डिजिटल पाठ और भाषाई डेटा के आधार पर प्रशिक्षित होती हैं। यदि किसी भाषा में पर्याप्त डिजिटल सामग्री उपलब्ध नहीं है, तो उस भाषा के लिए विकसित एआई मॉडल अपेक्षाकृत कमजोर या सीमित क्षमता वाले होते हैं। भारत के संदर्भ में यही समस्या सबसे बड़ी चुनौती बनकर उभर रही है। हिंदी, तमिल, बंगाली और मराठी जैसी प्रमुख भाषाओं के लिए कुछ हद तक डिजिटल संसाधन उपलब्ध हैं, लेकिन कई अन्य भाषाओं और बोलियों के लिए यह संसाधन अत्यंत सीमित हैं। इसका परिणाम यह होता है कि एआई आधारित अनुवाद, वाणी पहचान, पाठ विश्लेषण और डिजिटल सहायक जैसी सेवाएँ भारतीय भाषाओं में उतनी प्रभावी नहीं हो पातीं जितनी अंग्रेजी में होती हैं। इस समस्या की गंभीरता को विभिन्न नीति दस्तावेजों और शोध अध्ययनों में भी रेखांकित किया गया है। भारत सरकार के नीति आयोग ने अपनी "राष्ट्रीय एआई रणनीति" से संबंधित चर्चाओं में इस बात पर जोर दिया है कि भारतीय भाषाओं के लिए डिजिटल डेटा का अभाव एआई विकास की बड़ी बाधाओं में से एक है। इसी प्रकार इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय द्वारा संचालित कई तकनीकी कार्यक्रमों में यह स्वीकार किया गया है कि स्थानीय भाषाओं के लिए बड़े पैमाने पर भाषाई डेटा का निर्माण आवश्यक है। यदि यह कार्य समय रहते नहीं किया गया तो तकनीकी विकास का लाभ केवल उन लोगों तक सीमित रह जाएगा जो अंग्रेजी या कुछ प्रमुख भाषाओं का उपयोग करते हैं। भारतीय भाषाओं के डेटा की कमी केवल तकनीकी समस्या नहीं है बल्कि यह सामाजिक और आर्थिक असमानता से भी जुड़ी हुई है। भारत की बड़ी आबादी अभी भी अपनी मातृभाषाओं में संवाद करती है। ग्रामीण क्षेत्रों और छोटे शहरों में रहने वाले करोड़ों लोग अंग्रेजी का सीमित उपयोग करते हैं या बिल्कुल नहीं करते। यदि डिजिटल सेवाएँ और एआई आधारित प्रणालियाँ मुख्य रूप से अंग्रेजी पर आधारित रहेंगी, तो समाज का एक बड़ा हिस्सा इन सेवाओं से वंचित रह सकता है। इसका सीधा प्रभाव शिक्षा, स्वास्थ्य, सरकारी सेवाओं और डिजिटल अर्थव्यवस्था तक पहुँच पर पड़ सकता है। इसलिए भारतीय भाषाओं के लिए एआई विकास केवल तकनीकी नवाचार का प्रश्न नहीं बल्कि सामाजिक समावेशन का भी विषय है। शिक्षा के क्षेत्र में भी भारतीय भाषाओं के डेटा की कमी का प्रभाव स्पष्ट दिखाई देता है। एआई आधारित शैक्षिक उपकरणों का उपयोग दुनिया भर में तेजी से बढ़ रहा है। व्यक्तिगत सीखने की प्रणाली, स्वचालित अनुवाद और डिजिटल शिक्षण सामग्री जैसी तकनीकें शिक्षा को अधिक सुलभ बनाने में मदद कर सकती हैं। लेकिन यदि ये उपकरण केवल अंग्रेजी में उपलब्ध हों, तो भारतीय भाषाओं में शिक्षा प्राप्त करने वाले लाखों छात्र इन सुविधाओं से वंचित रह सकते हैं। भारत में प्राथमिक और माध्यमिक शिक्षा का एक बड़ा हिस्सा क्षेत्रीय भाषाओं में संचालित होता है। इसलिए शिक्षा में एआई के प्रभावी उपयोग के लिए भारतीय भाषाओं में डिजिटल सामग्री और डेटा का निर्माण अत्यंत आवश्यक है। स्वास्थ्य और प्रशासन जैसे क्षेत्रों में भी यही समस्या सामने आती है। यदि स्वास्थ्य सेवाओं में उपयोग होने वाली एआई प्रणालियाँ केवल कुछ भाषाओं तक सीमित होंगी, तो ग्रामीण क्षेत्रों के मरीजों तक उनका लाभ नहीं पहुँच पाएगा। इसी प्रकार सरकारी सेवाओं के डिजिटल प्लेटफॉर्म भी तभी प्रभावी होंगे जब वे नागरिकों की भाषाई विविधता को ध्यान में रखते हुए विकसित किए जाएँ। भारत में डिजिटल शासन की सफलता काफी हद तक इस बात पर निर्भर करेगी कि तकनीक कितनी भाषाई समावेशिता के साथ विकसित की जाती है। भारतीय भाषाओं के डेटा की कमी के पीछे कई कारण हैं। सबसे बड़ा कारण यह है कि लंबे समय तक डिजिटल तकनीक का विकास मुख्य रूप से अंग्रेजी भाषा के आधार पर हुआ। इंटरनेट और कंप्यूटर तकनीक की प्रारंभिक संरचना भी अंग्रेजी पर केंद्रित थी। इसके अतिरिक्त कई भारतीय भाषाओं में मानकीकृत डिजिटल पाठ और भाषाई संसाधनों का अभाव रहा है। कई भाषाओं में लिखित साहित्य तो प्रचुर मात्रा में है, लेकिन उसका डिजिटल रूपांतरण अभी भी सीमित है। इसके अलावा भाषाई अनुसंधान और तकनीकी संसाधनों में निवेश भी अपेक्षाकृत कम रहा है। हाल के वर्षों में इस स्थिति को सुधारने के लिए कुछ प्रयास शुरू हुए हैं। भारत सरकार और विभिन्न तकनीकी संस्थानों ने भारतीय भाषाओं के लिए डिजिटल संसाधन विकसित करने की दिशा में कई पहलें शुरू की हैं। उदाहरण के लिए भाषा प्रौद्योगिकी से संबंधित कार्यक्रमों के माध्यम से विभिन्न भाषाओं के लिए डेटा संग्रह और संसाधन निर्माण का कार्य किया जा रहा है। कई विश्वविद्यालय और शोध संस्थान भी भारतीय भाषाओं के लिए भाषाई कॉर्पस विकसित करने पर काम कर रहे हैं। तकनीकी कंपनियाँ भी बहुभाषी एआई मॉडल विकसित करने की दिशा में निवेश कर रही हैं। हालांकि इन प्रयासों के बावजूद अभी भी बहुत काम किया जाना बाकी है। भविष्य के डिजिटल समाज में भाषा की भूमिका अत्यंत महत्वपूर्ण होगी। यदि कृत्रिम मेधा के विकास में भारतीय भाषाओं को पर्याप्त स्थान नहीं दिया गया, तो यह तकनीक समाज के बड़े हिस्से को पीछे छोड़ सकती है। इसके विपरीत यदि भारतीय भाषाओं के लिए पर्याप्त डिजिटल डेटा और संसाधन विकसित किए जाते हैं, तो एआई तकनीक शिक्षा, प्रशासन, कृषि और स्वास्थ्य जैसे क्षेत्रों में व्यापक सकारात्मक परिवर्तन ला सकती है। इससे डिजिटल सेवाएँ अधिक समावेशी बनेंगी और तकनीकी विकास का लाभ समाज के हर वर्ग तक पहुँच सकेगा। अंततः यह स्पष्ट है कि कृत्रिम मेधा के विकास में भारतीय भाषाओं के डेटा की कमी का मुद्दा अत्यंत गंभीर है। यह केवल तकनीकी विकास का प्रश्न नहीं बल्कि भाषाई समानता, सांस्कृतिक संरक्षण और सामाजिक न्याय से भी जुड़ा हुआ है। यदि भारत को वास्तव में डिजिटल और तकनीकी शक्ति के रूप में विकसित होना है, तो उसे अपनी भाषाई विविधता को तकनीकी विकास का आधार बनाना होगा। इसके लिए सरकार, तकनीकी कंपनियों, शैक्षणिक संस्थानों और नागरिक समाज को मिलकर काम करना होगा। बड़े पैमाने पर भाषाई डेटा का निर्माण, डिजिटल सामग्री का विकास और बहुभाषी तकनीकी अनुसंधान ही इस समस्या का स्थायी समाधान प्रदान कर सकते हैं। तभी कृत्रिम मेधा का विकास भारत की वास्तविक भाषाई और सांस्कृतिक विविधता को प्रतिबिंबित करते हुए एक समावेशी तकनीकी भविष्य का निर्माण कर सकेगा।

डॉ. शैलेश शुक्ला , वैश्विक समूह संपादक, सृजन संसार अंतरराष्ट्रीय पत्रिका समूह

सनी लियोन वाला किरदार निभाएंगी तमन्ना भाटिया

एकता कपूर की फिल्म 'रागिनी एमएमएस' के तीसरे पार्ट 'रागिनी एमएमएस 3' के लिए एक्ट्रेस तमन्ना भाटिया का नाम फायनल हो चुका है। सनी लियोन की तरह तमन्ना भी अब इस फिल्म के जरिए अपने हुस्न के जलवे दिखाने के लिए पूरी तरह तैयार हैं। शशांक घोष दारा डायरेक्ट की जाने वाली इस फिल्म में वह आमिर खान के बेटे जुनैद खान संग रोमांस करते नजर आने वाले हैं। इस डार्क कॉमेडी और म्यूजिकल फिल्म की शूटिंग शुरू हो चुकी है और फिल्म अगले साल रिलीज होगी। 21 दिसंबर 1989 को मुंबई में जन्मीं तमन्ना आज बॉलीवुड और फैशन की दुनिया की मशहूर हस्तियों में से एक हैं। रेड कार्पेट से लेकर कैजुअल आउटिंग तक, तमन्ना हर मौके पर स्टाइलिश और ट्रेंडी दिखती हैं।उनके कपड़े हमेशा फैशन ट्रेंड्स के हिसाब से होते हैं और उनका स्टाइल उनकी पर्सनालिटी को और भी निखार देता है। खूबसूरती के मामले में तो वह ऐश्वर्या को कड़ी टक्कर देती है।फिल्मों में कदम रखने से पहले साल 2005 में सिंगर अभिजीत सावंत म्यूजिक वीडियो 'लफ्जों में' में पहली बार तमन्ना भाटिया को नोटिस किया गया था। उसके बाद उन्होंने अपने एक्टिंग करियर की शुरुआत हिंदी फिल्म 'चांद सा रोशन चेहरा' (2005) से की थी।फिर उसी साल तेलुगु फिल्म 'श्री' (2005) और उसके उसके अगले साल तमिल फिल्म 'केडी' (2006) में काम किया। इसके बाद उनकी तेलुगु फिल्म 'हैप्पी डेज़' और तमिल फिल्म 'कल्लूरी' (2007) आईं।करियर के शुरुआती दिनों में तमन्ना भाटिया ने छोटे मोटे रोल भी किए मगर आगे उनकी मेहनत, टैलेंट और आत्मविश्वास ने उन्हें सिर्फ साउथ ही नहीं, बल्कि पूरे देश में पहचान दिलाई और देखते ही देखते वह साउथ की फिल्म इंडस्ट्री की पॉपुलर एक्ट्रेस बन गईं।तमन्ना भाटिया को सबसे ज्यादा पॉपुलेरिटी पेन इंडिया फिल्म 'बाहुबलीः द बिगिनिंग' (2015) और 'बाहुबली 2ः द कन्क्लूजन' (2017) से मिली।फिल्म 'चांद सा रोशन चेहरा' (2005) के बाद तमन्ना ने 'हिम्मतवाला' (2013), 'हमशकल्स' (2014), 'एंटरटेनमेंट' (2014), 'तूतक तूतक तूतिया' (2016), 'खामोशी' (2019) और 'बबली बाउंसर' (2022) 'प्लान ए प्लान बी' (2022) और 'सिकंदर का मुकद्दर' (2024) जैसी हिंदी फिल्में कीं लेकिन साउथ की तरह उन्हें यहां उतनी कामयाबी नहीं मिल सकी। दूसरी तरफ तमन्ना भाटिया ने जब कुछ हिंदी फिल्मों मे स्पेशल सॉग अपीयरेंस किया, तब उन पर फिल्माये गये वे डांस नंबर काफी सराहे गये।फिल्म 'हिम्मतवाला' (2013) में अजय देवगन के साथ स्क्रीन शेयर करते हुए उन्होंने 'ताकी ताकी...' किया था। उसके बाद वह फिल्म 'हमशकल्स' (2014) में 'पिया के बाजार में' नजर आई थी। 'स्त्री 2' (2024) के गाने 'आज की रात' में तमन्ना ने अपने डांस मूव्स से जो जलवा बिखरा वह कमाल का था। उसके बाद अजय देवगन की फिल्म 'रेड 2' (2025) के गाने 'नशा' में तमन्ना भाटिया ने अपने डांस मूव्स से फैंस के होश ही उड़ा दिए। तमन्ना भाटिया ट्रेंड भरतनाट्यम डांसर हैं। अपने अमेजिंग डांस मूव्स और स्टाइलिश स्क्रीन प्रेजेंस से वो हर बार ही बाजी अपने नाम कर लेती हैं. उनके लटके–झटके लोगों को दीवाना बना देते हैं। तमन्ना का डांस और अदाओं पर फैंस फिदा होते हैं।हाल ही में शाहिद कपूर की फिल्म ओ रोमियो' (2026) में नजर आईं। इसमें शाहिद कपूर के साथ तृप्ति डिमरी लीड रोल में थीं जबकि तमन्ना का एक खास किरदार था। इसके बाद तमन्ना तमिल फिल्म 'पुरूषन' के अलावा हिंदी फिल्म 'विवान–फोर्स ऑफ द फोरेस्ट', 'रेंजर्स', 'आईपीएस मारिया', वी शांताराम की बायोपिक और काफी समय से बन रही बोले चूड़ियां कर रही हैं।सस्पेंस थ्रिलर फिल्म 'वन फोर्स ऑफ द फॉरेस्ट' 15 मई 2026 में रिलीज होगी। जबकि 'रेंजर्स' 4 दिसंबर 2026 को रिलीज होगी। इसमें अजय देवगन और संजय दत्त लीड रोल में हैं। 2026 में वो फिल्म 'रेंजर' में दिखेंगी। वी शांताराम की बायोपिक में वे उनकी पत्नी जयश्री शांताराम का किरदार निभा रही हैं। यह फिल्म संभवतः अगले साल आयेगी।

हमारे बीच कभी कोई मतभेद नहीं रहाः अक्षय और प्रियदर्शन

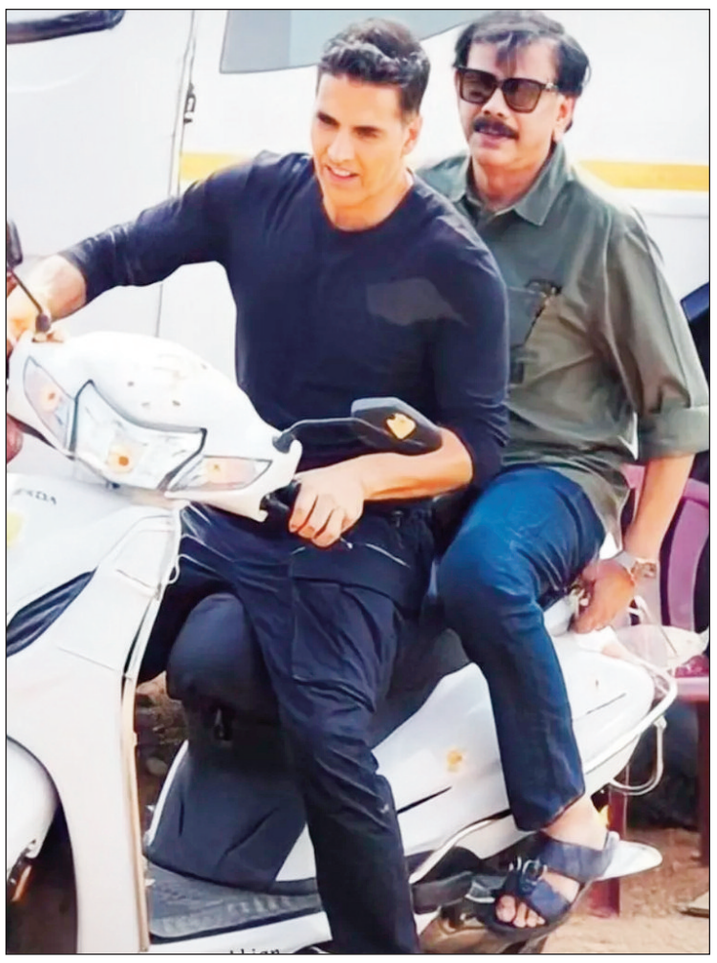

मुंबई, (भाषा) अभिनेता अक्षय कुमार और निर्देशक प्रियदर्शन ने कहा है कि उनके बीच कोई मतभेद नहीं है। दोनों अपनी अगली फिल्म 'भूत बंगला' की रिलीज की तैयारी में जुटे हैं, जो उनकी कई सफल कॉमेडी फिल्मों के बाद आ रही है। अक्षय और प्रियदर्शन ने पहली बार वर्ष 2000 में फिल्म 'हेरा फेरी' में साथ काम किया था, जिसे अभिनेता की छवि को 'एक्शन स्टार' से हास्य अभिनेता में बदलने का श्रेय दिया जाता है। इसके बाद उनकी जोड़ी ने फिल्म 'गरम मसाला', 'भागम भाग', 'भूल भुलैया', 'दे दना दन' और 'खट्टा मीठा' जैसी फिल्में दीं। लंबे समय तक साथ काम करने के दौरान मतभेद होने के सवाल पर दोनों ने इनकार किया। अक्षय ने 'पीटीआई–भाषा' से कहा, "अगर मैं उनसे कहता हूं, 'सर, यह अच्छा लग रहा है?' और वे कहते हैं 'नहीं', तो मैं वह नहीं करता। इसमें कोई मतभेद नहीं होता।" प्रियदर्शन ने कहा, "यह शब्द, उसका मतलब ही हमारे शब्दकोश में नहीं है।" उनकी अगली फिल्म 'भूत बंगला' 10 अप्रैल को सिनेमाघरों में रिलीज होगी। निर्देशक प्रियदर्शन भूत–प्रेत में विश्वास नहीं करते, जबकि अभिनेता अक्षय कुमार का कहना है कि वह "ऊर्जाओं" में विश्वास करते हैं। प्रियदर्शन ने कहा कि फिल्म में नवीनता इस बात में है कि इसमें देश में प्रचलित लोककथाओं, अंधविश्वास और काले जादू जैसे तत्वों को शामिल किया गया है। उन्होंने कहा, "हम इन कमजोरियों का इस्तेमाल कर रहे हैं और इसमें काफी तर्क भी जोड़ रहे हैं।" अक्षय ने प्रियदर्शन को उन्हें 'सिचुएशनल कॉमेडी' से परिचित कराने का श्रेय दिया। अक्षय ने कहा, ''उन्होंने मुझे 'सिचुएशनल कॉमेडी' सिखाई। मैंने यह भी सीखा कि एक संपादक का कितना महत्व होता है और निर्देशक का दृढ़ विश्वास क्या मायने रखता है। अलग–अलग कोणों से शॉट लेने की जरूरत नहीं होती। उन्होंने मुझसे कहा कि जो निर्देशक संपादक भी होता है, वह अपने काम को जानता है और निर्माता का समय और पैसा बर्बाद नहीं करता।''

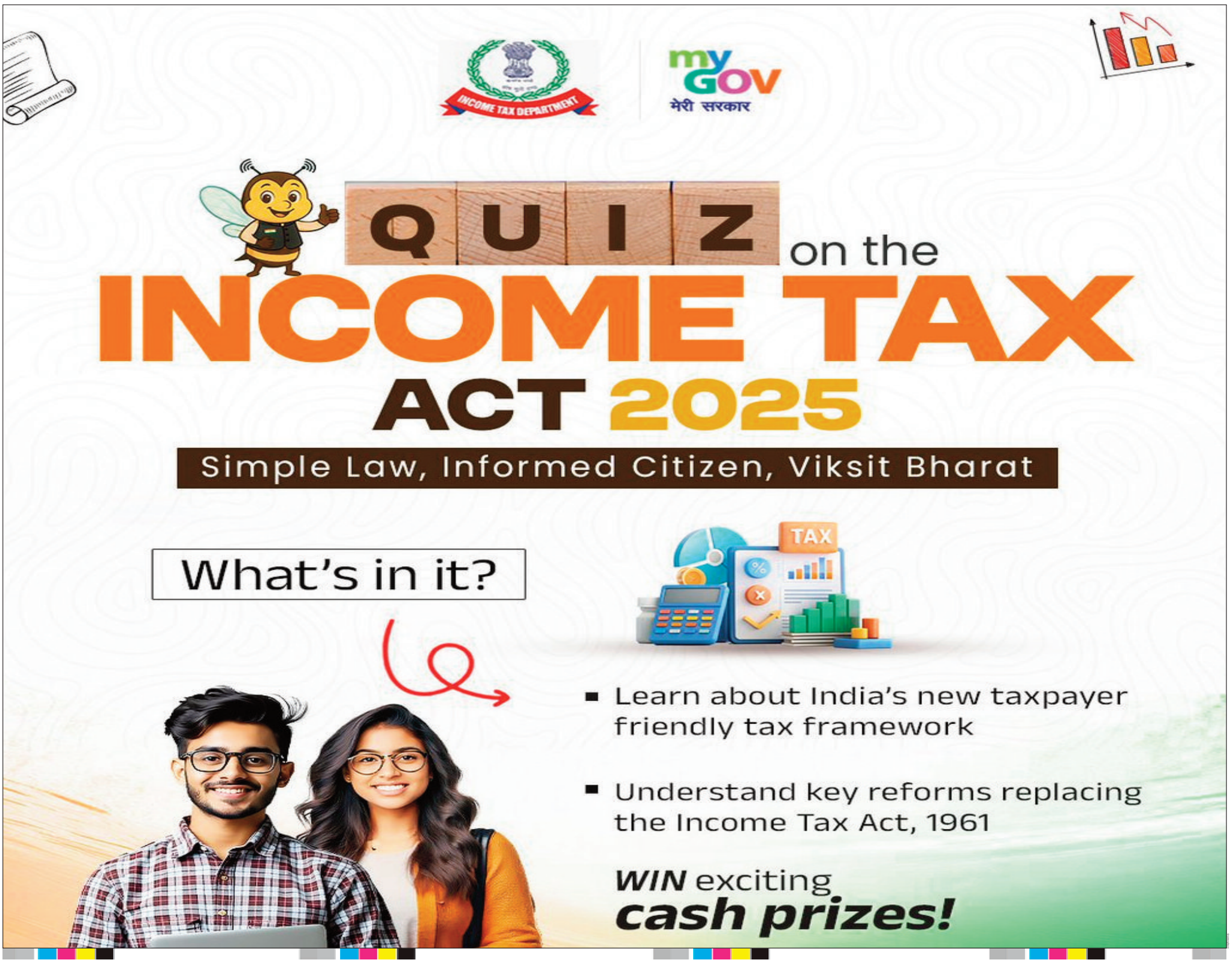

महानगरों में ईंधन संकट

आज भारतीय ज्ञान परंपरा को लेकर अध्ययन अध्यापन हो रहा है। विचार करें तो भारतीय ज्ञान परंपरा और भारतीय समाज कभी किसी देश पर आश्रित नहीं रहा है। हमें जो भी चाहिए था, हमने शोधपरक दृष्टि से उसे वस्तु को यहां पैदा किया है। हमारे ऋषि–मुनियों, साधकों, संतों, शोधकर्ताओं ने सृष्टि में जड़ से लेकर वृक्ष के हर भाग पर शोध किया। नदी, पर्वतों, ग्रहों, नक्षत्रों, दिन–रात के पहरों, पलों आदि सभी का अध्ययन किया।हमारे स्वास्थ्य, पर्यावरण, समाज को कैसे ठीक रखा जा सकता है, उसका उपचार किया। उसके अलग–अलग नाम और उपयोग भी समाज को समझाये। लकड़ी का ही उदाहरण ले सकते हैं। यज्ञ में प्रयोग होने वाली आम की लकड़ी, जिसे समिधा कहा जाता है। चूल्हे में जलने पर इसे ईंधन कहा जाता है। चिता में लकड़ी लगाई जाती है। इस प्रकार अलग–अलग प्रयोग क्षेत्र में अलग–अलग शब्द प्रयोग में लाए गए। हमने अपने आसपास और वातावरण के हिसाब से फल–सब्जियां, अन्न आदि को बोया–खाया, जिससे हम स्वस्थ रहें। हमारे समाज का विकास हर क्षेत्र में अलग–अलग तरीके से किया गया। गांव में ही कारीगरों को स्थापित किया गया। गांव का सारा काम बिना किसी बड़े खर्च के वहां रह रहे लोग आसानी से आपसी सहयोग से कर लेते थे। सभी काम आपसी भाईचारे के साथ किए जाते थे। जैसे–जैसे आक्रमणकारी भारत में आए, उन्होंने हमारी सामाजिक व्यवस्था को भंग किया। देश में नए–नए विवाद पैदा कर दिए। गांव से अलग किले, नगर और महानगर बसा दिए गए। जाति–धर्म के नाम पर लोगों को बांटकर आपस में ही लड़वाया गया। समाज विकसित कम बिखरा हुआ अधिक दिखाई देने लगा। एक बार फिर गांव की ओर चलते हैं। गांव में कभी ऊर्जा, जल, खाद्य सामग्री आदि का संकट था ही नहीं और ना कभी होगा, यह भी एक दावे के साथ कहा जा सकता है। हमने गांव के बाहर पानी के तालाब बनवाए हुए थे जिसमें पशु–पक्षी सभी पानी पीते थे। बरसात का पानी वहां इक्ट्ठा होता था। तालाब के नजदीक ही कुएं बनवाएं, जिनका पानी मीठा रहा। पीने के प्रयोग और खान–पान में प्रयोग होने के चलते ही इन कुओं को हमने पूजा और कुआं पूजन आज भी भारतीय संस्कृति में है। पशुधन से दूध मिला, साथ ही उनके गोबर से उपले बनाकर खाना बनाने में अर्थात ईंधन के रूप में प्रयोग किया। उत्तम खेती के लिए गोबर का खाद प्रयोग में लिया। विचार करें तो किसान खेत में बहुत सारी फैसलें ऐसी भी बोता है, जिससे ईंधन पैदा होता है, जैसे– सरसों, ढांचा, अरहर आदि की खेती से बड़ी मात्रा में ईंधन निकलकर आता है, इससे चूल्हा जलता है। ईंधन अर्थात ऊर्जा का कोई संकट किसी भी तरीके का नहीं था। आधुनिकता की दौड़ने नगरों–महानगरों को जन्म दिया लेकिन विचार करके देखें तो यहां सुविधाओं के साथ संकट की भी स्थिति पैदा हो जाती है। वर्तमान में वैश्विक स्तर पर जो युद्ध हो रहे हैं, उनसे हमारे देश का किसी प्रकार का कोई लेना–देना नहीं है और ना ही हम उस युद्ध में शामिल हैं। उन देशों की लड़ाई का संकट आज हमारे देश में भी कई प्रकार का संकट खड़ा कर रहा है जिसमें ऊर्जा संकट सबसे बड़ा है क्योंकि हम ऊर्जा के लिए आश्रित हो गए हैं। हमने अपनी ज्ञान परंपरा, अपने सामाजिक ढांचे को सही से समझा नहीं। अब घरेलू गैस, डीजल, पेट्रोल आदि की कमी के चलते लोग शहर से फिर गांव की ओर बढ़ रहे हैं। कोरोना के समय भी लोग शहर से गांव की ओर आए थे। सही मायने में हमारी सामाजिक और ज्ञान परंपरा गांव में ही बसती है। हमें अपने गांवों को उन्नत करना होगा, वहां पर साधन–सुविधाओं का विकास करना होगा। वैश्विक पटल पर दुनिया अपना अलग रंग रखती है लेकिन गांव व्यक्ति के मूल से जुड़े हैं। पीपल–बरगद के नीचे बैठे लोग डिप्रेशन में नहीं बल्कि मौज–मस्ती से बात करते हैं। हम आधुनिकता और नयापन का चोला ओढ़ कर महानगरों में भागते हैं। संकट के समय फिर गांव की ओर होते हैं। विदेशी आक्रमणकारियों ने हमें ऐसा व्यापार सिखाया है, जिससे हम उन पर आश्रित हो सके, हमें उनसे लाभ कम, हानि अधिक होती है। सरकार को अपनी नीतियों में परिवर्तन लाना होगा।विचार करें तो गौशाला के अंदर ही गोबर गैस प्लांट की संख्या को बढ़ाना होगा। साथ ही पशु डेयरी उद्योग में भी गोबर गैस प्लांट को नए सिरे से जन्म देना होगा। सौर ऊर्जा से घर की रसोई का ईंधन बनाना आदि विषयों पर सोचना होगा। बहुत सारे परिवर्तनों के साथ सरकार को इस ओर ध्यान देना होगा। यदि हम किसी भी देश पर आश्रित रहेंगे तो विकसित भारत का जो स्वप्न है, वह कैसे संभव हो पाएगा। ऐसे तो विश्व में कहीं ना कहीं युद्ध और कहीं ना कहीं अर्थव्यवस्था, राजनीति आदि में परिवर्तन होता ही रहता है। ऐसे संकटों से निपटने के लिए सरकार को स्वयं बड़े–बड़े निर्णय लेने होंगे और आत्मनिर्भर की ओर बढ़ना होगा। जिससे कि समयानुसार हम किसी दूसरे का मुंह ना तांके। डॉ. नीरज भारद्वाज

प. बंगाल की मतदाता सूची से 79 लाख 'फर्जी' नाम हटाए गए; भाजपा 177 से अधिक सीट जीतेगी: शुभेंदु

कोलकाता, (भाषा) भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) के वरिष्ठ नेता शुभेंदु अधिकारी ने बुधवार को दावा किया कि मतदाता सूचियों के विशेष गहन पुनरीक्षण (एसआईआर) के दौरान राज्य की मतदाता सूची से लगभग 79 लाख "फर्जी" नाम हटा दिए गए हैं और इस बात पर जोर दिया कि इससे भाजपा को अगले महीने होने वाले विधानसभा चुनाव में 177 से अधिक सीट हासिल करने में मदद मिलेगी। शुभेंदु अधिकारी ने पूर्व मेदिनीपुर जिले में पार्टी कार्यकर्ताओं की एक बैठक को संबोधित करते हुए आरोप लगाया कि राज्य में सत्तारूढ़ तृणमूल कांग्रेस सत्ता में बने रहने के लिए हमेशा फर्जी मतदाताओं पर निर्भर रही है और जारी पुनरीक्षण प्रक्रिया ऐसे नामों को हटाने के लिए शुरू की गई है। उन्होंने कहा कि इससे भाजपा को चुनाव जीतने में मदद मिलेगी। भाजपा नेता अधिकारी ने हटाए गए नामों का वर्णन करने के लिए कई उपमाओं का प्रयोग करते हुए कहा, "नाश्ते के समय 58 लाख नाम हटाए गए, दोपहर के भोजन के समय सात लाख नाम हटाए गए और शाम की चाय के दौरान 14 लाख और नाम हटा दिए गए। रात का खाना अभी परोसा जाना बाकी है।" पश्चिम बंगाल विधानसभा में विपक्ष के नेता शुभेंदु अधिकारी का परोक्ष तौर पर इशारा एसआईआर कवायद के गणना चरण के बाद हटाए गए 58 लाख नाम और 28 फरवरी को सूचियों के अंतिम प्रकाशन के दौरान कथित तौर पर हटाए गए अतिरिक्त सात लाख नामों की ओर था। अधिकारी ने दावा किया कि सोमवार को प्रकाशित पहली पूरक मतदाता सूची में जिन 32 लाख मतदाताओं की पड़ताल की गई थी, उनमें से 14 लाख नाम हटा दिए गए थे। हालांकि, निर्वाचन आयोग ने अभी तक पूरक सूची में जांचे गए मतदाताओं की कुल संख्या या हटाए गए नामों की संख्या की आधिकारिक पुष्टि नहीं की है। उन्होंने कहा, ''मतदाता सूची से अब तक 79 लाख नाम हटाए जा चुके हैं।'' उन्होंने दावा किया कि ''इन फर्जी मतदाताओं में से 90 प्रतिशत तृणमूल कांग्रेस के पक्ष में वोट डालते थे।'' अधिकारी ने आरोप लगाया कि पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी पुनरीक्षण प्रक्रिया का विरोध कर रही थीं और इसे रोकने के लिए उन्होंने भारत के उच्चतम न्यायालय का रुख किया। उन्होंने कहा कि एसआईआर कवायद पहले भी कई बार की जा चुकी है, लेकिन इस बार सत्ताधारी पार्टी ने इसका विरोध किया। भाजपा नेता ने आरोप लगाया कि मुख्यमंत्री बांग्लादेश से आए ''अवैध मुस्लिम घुसपैठियों को बचाने की कोशिश कर रही हैं, जो तृणमूल कांग्रेस के वोट बैंक रहे हैं।'' अधिकारी ने राज्य में जनसांख्यिकीय परिवर्तनों का भी उल्लेख किया और दावा किया कि ''पश्चिम बंगाल में हिंदू आबादी 1951 की जनगणना में 85 प्रतिशत से घटकर आज 65 प्रतिशत से भी कम हो गई है।'' पश्चिम बंगाल में 23 और 29 अप्रैल को होने वाले विधानसभा चुनाव में भाजपा की संभावनाओं पर विश्वास जताते हुए उन्होंने कहा कि राज्य में पार्टी की बढ़त उल्लेखनीय रही है। उन्होंने याद दिलाया कि 2016 में भाजपा की तीन सीट थीं, जो 2021 के विधानसभा चुनाव में बढ़कर 77 हो गईं। उन्होंने कहा, ''इस बार कम से कम 177 सीट होंगी; चार मई की दोपहर (जब चुनाव परिणाम घोषित होंगे) तक यह आंकड़ा कहां तक पहुंचता है, यह हम देखेंगे।'' अधिकारी ने पार्टी कार्यकर्ताओं के लिए एक रणनीति भी बताई और उनसे आग्रह किया कि वे अद्यतन मतदाता सूची का अध्ययन करें। उन्होंने पार्टी कार्यकर्ताओं से यह सुनिश्चित करने को भी कहा कि रोजगार के लिए राज्य छोड़कर गए प्रवासी श्रमिक मतदान की अंतिम तिथि से पहले अपना वोट डालने के लिए वापस लौट आएं। उन्होंने कहा, ''अगर उन्हें मुस्लिम बूथ में 100 में से 99 वोट मिलते हैं, तो हमें सनातनी बूथ में 100 में से 100 वोट क्यों नहीं मिलने चाहिए?'' इस चुनाव को एक "राष्ट्रवादी और सनातनी सरकार" की स्थापना की लड़ाई बताते हुए अधिकारी ने कहा कि अगर प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी के तहत भाजपा सत्ता में आती है, तो वह राज्य में आयुष्मान भारत स्वास्थ्य योजना लागू करेगी, महिलाओं को 3,000 रुपये की वित्तीय सहायता प्रदान करेगी और योग्यता के आधार पर छह लाख सरकारी नौकरियां सृजित करेगी। उन्होंने मतदाताओं से राम नवमी के दिन राज्य में "परिवर्तन" लाने की शपथ लेने का आग्रह भी किया।

उत्तर प्रदेश: जल जीवन मिशन योजना में लापरवाही बरतने पर 26 कर्मियों के खिलाफ कार्रवाई, 12 निलंबित

लखनऊ, (भाषा) उत्तर प्रदेश के हर गांव में घर तक नल से जल पहुंचाने के लिए शुरू की गई जल जीवन मिशन परियोजना के कार्यों में लापरवाही बरतने के आरोप में 26 अभियंताओं के खिलाफ कार्रवाई की गई है। राज्य सरकार की ओर से जारी बयान के मुताबिक इन अभियंताओं के खिलाफ निलंबन, विभागीय कार्रवाई, कारण बताओ नोटिस जारी किए जाने जैसी कार्रवाइयां की गई हैं। अधिकारियों के मुताबिक हाल के दिनों में जल निगम कर्मियों के खिलाफ यह सबसे बड़ी कार्रवाई है। बयान के अनुसार ग्रामीण जलापूर्ति विभाग के अपर मुख्य सचिव अनुराग श्रीवास्तव ने अधिशासी अभियंता, सहायक अभियंता और कनिष्ठ अभियंता रैंक के 12 अभियंताओं को निलंबित कर दिया है। वहीं, चार अधिशासी अभियंताओं के खिलाफ विभागीय अनुशासनिक जांच कराने के निर्देश दिए हैं।

अगर मतदाता सूची में 30 लाख नाम शामिल होते हैं तो इसका श्रेय तृणमूल कांग्रेस को मिलेगा : ममता बनर्जी

दुबराजपुर (प. बंगाल), (भाषा) तृणमूल कांग्रेस प्रमुख ममता बनर्जी ने बृहस्पतिवार को दावा किया कि अगर विचाराधीन 60 लाख से अधिक लोगों के नामों में से लगभग 30 लाख नाम मतदाता सूची में शामिल हो जाते हैं तो इसका श्रेय उनकी पार्टी को मिलेगा। पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री बनर्जी ने बीरभूम जिले में एक चुनावी रैली को संबोधित करते हुए कहा कि तृणमूल कांग्रेस उन सभी लोगों के लिए कानूनी उपाय सुनिश्चित करेगी जिनके नाम मतदाता सूचियों से हटा दिए गए हैं। उन्होंने कहा, ''अगर विचाराधीन 60 लाख से अधिक नामों में से 29 से 30 लाख नाम मतदाता सूची में शामिल हो जाते हैं तो यह हमारी उपलब्धि है। हमारे अभियान और संघर्ष के कारण ही ये नाम सूची में आ पाए हैं, लेकिन मैं चाहती हूं कि सूची में 100 प्रतिशत नाम हों क्योंकि वे सभी वास्तविक मतदाता हैं।''

आत्महत्या विकल्प नहीं हो सकता?

आज जीवन की सबसे बड़ी कड़वी सच्चाई है कि जीवन में थोडी सी निराशा आई नहीं कि मानव आत्महत्या की ओर अग्रसर हो जाता है । क्या उसे आत्महत्या के आलावा अन्य विकल्प नहीं दिखता ताकि वह इस सोच से आगे बढ़ सके। हमारे समाज को भी इस ओर सोचना होगा कि अगर कोई बेरोजगार है या किसी समस्या से ग्रसित है तो उसे प्यार से आगे बढ़ने का संदेश दें जिससे वह उस निराशा समय से निकल सके। आज के तेज रफ्तार और प्रतिस्पर्धी दौर में मानसिक दबाव, असफलताओं का भय और अकेलेपन की भावना कई लोगों को भीतर से तोड़ रही है। ऐसे में आत्महत्या जैसे खतरनाक विचार मन में आना एक गंभीर सामाजिक और मानवीय संकट का संकेत है। यह केवल व्यक्तिगत कमजोरी नहीं, बल्कि हमारी सामाजिक संरचना, संवादहीनता और मानसिक स्वास्थ्य के प्रति उदासीनता का परिणाम भी है। देश में आत्महत्या के आंकड़े तो उपलब्ध नहीं है ? लेकिन आए दिन अखबारों में यह खबर दिल को झकझोर देती है।अधिकतर खबरें कॉलेज, किसान, व्यवसायी, बेराजगारी से ही आतीं हैं। कारण अलग अलग हो सकते हैं लेकिन शब्द एक ही आता है हताशा–निराशा? माना कि जीवन के संघर्ष में कुछ समय ऐसा आ जाता है कि जब चारों ओर से अंधेरा दिखाई देता है जो आगे का रास्ता अंधेरा बंद कर देता है। ऐसे में कही से एक आशा की किरण दिखाई दे जाये तो कुछ हद तक इन आत्महत्याओं पर रोक लग सकेगी। आज हम एक बात अच्छी तरह समझ लें कि यह काया जो हमें प्रकृतित्व से मिली है। वह अनमोल है इसे वयर्थ नहीं कर सकते जब हमें किसी को जीवन देने का अधिकार नहीं है तो जीवन खत्म करने का अधिकार कहां से मिल जाता है। अगर हम छात्र जीवन में हैं तो हमें बार बार असफलता हाथ लगती है तो क्या हम इस पर ही निराशा समझ लेंगे? नहीं बरन यह असफलता ही हमें सफलता की कुंजी देती है जिससे जीवन भर हम कभी असफलता की और नहीं देती? आज हम उन सफल महापुरुषों की ओर देखेंगे तो पता चलेगा कि उनके पीछे कितनी असफलताऐं जुड़ी है। अगर किसान है तो फसल नष्ट होने पर हम निराशा की ओर चले जाते हैं क्योंकि फसल के लिए लिया गया उधार हमें भार मालूम चलता है। ऐसा नहीं है कि अगर एक फसल चौपट हुई है तो जीवन का आधार कहीं से यानी जीवन जीना ही छोड़ दें नहीं हमें आगे बढना होगा । हमें किसान के साथ–साथ ऐसा भी कार्य करना होगा जिससे हमें एक सहायक कार्य भी करना होगा जो कि उसी खेती कार्य से जुड़ा होगा। इसके आलावा अन्य सरकारी सहायता पर ध्यान देना होगा। इसके अलावा हम व्यवसायी हो या बेराजगार हैं तो हमें निराशा की जरूरत नहीं है। जीवन एक संघर्ष है। इसे ऐसे ही जीना पड़ता है। यह दुनिया है टांका टांकी को एक कुम्हार के घड़े की तरह लें जिसे कुम्हार तैयार करते समय उसमें चोटें मारता है।

आत्महत्या नहीं–जीवन का चयन करें: यह समझना जरूरी है कि जीवन में कठिनाइयाँ स्थायी नहीं होतीं। हर अंधेरी रात के बाद सुबह होती है। लेकिन जब व्यक्ति निराशा के गहरे गर्त में होता है, तो उसे यही अंधेरा स्थायी लगने लगता है। ऐसे समय में सबसे अधिक आवश्यकता होती हैकृसमझ, सहानुभूति और संवाद की। परिवार, मित्र और समाज की भूमिका यहां अत्यंत महत्वपूर्ण हो जाती है। यदि कोई व्यक्ति असामान्य व्यवहार कर रहा है, खुद को अलग–थलग कर रहा है या बार–बार निराशा की बातें कर रहा है, तो इसे नजरअंदाज नहीं करना चाहिए। समय रहते संवेदनशील बातचीत, सहयोग और पेशेवर मदद किसी की जिंदगी बचा सकती है।सरकार और संस्थाओं को भी मानसिक स्वास्थ्य सेवाओं को सुलभ और सस्ता बनाना होगा। स्कूलों और कार्यस्थलों पर काउंसलिंग की व्यवस्था, जागरूकता अभियान और हेल्पलाइन सेवाओं को मजबूत करना समय की मांग है। मानसिक स्वास्थ्य को शारीरिक स्वास्थ्य जितना ही महत्व देना होगा। सबसे अहम बातकृहर व्यक्ति को यह समझना चाहिए कि वह अकेला नहीं है। कठिन समय में मदद मांगना कमजोरी नहीं, बल्कि साहस है। जीवन अनमोल है, और हर समस्या का समाधान संभव है, बस जरूरत है सही दिशा और सहयोग की।आइए, म सब मिलकर एक ऐसा समाज बनाएं जहां कोई भी व्यक्ति अकेलेपन और निराशा के कारण अपनी जिंदगी खत्म करने का विचार न करे। जीवन चुनें क्योंकि हर सुबह एक नई उम्मीद लेकर आती है। आज के तेज रफ्तार और प्रतिस्पर्धात्मक जीवन में मानसिक दबाव एक सामान्य वास्तविकता बन चुका है। पढ़ाई, नौकरी, पारिवारिक जिम्मेदारियां और सामाजिक अपेक्षाएंकृ इन सबके बीच व्यक्ति कई बार स्वयं को असहाय और अकेला महसूस करने लगता है। ऐसी परिस्थितियों में कुछ लोग आत्महत्या जैसे कठोर कदम के बारे में सोचने लगते हैं। लेकिन यह समझना अत्यंत आवश्यक है कि आत्महत्या किसी भी समस्या का समाधान नहीं बल्कि स्थायी पीड़ा का कारण है।आत्महत्या एक पल की निराशा का निर्णय होता है, जबकि जीवन अनगिनत संभावनाओं से भरा होता है। कठिनाइयां जीवन का हिस्सा हैं, और हर समस्या का कोई न कोई समाधान अवश्य होता है। जो आज असहनीय लग रहा है, वह समय के साथ हल्का हो सकता है। इतिहास गवाह है कि अनेक महान व्यक्तियों ने गहरे संघर्षों का सामना किया लेकिन उन्होंने हार नहीं मानी और अंततरू सफलता हासिल की।समाज में मानसिक स्वास्थ्य को लेकर अभी भी जागरूकता की कमी है। लोग अपनी भावनाओं को खुलकर व्यक्त नहीं कर पाते, जिससे अंदर ही अंदर तनाव बढ़ता जाता है। ऐसे में जरूरी है कि हम अपने आसपास के लोगों के प्रति संवेदनशील बनें, उनकी बातों को ध्यान से सुनें और उन्हें सहारा दें। परिवार और मित्रों का साथ किसी भी कठिन परिस्थिति में व्यक्ति को संभाल सकता है।शिक्षा संस्थानों और कार्यस्थलों को भी इस दिशा में सक्रिय भूमिका निभानी चाहिए। काउंसलिंग सेवाएं, तनाव प्रबंधन कार्यक्रम और सकारात्मक वातावरण व्यक्ति के मानसिक स्वास्थ्य को बेहतर बनाने में सहायक हो सकते हैं। सरकार और समाज दोनों को मिलकर ऐसे प्रयास करने होंगे जिससे लोग मानसिक समस्याओं को छिपाने के बजाय खुलकर बात कर सकें। यह याद रखना चाहिए कि जीवन अमूल्य है। हर अंधेरी रात के बाद सुबह होती है। निराशा के क्षणों में धैर्य रखना और सहायता मांगना कमजोरी नहीं, बल्कि साहस का प्रतीक है। यदि हम स्वयं या हमारे आसपास कोई व्यक्ति कठिन दौर से गुजर रहा है, तो उसे यह विश्वास दिलाना हमारी जिम्मेदारी है कि वह अकेला नहीं है। आत्महत्या नहीं, जीवन चुनेंकृ क्योंकि हर जीवन महत्वपूर्ण है और हर समस्या का समाधान संभव है। **सौरभ वार्ष्णेय**

आखिर क्यों देश भर में निरंतर लोकप्रिय हो रहा है विकास का उत्तर प्रदेश मॉडल

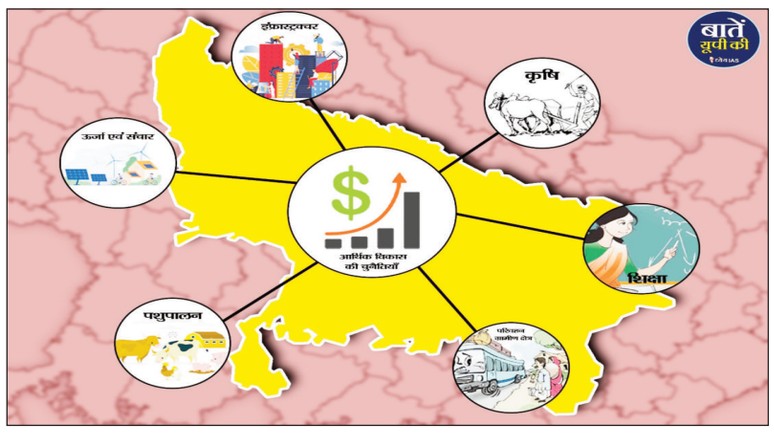

समय की सजीव सरगम में जब विकास की धारा दिशाओं को द्रुत गति से बदलती है, तब कुछ प्रदेश ऐसे होते हैं जो परिवर्तन के प्रतीक बन जाते हैं। उत्तर प्रदेश आज उसी परिवर्तन, प्रगति और प्रबंधन का पर्याय बनकर उभर रहा है। कभी पिछड़ेपन, बेरोजगारी और अव्यवस्था के लिए चर्चा में रहने वाला यह प्रदेश अब विकास, निवेश और नवाचार का केंद्र बनता जा रहा है। प्रश्न यह है कि आखिर ऐसा क्या हुआ कि "उत्तर प्रदेश मॉडल" देश भर में चर्चा, आकर्षण और अनुकरण का विषय बन गया है। इसका उत्तर केवल राजनीतिक विमर्श में नहीं बल्कि प्रमाणिक आँकड़ों, नीतिगत निर्णयों और जमीनी बदलावों में छिपा हुआ है। सबसे पहले यदि आर्थिक परिप्रेक्ष्य में इस परिवर्तन को समझें तो उत्तर प्रदेश की अर्थव्यवस्था ने पिछले वर्षों में उल्लेखनीय विस्तार किया है। राज्य के आर्थिक सर्वेक्षण 2025–26 के अनुसार वर्ष 2016–17 में जहाँ सकल राज्य घरेलू उत्पाद लगभग 13.30 लाख करोड़ रुपये था, वहीं यह बढ़कर 2024–25 में 30.25 लाख करोड़ रुपये तक पहुँच गया और 2025–26 में इसके 36 लाख करोड़ रुपये तक पहुँचने का अनुमान व्यक्त किया गया है, जो लगभग 10.8 प्रतिशत की चक्रवृद्धि वार्षिक वृद्धि दर को दर्शाता है। यह वृद्धि केवल संख्यात्मक नहीं, बल्कि संरचनात्मक है क्योंकि इसमें उद्योग, सेवा और कृषि तीनों क्षेत्रों का संतुलित योगदान शामिल है। प्रति व्यक्ति आय में भी उल्लेखनीय वृद्धि दर्ज की गई है। आर्थिक सर्वेक्षण के अनुसार यह आय 2016–17 के 54,564 रुपये से बढ़कर 2024–25 में 1,09,844 रुपये हो गई है । यह दोगुनी वृद्धि इस बात का संकेत है कि विकास का लाभ केवल आंकड़ों तक सीमित नहीं, बल्कि आम नागरिक तक पहुँच रहा है। यही कारण है कि उत्तर प्रदेश का विकास मॉडल "समावेशी विकास" के रूप में भी देखा जा रहा है। निवेश के क्षेत्र में उत्तर प्रदेश ने जो छलांग लगाई है, वह इस मॉडल की लोकप्रियता का प्रमुख कारण है। राज्य सरकार द्वारा प्रस्तुत आँकड़ों के अनुसार 50 लाख करोड़ रुपये से अधिक की निवेश पाइपलाइन तैयार की गई है । हाल ही में आयोजित निवेश सम्मेलनों और उनके फॉलोअप कार्यक्रमों के माध्यम से लाखों करोड़ रुपये के निवेश प्रस्तावों को धरातल पर उतारा गया है, जैसा कि समकालीन समाचार रिपोर्टों में उल्लेख किया गया है कि 7.5 लाख करोड़ रुपये की नई परियोजनाएँ प्रस्तावित हैं और पूर्व सम्मेलनों के माध्यम से लगभग 15 लाख करोड़ रुपये के निवेश को क्रियान्वित किया जा चुका है। यह निवेश केवल कागजों तक सीमित नहीं बल्कि औद्योगिक इकाइयों, रोजगार और उत्पादन में परिवर्तित होता दिखाई दे रहा है। औद्योगिक विकास की दृष्टि से भी उत्तर प्रदेश ने उल्लेखनीय प्रगति की है। हालिया रिपोर्टों के अनुसार राज्य में कारखानों की संख्या 30,000 से अधिक होने जा रही है और पिछले छह वर्षों में इसमें 800 प्रतिशत से अधिक वृद्धि दर्ज की गई है। यह वृद्धि दर्शाती है कि उत्तर प्रदेश अब केवल कृषि आधारित अर्थव्यवस्था नहीं, बल्कि औद्योगिक शक्ति के रूप में भी उभर रहा है। यमुना एक्सप्रेसवे औद्योगिक क्षेत्र में 3,400 करोड़ रुपये के निवेश और हजारों रोजगार सृजन जैसी परियोजनाएँ इस परिवर्तन को और अधिक सुदृढ़ करती हैं। अवसंरचना विकास इस मॉडल की रीढ़ है। उत्तर प्रदेश ने स्वयं को "एक्सप्रेसवे हब" के रूप में स्थापित किया है, जहाँ 22 एक्सप्रेसवे विकसित किए जा रहे हैं या निर्माणाधीन हैं। हालिया रिपोर्टों में यह भी उल्लेख किया गया है कि पिछले नौ वर्षों में 63,000 किलोमीटर से अधिक सड़कों का निर्माण और सुदृढ़ीकरण किया गया है तथा 35,000 किलोमीटर ग्रामीण सड़कों का निर्माण हुआ है। यह व्यापक नेटवर्क न केवल परिवहन को सुगम बनाता है, बल्कि उद्योग, पर्यटन और व्यापार को भी गति देता है। विमानन और लॉजिस्टिक्स के क्षेत्र में भी उत्तर प्रदेश तेजी से आगे बढ़ रहा है। राज्य में 24 हवाई अड्डों के विकास की योजना, जिसमें पाँच अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे शामिल हैं, इसे वैश्विक संपर्क का केंद्र बना रही है। 28 मार्च 2026 से प्रचालन शुरू किए जाने वाले नोएडा अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डा और डिफेंस इंडस्ट्रियल कॉरिडोर जैसी परियोजनाएँ इसे रणनीतिक और आर्थिक दृष्टि से महत्वपूर्ण बना रही हैं। कृषि क्षेत्र, जो उत्तर प्रदेश की अर्थव्यवस्था की आत्मा है, उसमें भी महत्वपूर्ण सुधार हुआ है। राज्य देश का सबसे बड़ा खाद्यान्न उत्पादक है और राष्ट्रीय उत्पादन में लगभग 20.6 प्रतिशत का योगदान देता है)। दूध उत्पादन में भी इसका योगदान 15.66 प्रतिशत है, जो इसे इस क्षेत्र में अग्रणी बनाता है। सिंचाई क्षेत्र के विस्तार और फसल विविधीकरण के कारण कृषि उत्पादकता में वृद्धि हुई है, जिससे किसानों की आय में सुधार हुआ है। कानून व्यवस्था में सुधार भी उत्तर प्रदेश मॉडल की लोकप्रियता का एक महत्वपूर्ण कारण है। हालिया रिपोर्टों में यह उल्लेख किया गया है कि राज्य में शांति, सुरक्षा और विश्वास का वातावरण विकसित हुआ है, जिससे निवेशकों का भरोसा बढ़ा है। बेहतर कानून व्यवस्था के कारण उद्योगों और व्यापारिक गतिविधियों को स्थिरता मिली है, जो आर्थिक विकास के लिए आवश्यक है। डिजिटल शासन और पारदर्शिता भी इस मॉडल की विशेषता है। डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर (डीबीटी) के माध्यम से योजनाओं का लाभ सीधे लाभार्थियों तक पहुँचाया जा रहा है। हाल ही में 90,000 लाभार्थियों को 900 करोड़ रुपये सीधे उनके खातों में हस्तांतरित किए गए। इससे भ्रष्टाचार में कमी आई है और शासन की विश्वसनीयता बढ़ी है। रोजगार सृजन के क्षेत्र में भी उल्लेखनीय प्रयास किए गए हैं। रिपोर्टों के अनुसार 2017 से अब तक 13.45 लाख युवाओं को रोजगार मेलों के माध्यम से निजी क्षेत्र में रोजगार उपलब्ध कराया गया है। इसके अतिरिक्त विदेशी रोजगार के अवसरों से भी राज्य के युवाओं को जोड़ा गया है, जिससे उनकी आय और कौशल दोनों में वृद्धि हुई है। विश्व के विभिन्न देशों में उत्तर प्रदेश के कुशल श्रमिकों की मांग निरंतर बढ़ रही है। सामाजिक क्षेत्र में भी सुधार देखने को मिला है। स्वास्थ्य बजट में वृद्धि, चिकित्सा संस्थानों का विस्तार और शिक्षा के क्षेत्र में निवेश ने मानव विकास सूचकांकों में सुधार किया है। यह दर्शाता है कि विकास केवल आर्थिक नहीं बल्कि सामाजिक भी है।उत्तर प्रदेश मॉडल की लोकप्रियता का एक और कारण है "डबल इंजन सरकार" का समन्वय। केंद्र और राज्य सरकारों के बीच तालमेल के कारण योजनाओं का प्रभावी क्रियान्वयन संभव हुआ है, जिससे विकास की गति तेज हुई है। हालाँकि, इस मॉडल की कुछ आलोचनाएँ भी हैं, जिन्हें नजरअंदाज नहीं किया जा सकता। कुछ विशेषज्ञों का मानना है कि तेजी से औद्योगिकीकरण के साथ पर्यावरणीय संतुलन और क्षेत्रीय असमानताओं पर भी ध्यान देना आवश्यक है। इसके अतिरिक्त, प्रति व्यक्ति आय अभी भी राष्ट्रीय औसत से कम है, जो यह संकेत देता है कि विकास की यात्रा अभी अधूरी है। फिर भी, यह तथ्य अस्वीकार्य नहीं है कि उत्तर प्रदेश ने विकास के क्षेत्र में एक नई दिशा प्रस्तुत की है और पिछले 9 वर्षों में उल्लेखनीय बहुआयामी प्रगति की है। यह मॉडल केवल आर्थिक वृद्धि तक सीमित नहीं, बल्कि यह प्रशासनिक सुधार, तकनीकी नवाचार, सामाजिक समावेशन और निवेश आकर्षण का समन्वित रूप है। अंततः यह कहा जा सकता है कि उत्तर प्रदेश मॉडल की लोकप्रियता का मूल कारण उसका बहुआयामी स्वरूप है। यह केवल आंकड़ों की चमक नहीं, बल्कि जमीनी बदलाव की सच्चाई है। यह मॉडल बताता है कि यदि नीति, नियत और प्रयास में संतुलन हो, तो कोई भी प्रदेश पिछड़ेपन से प्रगति की पराकाष्ठा तक पहुँच सकता है। समय की सशक्त सीख यही है कि विकास केवल योजनाओं से नहीं, बल्कि उनके प्रभावी क्रियान्वयन से आता है। उत्तर प्रदेश का अनुभव इस बात का प्रमाण है कि जब शासन, समाज और संसाधनों का समुचित समन्वय होता है, तब विकास केवल लक्ष्य नहीं, बल्कि वास्तविकता बन जाता है। यही कारण है कि आज देश भर में उत्तर प्रदेश मॉडल चर्चा, प्रेरणा और अनुकरण का केंद्र बनता जा रहा है। डॉ. शैलेश शुक्ला

देसी घी एवं दूध पाउडर में नरमी लिए ठहराव

नई दिल्ली, (एनएनएस) गत सप्ताह लिक्विड दूध की आपूर्ति घटने के बावजूद भी घरेलू निर्यात मांग अनुकूल नहीं होने से देसी घी एवं दूध पाउडर में पूर्ववत नरमी बरकरार रही। आगे मौसम एवं खपत को देखते हुए रुक रुक कर इसमें 10 किलो की बढ़त के आसार बन गए हैं। आलोच्य सप्ताह उत्तर भारत की कंपनियों में लिक्विड दूध की आपूर्ति 35 लाख लीटर घटकर 1.35/1.40 लाख लीटर दैनिक रह गई, क्योंकि होली के बाद ईद हेतु मक्खन में स्टॉकिस्टों की पकड़ मजबूत होने से देसी घी का उत्पादन घट गया, लेकिन देसी घी में ग्राहकी कमजोर होने से कंपनीयां देसी घी के प्रीमियम क्वालिटी के 9100/9425 रुपए प्रति टीन से पर सुस्त बोल रही हैं। उपभोक्ता पैक में भी खपत अच्छी रही है। इधर मक्खन के भाव भी इसी अनुपात में तेज बोले गए। कंपनियां एवं स्टॉकिस्ट भी मक्खन का स्टॉक करने लगी है, जिस कारण अतिरिक्त खपत लिक्विड दूध की 22–23 प्रतिशत बढ़ गई। हल्के माल भी ऊपर में 7800/8000 रुपए प्रति टीन से कम में बेचू नहीं आ रहे हैं। लिक्विड दूध की आपूर्ति कम के प्रभाव से छोटी बड़ी कंपनियों को खरीद में काफी मशक्कत करनी पड़ रही हैं। अब लिक्विड दूध 60/62 रुपए लीटर क्वालिटी के अनुसार बिकने लगा है। इधर दूध पाउडर दक्षिण भारत की कंपनियों में इस बार स्टॉक में कम है तथा उत्तर भारत में ऊंचे भाव होने से फेडरेशन भी खरीद कम कर पाए हैं, इस वजह से तमिलनाडु महाराष्ट्र में दूध पाउडर के भाव 280/290 रुपए प्रति किलो के बीच बिक रहे हैं। फलतः उत्तर दक्षिण का अंतर कम हो जाने से इस बार यहां माल की कमी बनी हुई है। अंतर्राष्ट्रीय बाजारों में भी ऊंचे भाव चल रहे हैं, जिस कारण निर्यात भी हो रहा है, इन परिस्थितियों में आगे कुछ दिनों में ही दूध पाउडर में तेजी के आसार बन गए हैं।

उत्पादन व स्टॉक अधिक होने से गेहूं में मंदे का दलदल, किन्तु मंदा रुकने के आसार

नई दिल्ली, (एनएनएस) गेहूं का स्टॉक सरकारी व गैर सरकारी गोदामों में अधिक होने तथा नया माल आने से चौतरफा भी बिकवाली का प्रेशर बन गया है, जिसके चलते लुढक कर यहां गेहूं पानी–पानी हो गया है। आज 25/30 रुपए की और गिरकर आ गई। देश में गेहूं की बिजाई अधिक होने के साथ–साथ मौसम अनुकूल रहने से उत्पादन अनुमान 1150 लाख मैट्रिक टन का आने लगा है, जो गत वर्ष 1090 लाख मैट्रिक टन के करीब व्यापारियों द्वारा अनुमान लगाया जा रहा है। दूसरी ओर पुराना स्टॉक सरकारी व गैर सरक. ारी गोदामों में भारी मात्रा में होने से बिकवाली का चौतरफा प्रेशर बन गया है। जिस कारण एक महीने के अंतराल 200 रुपए तथा आज 25/30 रुपए लुढक़कर मिल क्वालिटी गेहूं 2600/2625 रुपए प्रति क्विंटल यहां रह गया है। पिछले दिनों एक बड़ी रोलर फ्लोर मिल ने काफी मंदे भाव में फुल अप्रैल का माल 2560 रुपए प्रति क्विंटल पहुंच में खरीद चुकी है, इसे देखकर इन भाव में स्टाक के लिए कोई भी रोलर उपयोग मिल नहीं खरीद रही है, केवल जरूरत का व्यापार है। उधर बिहार में अलग–अलग रोलर फ्लोर मिलों में 2500/2550 रुपए पहुंच में गेहूं मिलने लगा है। वहां 2400/2425 रुपए बोलने लगे हैं, मध्य प्रदेश में भी मंदा चल रहा है, इन परिस्थितियों में गेहूं तेज नहीं लग रहा है। हालांकि जिस तरह आज मौसम दिल्ली में खराब हुआ है, इस तरह उत्पादक मंडियों में होने पर तैयार फसल थोड़ा लेट जरूर हो जाएगी लेकिन अभी 80 प्रतिशत क्षेत्रों में वर्तमान बरसात से गेहूं के लाभ ही मिलने वाला है। हम मानते हैं कि इस महीने के अंत तक यूपी हरियाणा का भी नया गेहूं आ जाएगा, लेकिन फुल प्रेशर अप्रैल में ही बन पाएगा। गौरतलब है कि गेहूं का बिजाई क्षेत्र में भी वृद्धि हुई है तथा अभी तक मौसम अनुकूल बना हुआ है। उत्पादक क्षेत्रों में फसल बहुत बढिया बताई जा रही है, मध्य प्रदेश में गेंहू की कटाई जोरों पर चल रही है, जबकि हरियाणा पंजाब यूपी में फसल के अंदर तैयार होने वाली है। सरकार द्वारा गत वर्ष केंद्रीय पूल में गेहूं की खरीद 299.7 लाख मीट्रिक टन की गई थी, जिसमें मुक्त वितरण एवं टेंडर में भी ज्यादा गेहूं नहीं निकल पाया है, इसे देखकर सरकार द्वारा टेंडर भी बंद कर दिया गया है, क्योंकि यूपी हरियाणा राजस्थान पंजाब बिहार में गेहूं के भाव 2500/2550 रुपए प्रति क्विंटल में उपलब्ध हो रहा है। ग्रामीण क्षेत्रों में भी किसानों का गेहूं 2350/2400 रुपए के बीच छोटे कारोबारी सप्लायर मांगने लगे हैं। दिल्ली में 2600/2625 रुपए प्रति क्विंटल बिक रहा हैं, जो गत वर्ष इन दोनों 3000 रुपए था। आटा मैदा सूजी के भाव भी 200/250 रुपए प्रति 50 किलो गत वर्ष की अपेक्षा नीचे चल रहे हैं। यहां जो आटा इन दिनों 1750 रुपए बिका था उसके भाव 1490/1500 रुपए प्रति 50 किलो रह गए हैं। गत वर्ष गेहूं का न्यूनतम समर्थन मूल्य 2425 रुपए था, जो वर्ष 2026–27 विपणन वर्ष के लिए सरकार द्वारा 2585 रुपए प्रति क्विंटल कर दिया गया है। गेहूं की केंद्रीय पूल में सकल खरीद 350 लाख मिट्रिक टन को पार कर जाएगी।

मसूर–7000 रुपए बिकना संभव

नई दिल्ली, (एनएनएस) मसूर की बिजाई अधिक होने के बावजूद भी अक्टूबर में प्रतिकूल मौसम होने से सकल उत्पादन में कमी आ गई है। यही कारण है कि उत्पादक मंडियों में आपूर्ति नहीं बढने से यहां तेजी का रुख बना हुआ है। गत दो दिनों में 200 रुपए बढ़ गए हैं तथा जल्दी 400 रुपए और बढ़ जाने के आसार बन गए हैं। मसूर की शत–प्रतिशत फसल आ चुकी है तथा गत वर्ष की अपेक्षा इन दिनों 22–23 प्रतिशत आवक मुंगावली गंज बासौदा सागर भोपाल बीनागंज लाइन में कम हो रही है। हालांकि गत वर्ष भी उत्पादन कम ही हुआ था, लेकिन इस बार बिजाई अधिक होने के बावजूद भी स्कूल मौसम से उत्पादन गत वर्ष के बराबर मुश्किल से बैठेगा, लेकिन पुराना स्टॉक इस बार मुश्किल से 50–60 हजार बोरी देसी माल का सारी मंडियों को मिलाकर बचा है। इसके अलावा अंतरराष्ट्रीय बा. जारों में ऊंचे भाव होने तथा डॉलर की तुलना में रुपया कमजोर पडने से आयात इस बार महंगा पड़ रहा है। हम मानते हैं कि कनाडा की मसूर, देसी मोटी की बजाय सस्ती पड़ रही है तथापि आगे जिस भाव के सौदे हो रहे हैं, उस भाव में यहां काफी महंगा जाकर पड़ेगा। फिलहाल उत्पादन, खपत की तुलना में कम होने से बिल्टी में मसूर 2 दिन के अंतराल 200 रुपए और बढक़र 6600 रुपए प्रति क्विंटल हो गई। कनाडा के माल भी 6000 रुपए से ऊपर बोलने लगे हैं। मलका व दाल की घरेलू खपत निर्यात हेतु देसी मसूर की बढिया होती है तथा मुंगावली गंज बासौदा सागर भोपाल बीनागंज एवं अशोक नगर लाइन में मोटी नयी मसूर का प्रेशर नहीं बन पा रहा है। इस वजह से आने वाली फसल भी 18–19 लाख मैट्रिक टन से अधिक होने का अनुमान नहीं है, जबकि घरेलू खपत 30 लाख मीट्रिक टन की है। इस बार छोटी मसूर गोंडा बहराइच लाइन से लेकर बिहार के चनपतिया फतुहा बख्तियारपुर लाइन में अधिक बोई गई थी, क्योंकि किसानों ने छोटी मसूर के भाव काफी ऊंचे देख चुके हैं। छोटी मसूर इस बार कोटा बूंदी लाइन में भी अधिक हुई है, मोटी मसूर के बिजाई क्षेत्र में बहुत ज्यादा वृद्धि थी, लेकिन बिजाई के समय में मौसमी बरसात से सकल उत्पादन अपेक्षाकृत अधिक नहीं है। छोटी मसूर में बीते वर्ष वाले भाव दिखाई नहीं देंगे, जबकि मोटी मसूर, डॉलर महंगा होने एवं अंतर्राष्ट्रीय बाजारों में आयात पड़ते ऊंचे होने से और तेजी लग रही है। भारतीय बंदरगाहों पर 5700/5710 रुपए प्रति कुंतल के भाव चल रहे हैं। यहां उन मालों के भाव 6000/6050 रुपए चल रहे हैं। नई मसूर 200 रुपए दो दिनों में बढक़र 6600 रुपए प्रति कुंतल मुंगावली लाइन की बिक रही है, इसमें भी 300 रुपए से रुपए और बढ़ जाने के आसार बन गए है, पुरानी देसी मसूर गोदाम में पूरी तरह समाप्त हो गई है, इधर खपत वाली मंडियों में भी कारोबारी माल लेकर नहीं चल रहे थे, इस वजह से मोटी मसूर मुश्किल से 100 रुपए का करेक्शन आ सकता है। अतः 6600 रुपए की देशी मोटी मसूर आगे चलकर 400 रुपए का लाभदायक लाभ दे जाएगी।

काबुली चने के मंदे वाले भाव ढूंढते रह जाओगे

नई दिल्ली, (एनएनएस) काबुली चने में कारोबारी सन्नाटा छाया हुआ था, जो 2–3 दिनों से थोड़ी सी पूछ परख आते ही मजबूती बन गई है। पूर्व में जितना फसल का अनुमान लगाया गया था, उतना नहीं है। यही कारण है कि बाजार दो–तीन रुपए किलो बढ़ गया है तथा मंडियों में आवक को देखते हुए वर्तमान व्यापार में भरपूर लाभ दे जाएगा। काबुली चने की बिजाई अक्टूबर के दूसरे पखवाड़े में इस बार हुई थी, जो पीछे लगातार बरसात से जर्मिनेशन कम हुआ था, क्योंकि उस समय काबुली चने के बोए हुए क्षेत्र में बीज ही नष्ट हो गया, यही कारण है कि मार्च का दूसरा पखवाड़ा चल रहा है तथा मंडियों में माल का प्रेशर कहीं भी नहीं है। हां, यह बात सही है कि पुराना माल इस बार ज्यादा बचा है। गत वर्ष काबुली चने का उत्पादन 31 लाख मैट्रिक टन हुआ था, वह इस बार मुश्किल से 18–20 लाख मैट्रिक टन रह जाने की अटकलें लगाई जाने लगी हैं। गत वर्ष नया पुराना मिलाकर काबुली चने का स्टॉक 36 लाख मीट्रिक टन की उपलब्धि रही। वह इस बार 24 लाख मीट्रिक टन नया पुराना मिलाकर वर्तमान में अनुमान लगाया जा रहा है। अंतरराष्ट्रीय बाजारों में ऊंचे भाव होने से इस बार निर्यात के पड़ते हमारे लगेंगे तथा आयात नहीं होगा। पिछले दिनों आने–पौने भाव में बढिया तथा मोटा एक दो प्रतिशत डंक वाला काबुली चना 90 प्रतिशत निबट चुका है तथा नया माल आ रहा है, लेकिन किसी भी मंडी में माल का प्रेशर नहीं है। गौरतलब है कि सीजन के शुरुआत में जो काबली चना 71/72 रुपए कच्चा माल बिका था, उसके भाव नीचे में 57/60 रुपए प्रति किलो पिछले सप्ताह रह जाने के बाद दो–तीन दिन से थोड़ी सी ग्राहकी सुधरने से उसके भाव 60/62 रुपए बोलने लगे हैं, बढिया महाराष्ट्र का बिना छना माल 64 रुपए तक बिक गया है। इस बार महाराष्ट्र में फसल लेट और कम आई है, क्योंकि वहां बिजाई देर तक हुई है। बाजारों में रुपए की काफी तंगी से जितना मंदा आना था, वह आ चुका है। अब वर्तमान भाव से किसी भी देश से पड़ता नहीं लग रहा है। उधर इजिप्ट के देशों में काबुली चने काफी निपट चुके हैं। फिलहाल वहां इजरायल ईरान अमेरिका लड़ाई से अभी निर्यात नहीं है, लेकिन लड़ाई बंद होने के बाद पाइपलाइन में माल नहीं रहेगा, इसलिए चौतरफा मांग निकल जाएगी। इसके अलावा हमारा माल चालू माह में टेंडर में काफी खप गया है। गौरतलब है कि ग्राहकी का बाजारों में पूरी तरह सन्नाटा पिछले सप्ताह तक रहा, यहां बाजार धीरे–धीरे सुधर रहा है। यहां उत्पादक मंडियों की अपेक्षा भाव नीचे चल रहे हैं, इसलिए वर्तमान भाव में भरपूर लाभ मिलने की संभावना है ।

सोयाबीन 7000 एवं रिफाइंड 150 रुपए प्रति किलो बिकने की उम्मीद

नई दिल्ली, (एनएनएस) सोयाबीन का उत्पादन कम होने तथा अंत. रराष्ट्रीय बाजारों में खाद्य तेलों के ऊंचे भाव होने से बाजार सीजन से अब तक 20/22 रुपए प्रति किलो बढ़ गए हैं और इन भावों में भविष्य में 10 रुपए की और तेजी लग रही है। अब मंडियों में सोयाबीन की आपूर्ति टूट गई है। अतः यहां से और लाभदायक लग रहा है। सोयाबीन में पिछले 10 दिनों के अंत. राल 200/250 रुपए प्रति कुंतल की तेजी पर एमपी में प्लांट पहुंच 5800/5850 रुपए, कोटा में 6050/6100 रुपए एवं महाराष्ट्र में 6150/6200 प्रति कुंतल हो गए हैं। अंतरराष्ट्रीय बाजारों में खाद्य तेलों के भाव बढने से यहां भी इसमें 20/22 रुपए प्रति किलो गत डेढ़ माह में प्रति टन की और गिरावट बढक़र 145/146 रुपए एक्स प्लांट में हो गया। इटारसी इंदौर नागपुर लाइन में कच्चे मालों की आपूर्ति प्लांटों में काफी घट गई है। दूसरी ओर अंतरराष्ट्रीय बाजारों से आने वाले पॉम आयल काफी महंगे मिल रहे हैं। ईरान इजरायल लड़ाई के चलते समुद्री मार्ग पूरी तरह बाधित हो गया है। देश में सोयाबीन का उत्पादन कम रहा है, इन परिस्थितियों में तेल सोया रिफाइंड 150 रुपए एक्स प्लांट बन सकता है। इसी तरह सोया डीओसी कोटा लाइन में 43000 रुपए एवं नीमच दतिया सुजालपुर लाइन में 42000/42500 रुपए प्रति टन भाव हो गई हैं। सोयाबीन अक्टूबर नवंबर में मध्य प्रदेश राजस्थान महाराष्ट्र के अलग–अलग प्लांट में नीचे में 40/42 रुपए प्रति किलो तक थोक में प्लांट पहुंच में बिक गई थी, जो वर्तमान में क्वालिटी अनुसार 59/62 रुपए ऊपर में हो गई है तथा इसकी डीओसी भी चालू माह के अंतराल ऊपर 3 हजार रुपए प्रति टन बढ़ गई है। वास्तविकता यह है कि भारतीय बंदरगाहों से शिपमेंट वाले अधिकतर स्टीमर निकल चुके हैं तथा नए स्टीमर के लिए अभी बर्थ नहीं मिल रहा है, क्योंकि ईरान इजरायल युद्ध चल रहा है तथा निर्यात सौदे भी अब एफओबी में ही ज्यादा हो रहे हैं, उनकी शिपमेंट धीमी चल रही है। इस वजह से निर्यातकों की मांग डीओसी में पड़ते से काफी ऊपर भाव बोलने लगे हैं। इधर व्यापार इंदौर इटारसी नागपुर औरंगाबाद आदि राज्यों के प्लांटों में सोया रिफाइंड तेज हो जाने से सोयाबीन की क्रशिंग बढ़ गई है। इधर कच्चे एवं तैयार दोनों ही मालों की कमी बन गई है। गौरतलब है कि सोयाबीन का उत्पादन इस बार 100–102 लाख मैट्रिक टन के करीब रह गया है, जो 135–136 लाख मैट्रिक टन के करीब विगत के वर्षों में हुआ है, इस वजह से इस बार किसानों के पास सोयाबीन का स्टॉक नहीं है। अब जो भी माल है, कच्ची मंडियों के स्टॉकिस्टों एवं सॉल्वेंट प्लांटों में ही है। उधर अंतर्राष्ट्रीय बाजारों में खाद्य तेलों की बिकवाली ऊंचे भाव में हो रही है, डॉलर महंगा होने से ज्यादा व्यापार नहीं हुआ है। इधर अंतरराष्ट्रीय बाजारों में सोया डीओसी के जो भाव घटे थे, उन भावों में फिर से एक सप्ताह से भारतीय निर्यातकों की लिवाली आने लगी है, इन परिस्थितियों में बाजार यहां से और बढने की संभावना दिखाई दे रहा है। अतः भविष्य में सोयाबीन 7000 रुपए प्रति क्विंटल, तेल सोया रिफाइंड 150 रुपए प्रति किलो एक्स प्लांट एवं डीओसी 55000 रुपए प्रति टन पहुंचने की संभावना है।

युद्ध से गोंद में और तेजी के आसार

नई दिल्ली, (एनएनएस) देसी गोंद का उत्पादन इस बार कम हुआ है तथा ईरान इजरायल युद्ध से गोंद का आयात घट गया है। इसके अलावा ऊंचे भाव होने के साथ साथ माल आने में रिस्क होने से आयातक सौदे कम किए हैं। इधर सर्दी मौसम ठंडा होने से लोकल एवं चालानी मांग निकलने लगी है। जिस कारण चालू माह में 20/25 रुपए प्रति किलो की तेजी आ गई है। अभी आगे खपत और रहने वाली है तथा पड़ते से भाव अंतर्राष्ट्रीय बा. जारों में ऊंचे हो गए हैं, इसलिए बाजार 30/40 रुपए और बढ़ सकता है। गोंद का उत्पादन मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ महाराष्ट्र में मुख्य रूप से होता है। इस बार गोंद तैयार होने के समय में अधिक बरसात हुई है। दूसरी ओर नक्सलवाद को सफाई करने के लिए घने जंगलों में अभियान जोरों पर चलाया जा रहा है। यही कारण है कि शिवपुरी, श्योपुर कला, बिलासपुर के साथ–साथ जगदलपुर बस्तर सुकमा एवं महाराष्ट्र के सभी घने जंगलों से गोंद की निकासी कम रही है। दूसरी ओर सूडान नाइजीरिया एवं चाड में गोंद का उत्पादन कम होने तथा वहां से निर्यात मांग जोरों पर चलने से वहां भाव काफी ऊंचे हो गए हैं। इस वजह से जो सकोटो पैक माल यहां 90/100 रुपए प्रति किलो बिक रहा था, उसके भाव 130/135 रुपए हो गए हैं। हम मानते हैं कि दिसंबर में 65/70 कंटेनर और गोंद भारतीय बंदरगाहों पर उतरने वाले हैं, इन सबके बावजूद भी पहले के आए माल बिक जाने तथा खाद्य पदार्थ निर्माता कंपनियों की चौतरफा एवरेज माल की लिवाली चलने से बाजार बढ़ता जा रहा है।

बासमती चावल में करेक्शन के बाद रूक रूक कर तेजी

नई दिल्ली, (एनएनएस) बासमती चावल की सभी प्रजातियों में तीन–चार दिनों में उपर के भाव से इसमें 300 रुपए प्रति कुंतल की गिरावट आ गई है। वर्तमान में निर्यातकों की फिर पूछपरख से तथा धान महंगा होने से राइस मिलें घटाकर चावल के बिकवाल नहीं हैं। इस समय में निर्यात सौदे कम हो रहे हैं, लेकिन उत्पादक मंडियों में धान मिलना मुश्किल हो गया है। आगे तेजी मंदी जंग पर निर्भर करेगा। चालू सीजन में धान की रोपाई के समय ही बाढ़ एवं बरसात का तांडव रहा तथा जब फसल तैयार होने को हुई, उस समय भी लगातार बरसात होने से उत्पादन का समीकरण पूरी तरह बिगड़ गया। यही कारण है कि उत्पादन में भारी कमी आ गई है। पंजाब हिमाचल तथा हरियाणा के लगते क्षेत्रों में बाढ़ व बरसात से पंजाब में 24–25 प्रतिशत धान की फसल को नुकसान हो गया था। अब हरियाणा में भी 13–14 प्रतिशत का नुकसान बताया जा रहा है, जिस कारण फसल से ही 1509 सहित सभी प्रजाति के धान व चावल में पिछले दिनों भारी तेजी आ गई थी। तत्पश्चात जनवरी के तीसरे सप्ताह से ही राइस मिलों को धान नहीं मिलने एवं निर्यातकों की प्रतिस्पर्धात्मक खरीद से चावल 1718 सेला काफी ऊपर नीचे चल रहे हैं। इसी अनुपात में चावल 1509 सेला के भाव भी 7300/7400 रुपए चालू सप्ताह में ऊपर के भाव से थोड़ा नीचे आ गया है, लेकिन बिकवाली का प्रेशर नहीं है। पिछले डेढ़ माह में 1401 चावल स्टीम के भाव भी 8600 से गिरकर 7800/8000 रुपए प्रति क्विंटल नीचे आ गया है। राइस मिलों में धान एवं चावल दोनों की कमी बनी हुई है तथा दूसरे देशों के लिए निर्यातकों के पास सौदे काफी पेंडिंग में पड़े हुए हैं। अतः जब भी निर्यातकों की खरीद आएगी, बाजार में उछल जाएगा। इधर जंडियाला गुरु, अमृतसर, तारांतरण मंडी में 1718 धान के भाव 4350/4400 रुपए हो गए हैं। तरावड़ी कैथल टोहाना सफीदों चीका मंडी में धान के भाव 4300/4375 रुपए प्रति कुंतल के बीच नमी व लेंथ के हिसाब से बोल रहे हैं। यूपी के दादरी उझानी बहजोई जहांगीराबाद बरेली लाइन में क्वालिटी अनुसार धान के भाव 4200/4250 रुपए प्रति कुंतल हो गए हैं। इस बार निर्यात सौदे एवं राइस मिलों में मिलिंग पड़ता को देखते हुए हर धान एवं चावल में भरपूर लाभ मिलने की संभावना दिखाई दे रही है।

आपूर्ति की कमी से हैसियन में तेजी जारी

नई दिल्ली, (एनएनएस) सप्लाई में कमी आने तथा उठाव बढने से गत सप्ताह के दौरान बारदाना बाजार में हैसियन की कीमतों में 100/200 रुपए प्रति 91.4 मीटर की वृद्धि हुई। बिकवाली में कमी से सुतली व पुराने बारदाने की कीमतों में मजबूती का रुख बन गया। हैसियन में तेजी का रुख होने तथा आपूर्ति कमजोर होने व हरियाणा–पंजाब एवं लोकल की मांग बढने से हैसियन 50/100 रुपए बढक़र 38–6.5 के भाव 3650 रुपए तथा 40–8.12 साईज के भाव 5000 रुपए, 44–5.5 के भाव 3500 रुपए तथा 44–8.12 साईज के भाव 5300 रुपए प्रति 91.4 मीटर हो गये।

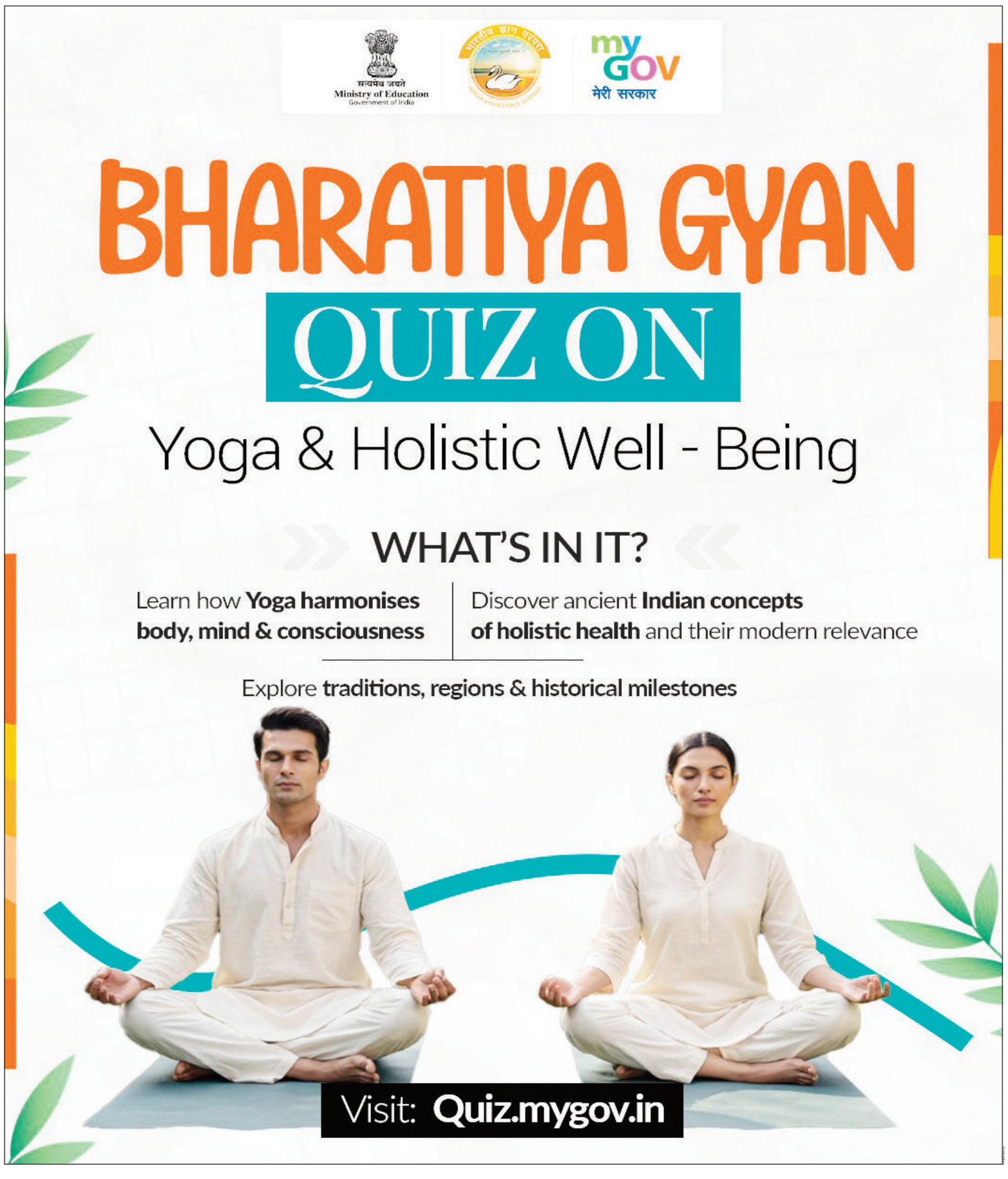

C R Patil chairs Consultative Committee meeting on Jal Jeevan Mission

New Delhi, Focus News: A meeting of the Consultative Committee of the Ministry of Jal Shakti was held on 24th March 2026 under the chairpersonship of Union Minister for Jal Shakti, Shri C. R. Patil, at his residence. The Minister of State for Jal Shakti, Shri V. Somanna and Shri Raj Bhushan Choudhary also attended the meeting. The meeting included a detailed presentation (PPT) on the progress, impact, and future roadmap of the Jal Jeevan Mission (JJM). During the meeting, members were apprised of the significant achievements of the Jal Jeevan Mission in ensuring drinking water security in rural India. Access to safe drinking water has contributed to reducing water-borne diseases such as diarrhoea, cholera, and typhoid, while also improving child health, nutrition, and school attendance. It was also apprised that the Union Cabinet has approved the extension of Jal Jeevan Mission till December 2028, with an enhanced outlay of ₹ 8.69 lakh crore. The restructured JJM 2.0 aims to move beyond infrastructure towards sustainable, reliable, and quality service delivery. **Some important Key reform areas highlighted during the meeting include:** Establishing Digital Data Governance in Rural Drinking Water Supply Systems: Development of a national digital public infrastructure – "Sujalam Bharat"

Utility based approach for drinking water service delivery

Strengthening community-led governance through Gram Panchayats

Institutionalisation of water quality monitoring and citizen engagement

Ensuring financial sustainability and O&M systems

Strengthening technical capacity at district level through District Technical Units (DTUs) as continuous support

Source Sustainability and Water Security Framework

Shift from event-based mobilisation to structured participatory governance through 'Jan Bhagidari'

Capacity Building Framework for continuous service improvement

The Ministry has initiated the process of signing Memorandum of Understanding (MoUs) with States/UTs, with 11 States already on board. States have also been requested to submit financial proposals for implementation of JJM 2.0.

Key Highlights:

The Mission has shifted focus from infrastructure creation to service delivery, ensuring a minimum of 55 litres per capita per day (LPCD) of potable water supply.

Coverage has been expanded from habitation-based to household-level access, ensuring tap water connections to every rural household.

As of March 2026, 15.82 crore (82%) rural households have been provided with Functional Household Tap Connections (FHTCs), compared to 3.23 crore (17%) in 2019, reflecting nearly a five-fold increase.

Over 28 lakh km of pipelines and millions of assets have been digitally mapped and geo-tagged, strengthening transparency and monitoring.

Jan Bhagidari and Communication Strategy: Community participation is being strengthened through initiatives such as "Jal Arpan," "Jal Utsav," and "Jal Sankalp." Awareness campaigns are being carried out through school curricula, community radio, and digital platforms to ensure greater public engagement and ownership.

Members of the Consultative Committee shared valuable suggestions during the meeting, which shall be duly considered by the Ministry. The Union Minister called for collective efforts from all stakeholders to achieve the goal of "Har Ghar Jal" in a time-bound and sustainable manner.

Cabinet approves Continuation of the Immigration, Visa, Foreigners Registration & Tracking (IVFRT) Scheme

New Delhi, Focus News: The Union Cabinet chaired by the Prime Minister Shri Narendra Modi has approved the continuation of the Immigration, Visa, Foreigners Registration & Tracking (IVFRT) Scheme beyond 31 March, 2026 for a period of five year from 01 April, 2026 to 31 March, 2031 with budget outlay of Rs.1800 crore. The, IVFRT platform seeks to interlink and optimize functions related to immigration, visa issuance and registration of foreigners in India. The core objective of the IVFRT is to modernize and upgrade immigration and visa services within a secure and integrated service delivery framework. It aims to facilitate legitimate travellers while strengthening national security. This project was approved by the Cabinet Committee on Economic Affairs on 13.05.2010 with a budget outlay of Rs.1011 crore and with project duration till September, 2014. The budget outlay for the project was revised to Rs.638.90 crore in 2015 along with extension of the implementation timeline up to 31st March, 2017, and further up to 31st March, 2021 without any additional financial implications. The expenditure of Rs.613.28 core was incurred against the total revised outlay of Rs.638.90 crore. The extension of the project for a further continuation for a period of five years from 01.04.2021 to 31.03.2026 was approved by the Cabinet on 19.01.2022 with a budget outlay of Rs.1365 crore. The scheme seeks to expand and strengthen the scope and capacity of the existing IVFRT Scheme not only by reimagining and revamping the existing structure, but also introducing the state-of-the-art technological solutions to enhance user experience without compromising the security architecture.

The modernization of the IVFRT project is essential to meet the evolving demands of global travel and address emerging national security challenges. After the recent enactment of the Immigration and Foreigners Act, 2025 and its subsequent Rules and Order, it has become imperative to strengthen and modernize the Immigration, Visa, and Foreigners Registration & Tracking (IVFRT) system to effectively meet emerging requirements and future challenges in the domain of immigration control and foreigner management including illegal migration. The continuation of the project is not just a technical upgrade, but a strategic transformation aligned with the vision of the Government of India to promote international mobility through a world-class immigration and visa issuance system. The next phase would focus on three broad areas: (a) emerging technology innovations, (b) Transformation of Core infrastructure, and (c) Technology and service optimization. The scheme will modernize the immigration and visa ecosystem through adoption of emerging technologies, including mobile-based services and self-service kiosks for seamless and secure passenger movement. It will upgrade and expand core infrastructure across Immigration Posts, FRROs, and Data Centres to build a resilient and scalable system nationwide. Additionally, it will optimize technology and service delivery by introducing unified digital platforms, revamping core application architecture, and strengthening network and deployment frameworks for improved efficiency and user experience, which will facilitate legitimate travellers while strengthening national security. It will help maintaining service continuity and induct innovative technological solutions to attract more foreign tourists in India in future. This will thus give a boost to the tourism, medical and business sectors. IVFRT has immense positive externalities that would boost international traffic, business, commerce, and tourism. This would pave the way for economic growth and would thus contribute towards employment opportunities.

The scheme has covered 117 Immigration Posts (JPs), 15 Foreigners Regional Registration Officers (FRROs) and 854 Foreigners Registration Officers (FROs)/Superintendents of Police (SPs)/Deputy Commissioners of Police (DCPs) across the country. IVFRT system has led to significant improvements in service delivery and operational efficiency across immigration and visa functions. The system has enabled a 100% contactless and faceless visa process with online appointment scheduling and payment facilities, leading to faster visa processing times with 91.24% of e-Visa applications have been cleared within 72 hours during the past five years.

3rd Convocation Ceremony of Haridev Joshi University of Journalism, Jaipur

Journalists Should Strive to be 'Most Accurate,' Not Just 'First' to Report: Speaker Vasudev Devnani

Jaipur, Focus News: Vasudev Devnani, Speaker of the Rajasthan Legislative Assembly, has called upon journalists to act as a bridge between the government and society, discharging their duties with truth, impartiality, and responsibility. He urged young journalists to strive to be "the most accurate" in their reporting, rather than merely aiming to be "the first." Devnani was addressing the 3rd Convocation Ceremony of the Haridev Joshi University of Journalism and Mass Communication in Jaipur as the Chief Guest. He appealed to journalists to recognize their responsibilities amidst the looming global crises of the present era and to uphold the *Dharma* (ethical duty) of journalism with a spirit of "Nation First." This dignified ceremony, held at the Rajasthan International Centre, was presided over by the Governor of Rajasthan and Chancellor of the University, Shri Haribhau Bagde. The State's Deputy Chief Minister and Minister for Higher and Technical Education, Dr. Prem Chand Bairwa, served as the Guest of Honour. The ceremony was attended by numerous dignitaries, including the University's Vice-Chancellor, Prof. Nand Kishore Pandey. Addressing the gathering, Assembly Speaker Shri Vasudev Devnani stated that a convocation ceremony is not merely an occasion to receive a degree, but a symbolic testament to the trust that the nation and society repose in future journalists. He emphasized that journalism is not merely a profession, but a medium for dedicating oneself to the pursuit of truth and the service of society. He called upon young journalists to prioritize delivering "the most accurate" news over the urge to be "the first" to break a story.

Speaker Devnani remarked that the media constitutes the fourth pillar of democracy, serving as a vital bridge between the government and society. Citing the Emergency imposed in the country in 1975, he noted that during that tumultuous period, the press set a courageous precedent in defending freedom of expression by leaving their editorial columns blank—framed within black borders—as a mark of protest against censorship. Ultimately, it was democracy that triumphed.

He told journalists, "Recognize the power of your pen, for it does not merely write words; it shapes history." Referring to the current digital era, Mr. Devanani stated that the flow of information has become extremely rapid today, and in the age of Artificial Intelligence (AI), the very nature of journalism is undergoing rapid transformation.

RBI, IRDAI and SEBI Intensify Measures to Help Citizens Reclaim Unclaimed Deposits

New Delhi, Focus News: The Financial Sector Regulators namely, Reserve Bank of India (RBI), Insurance Regulatory and Development Authority of India (IRDAI), and Securities and Exchange Board of India (SEBI) have informed that as on 28.02.2026, the unclaimed amount transferred by Public Sector Banks (PSBs) to the Depositor Education and Awareness (DEA) Fund of RBI is ₹ 60,518 crore (as on 31.1.2026). Further, the unclaimed insurance amount outstanding with the insurers is ₹ 8,973.89 crore(as on 28.2.2026). Also, the value of unclaimed amounts in mutual funds under SEBI regulations is ₹ 3,749.34 crore(as on 28.2.2026). In order to ensure timely identification of rightful claimants, reducing both the existing stock of unclaimed financial assets as well as the fresh accretion to it and to simplify and expedite the claim process for citizens, various measures have been undertaken by the Financial Sector Regulators, including, inter alia, the following: The RBI has issued comprehensive directions on settlement of claims in respect of deceased customers of banks, now consolidated under the RBI Responsible Business Conduction Directions, 2025, and an incentive scheme effective from 1.10.2025 providing a payout of 5% - 7.5% of the unclaimed deposit amount (subject to a cap) for successful settlement of claims. Banks have also been advised to undertake periodic drives to trace depositors or nominees or legal heirs, publish lists of unclaimed deposits and conduct awareness campaigns. The Banking Laws (Amendment) Act, 2025 has enabled multiple nominations in bank accounts, including successive and simultaneous nominations up to four. Further, the Indian Banks' Association (IBA) has introduced a Common Application Form and SOP for settlement of unclaimed deposits through a dedicated portal of banks. IRDAI has informed that the collection of details of proposer as well as nominee are mandated and are required to be collected at the proposal stage itself. Insurers have been advised to initiate all possible measures to reach out to their customer regularly by sending advance intimation about their claims due and to enhance their efforts in tracing the rightful recipient of unpaid amounts and ensure efficient disbursement of the same. Further, the SOPs, FAQs and awareness videos are made available on IRDAI website. SEBI has introduced multiple measures to simplify transmission procedures, including promotion of nomination, simplified documentation for claims up to ₹5 lakh, and availability of detailed guidelines, including required forms and documents for various scenarios on the Association of Mutual Funds in India website. Further, as per as per SEBI's Master Circular on Mutual Funds, dated 27.6.2024, AMCs are required to implement the image-based processing for nominee/joint holder claims to improve turnaround time and establish a dedicated help desk and webpage to assist investors in the transmission process. Further, with the objective of enabling citizens to trace and claim their unclaimed financial assets in a simplified manner, the Department of Financial Services organised a nationwide campaign titled "आपकी पँजी, आपका अधिकार– Your Money, Your Right" during October– December 2025 in coordination with RBI, SEBI, IRDAI. Special camps were organised in 748 districts, and as on 28.2.2026, unclaimed financial assets amounting to ₹5,777 crore relating to 22.95 lakh claims have been restituted to their rightful owners. In terms of the DEA Fund Scheme, 2014, banks are mandated to transfer the credit balance in accounts which have not been operated upon for a period of 10 years or more, to DEA Fund. Further, the total amount of unclaimed deposits due to depositors which have been transferred to DEA Fund, form part of Contingent Liability (as off-balance sheet item) of the respective banks. RBI has developed the Centralised Web Portal UDGAM (Unclaimed Deposits – Gateway to Access InforMation), which facilitates the registered users to search unclaimed deposits/ accounts across multiple banks at one place. RBI has informed that as on 1.3.2026 there are 18.86 lakh registered users on the UDGAM Portal. IRDAI's Bima Bharosa portal and SEBI's MITRA platform have been developed for tracing unclaimed insurance proceeds and mutual fund amounts, respectively. Further, RBI has constituted an Inter-Regulatory Working Group to develop a single integrated web portal enabling citizens to search and claim their unclaimed financial assets. This information was given by the Minister of State in the Ministry of Finance Pankaj Chaudhary in Rajya Sabha.

Reform Linked MoUs signed with Andhra Pradesh and Odisha under Jal Jeevan Mission 2.0

New Delhi, Continuing the nationwide rollout of reform linked implementation under Jal Jeevan Mission 2.0; the States of Andhra Pradesh and Odisha today signed MoUs with the Union Government, committing to a structured reform framework for sustainable, transparent and community-led rural drinking water service delivery. In the presence of the Union Minister of Jal Shakti, Shri C. R. Patil, who attended the meetings physically at DDWS, Ministry of Jal Shakti, along with other senior officials. The MoU with Andhra Pradesh was signed in the presence in of the Chief Minister of Andhra Pradesh, Shri Nara Chandrababu Naidu, and Shri. K. Pawan Kalyan, Deputy Chief Minister of Andhra Pradesh and Minister for Panchayat Raj, Rural Development, Environment, Forest, and Science & Technology joined the event virtually along with senior officials from the state. For Andhra Pradesh, the MoUs were signed and exchanged between Smt. Swati Meena Naik, Joint Secretary (Water), DDWS, and Shri Shashi Bhushan Kumar, Special Chief Secretary to Government of Andhra Pradesh. Marking a key step in Centre-State collaboration, the MoU with the State of Odisha was formally signed at 12.30 p.m. in the virtual presence of Chief Minister of Odisha, Shri Mohan Charan Majhi, Minister of Rural Development, Panchayati Raj, Drinking Water, Govt. of Odisha, Shri Rabi Narayan Naik, Chief Secretary, Odisha, Smt. Anu Garg, Development Commissioner cum Addl. Chief Secretary, Shri Deoranjan Kumar Singh, Sri Sanjeeb Kumar Mishra, Finance Secretary and other senior officials from the State. The MoU was signed between Smt. Swati Meena Naik, Joint Secretary (Water), DDWS, and Shri Girish S.N, Commissioner cum Secretary, PR&DW Dept, and exchanged by Shri Visal Gagan, Principal Residence Commissioner, Government of Odisha. Addressing the gathering, Union Minister of Jal Shakti, Shri C. R. Patil highlighted that while crores of rural households have already been provided tap water connections under the Jal Jeevan Mission, the focus under JJM 2.0 is on addressing gaps in existing infrastructure, covering the remaining households, and ensuring sustainable and reliable water supply systems. He emphasised the importance of formal handover of completed schemes to communities through proper documentation and strengthening community-led water management systems to ensure effective operation and maintenance. He further stressed the need to empower women through training in water quality testing using Field Test Kits, noting that the mission has already freed nearly 9 crore women from the burden of fetching water, marking a significant social transformation. Expressing confidence in the leadership of the State, he stated that Andhra Pradesh is well-positioned to achieve the vision of Har Ghar Jal and contribute to Viksit Bharat 2047. He also highlighted the Prime Minister's emphasis on water use efficiency, including pilot initiatives for agriculture through pipeline-based supply and promotion of drip irrigation. He emphasised source sustainability through Jal Sanchay Jan Bhagidari (JSJB), promoting water conservation, ground water recharge and community participation. He further urged the State to convene regular review meetings with district collectors and officials to accelerate implementation and ensure timely utilisation of funds, while assuring full support from the Government of India for the successful implementation of the mission. Chief Minister of Andhra Pradesh, Shri Nara Chandrababu Naidu, along with the Deputy Chief Minister, reaffirmed the State Government's strong commitment to effective implementation of Jal Jeevan Mission 2.0. Expressing gratitude to the Prime Minister for extending the Mission timeline, they stated that this decision has enabled the State to move decisively towards universal household tap water coverage.

Meeting of Consultative Committee of Ministry of Heavy Industries held at New Parliament Building under Chairmanship of Kumaraswamy

New Delhi, Focus News: A meeting of the Consultative Committee of the Ministry of Heavy Industries was held in New Parliament Building, New Delhi under the chairmanship of the Union Minister for Heavy Industries & Steel, H.D. Kumaraswamy. The meeting was attended by Shri Kamran Rizvi, Secretary, Ministry of Heavy Industries; Dr. Anshu Bharadwaj, Project Director, NITI Aayog; and Shri K. Sadashiv Murthy, CMD, BHEL, along with senior officials of MHI, Niti Aayog and BHEL. During the meeting, Union Minister for Heavy Industries & Steel, Shri H.D. Kumaraswamy, said, "Guided by the visionary leadership of the Prime Minister, India is transitioning towards a sustainable future. 'Viksit Bharat-2047' is a comprehensive roadmap to transform India into a premier global manufacturing powerhouse and a high-value export hub. The focus is on positioning the nation as a critical node in global supply chains through indigenous innovation and large-scale manufacturing excellence. The vision is clear: Make in India, Make for the World." He also appreciated BHEL's contribution to nation-building. During the meeting, a detailed presentation on the progress of Vande Bharat was made by Shri K. Sadashiv Murthy, CMD, BHEL, highlighting significant developments and achievements in advancing indigenous manufacturing capabilities. This was followed by a presentation on "Transition to Sustainable Green Energy" by Dr. Anshu Bharadwaj, Project Director (Energy, Green Transition & Climate Change), NITI Aayog, which focused on India's strategic approach towards achieving a sustainable, low-carbon, and energy-efficient future. Members of the Committee actively participated in the deliberations and provided valuable insights and suggestions on the issues discussed.

Ministry of Culture and YouTube sign MoU to amplify and champion Indian Traditional Folk and Tribal Music on a global stage

New Delhi, Focus News: A Memorandum of Understanding (MoU) was exchanged by the Ministry of Culture, Government of India, with YouTube to promote and amplify Indian traditional folk and tribal music on a global stage in New Delhi today. Shri Gajendra Singh Shekhawat, Union Minister for Culture and Tourism, Shri Vivek Aggarwal, Secretary, Ministry of Culture and Smt. Gunjan Soni, Managing Director – India, YouTube graced the event. Union Minister for Culture and Tourism, Shri Gajendra Singh Shekhawat said that preserving and promoting India's diverse folk traditions is a core mission for the Ministry of Culture. This collaboration with YouTube represents a significant step forward in nurturing our creative economy and empowering our artists. Our goal is to ensure folk musicians have the tools and platforms needed to achieve greater visibility, sustainability, and recognition both nationally and globally, Union Minister added. Vivek Aggarwal, Secretary, Ministry of Culture said that, the Ministry's focus is on democratizing access so that folk artists from all corners of the country can proudly uphold their culture and traditions, while growing into independent creative entrepreneurs. Shri Aggarwal further added that by integrating YouTube's global reach with the Ministry's scaled infrastructure, the Ministry is not just providing a stage, but are helping lay the groundwork for millions of folk artists to become self-reliant and run successful endeavours.

Commenting on the announcement, Gunjan Soni, Managing Director - India, YouTube, said that YouTube is built to help artists and creators, from every corner of India, to share their talent with the world. Folk music is a vibrant part of India's rich cultural tapestry, and this partnership with the Ministry of Culture is an invaluable opportunity to preserve and amplify these essential traditions. She further mentioned that YouTube is thrilled to combine the Ministry's deep cultural engagement and IMOC's infrastructure with its unique capacity to support and showcase artists on a global platform and democratize access for creators everywhere. The goal is to empower these talented artists not just with digital skills, but with sustainable pathways to connect with new audiences worldwide, build thriving careers online, and ensure their invaluable art form resonates for generations to come, she added. The initiative is aimed at empowering the country's rich community of traditional and folk musicians by providing them with access to digital tools, knowledge systems, and wider audiences. It focuses on strengthening the ecosystem of Indian traditional and folk music through digital skilling, awareness of intellectual property rights, enhanced collaboration opportunities, and sustainable career pathways for artists. India's folk, tribal and traditional music heritage, while diverse and vibrant, has often faced challenges in terms of global visibility, digital distribution, and awareness of rights in the modern content landscape. This initiative seeks to bridge these gaps by facilitating structured training programs, access to infrastructure, and continuous institutional support. The Ministry of Culture will provide strategic leadership and oversight for the program, focusing on the folk music creative economy, with a joint task force guiding execution and impact assessment. Through the Ministry's selected autonomous institutions of art and performance, this initiative will provide access to facilities, including recording equipment where feasible, and regional connections, and will also co-develop localized educational materials and identify mentors.

Shivraj Singh Chouhan directs officials to speed up 'Farmer ID' implementation

New Delhi, Focus News: The Union Minister for Agriculture & Farmers' Welfare and Rural Development, Shri Shivraj Singh Chouhan convened an important review meeting at his residence today. The primary objective of the meeting was to safeguard the interests of the Indian agricultural sector and its farmers amidst current global instability, while ensuring strategic preparedness for the upcoming Kharif season. During the meeting, the Union Agriculture Minister gave clear instructions to the senior officials of the Ministry of Agriculture, stating that they must play a proactive role during times of crisis.

Fertilizer supply and Farmer ID: The Union Agriculture Minister Shivraj Singh emphasized the need to ensure an equitable and uninterrupted supply of fertilizers. He directed officials to expedite the work on 'Farmer IDs' to make the distribution system transparent. He further stated that he would soon hold a meeting with the chief ministers and agriculture ministers of various states for this purpose. Instructions have been issued to take strict action against those engaging in the black marketing of fertilizers and seeds by taking advantage of the global crisis. Shri Chouhan stated that state governments will also be encouraged to take stringent measures in this direction.

Seed production and packaging assistance: The meeting reviewed the availability of agro-chemicals and the essential gases required for Drying Seed. Agriculture Minister Shri Shivraj Singh Chouhan emphasized that there should be no shortage of packaging materials, particularly for milk and other agricultural products, amidst the global crisis. To ensure this, he also issued directives to coordinate with the Ministry of Petroleum and other relevant departments.

Formation of a Special Cell: A 'Special Cell' has been established for the round-the-clock monitoring of the agricultural sector. This cell will submit a weekly report to the Union Agriculture Minister regarding the availability of fertilizers, seeds and pesticides. In his closing remarks, Shri Chouhan reaffirmed the government's unwavering commitment to ensuring the timely delivery of all necessary agricultural resources to the farming community.

Department of Posts Partners with TRIFED to Boost E-Commerce of Tribal Products Across India

New Delhi, Focus News: In a significant step towards empowering tribal artisans and promoting indigenous products, the Department of Posts (DoP), Ministry of Communications, has entered into a Memorandum of Understanding (MoU) with the Tribal Cooperative Marketing Development Federation of India (TRIFED), under the Ministry of Tribal Affairs. The partnership aims to establish a robust, reliable, and cost-effective logistics framework to support the delivery of products sold through TRIFED's e-commerce platform, including the Tribes India e-marketplace. Under the MoU, the Department of Posts will provide end-to-end logistics solutions for all e-commerce orders placed through TRIFED's online channels. Leveraging its vast nationwide network and last-mile connectivity, Department of Posts will ensure seamless pickup, transmission, and delivery of tribal products to customers across the country. The collaboration is designed to strengthen market access for tribal artisans and entrepreneurs by enabling efficient order fulfilment and enhancing customer experience. The Department of Posts will also provide shipment tracking, regular MIS reporting, and API integration with TRIFED's digital platform to facilitate smooth order processing and logistics management. As part of the arrangement, a Book Now Pay Later (BNPL) account will be created for TRIFED under the National Account Facility, enabling streamlined booking and payment processes for shipments through Speed Post. TRIFED, on its part, will ensure proper packaging, labelling, and sharing of order-related information to facilitate efficient logistics operations. The initiative will cover pick-ups from multiple regional offices across the country, ensuring wide geographic coverage and operational efficiency. This partnership reflects the Government's commitment to promoting tribal livelihoods by integrating them into the digital economy. By strengthening logistics support for tribal e-commerce, the initiative is expected to enhance income opportunities for tribal communities, expand the reach of authentic tribal products, and contribute to inclusive economic growth.

Digital India BHASHINI Division and Pension Fund Regulatory and Development Authority Sign MoU for Multilingual Enablement in Pension Services

New Delhi, Focus News: The Digital India BHASHINI Division (DIBD), under the Digital India Corporation (DIC), Ministry of Electronics and Information Technology (MeitY), and the Pension Fund Regulatory and Development Authority (PFRDA) have signed a Memorandum of Understanding (MoU) under the initiative titled "BHASHINI for Seva / Sanchalan – A BHASHINI Sahayogi Program." The collaboration aims to strengthen multilingual digital capabilities within the pension fund services ecosystem through integration with the BHASHINI Platform, India's National Language Digital Public Infrastructure. The MoU establishes a framework for integrating BHASHINI translation APIs, multilingual AI models, and voice-enabled technologies with PFRDA systems to enhance language accessibility and improve communication across digital platforms and user interfaces in the pension sector. The initiative seeks to strengthen multilingual access across all 22 languages recognised under the Eighth Schedule of the Constitution of India within PFRDA's operational and communication frameworks, enabling greater inclusivity for subscribers and stakeholders.

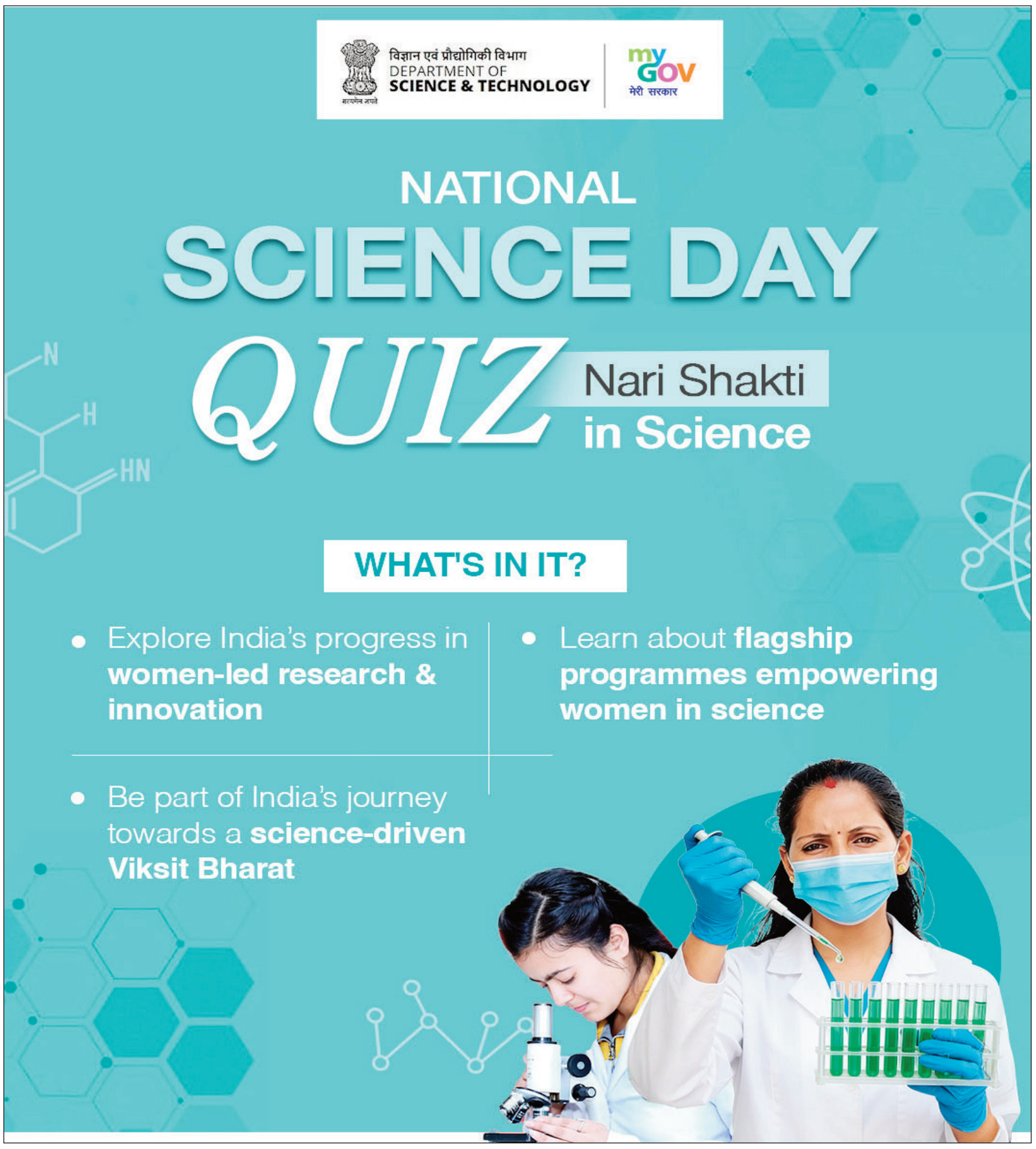

पश्चिम एशिया संघर्ष पर मुख्यमंत्रियों के साथ बैठक करेंगे मोदी, तैयारियों की समीक्षा करेंगे

नयी दिल्ली, फोकस न्यूज, प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी शुक्रवार को चुनाव वाले राज्यों को छोड़कर बाकी सभी राज्यों के मुख्यमंत्रियों के साथ पश्चिम एशिया संघर्ष के मद्देनजर उनकी तैयारियों और योजनाओं की समीक्षा के लिए बैठक करेंगे। सूत्रों ने यह जानकारी दी। यह पहली बार है जब प्रधानमंत्री पश्चिम एशिया संघर्ष को लेकर मुख्यमंत्रियों के साथ बैठक करेंगे। यह संघर्ष 28 फरवरी को अमेरिका और इजराइल द्वारा ईरान पर किए गए हमले के साथ शुरू हुआ था। ईरान ने भी खाड़ी के अपने पड़ोसी देशों और इजराइल पर हमले कर जवाबी कार्रवाई की है। सूत्रों ने बताया, ''प्रधानमंत्री कल शाम वीडियो कॉन्फ्रेंस के जरिये मुख्यमंत्रियों के साथ पश्चिम एशिया संघर्ष पर बातचीत करेंगे, ताकि राज्यों की तैयारियों और योजनाओं की समीक्षा की जा सके। इस बैठक का मुख्य उद्देश्य 'टीम इंडिया' की भावना के साथ प्रयासों में तालमेल सुनिश्चित करना होगा।'' जिन राज्यों में विधानसभा चुनाव होने जा रहे हैं, उन राज्यों के मुख्यमंत्री, आदर्श आचार संहिता लागू होने के कारण इस बैठक में शामिल नहीं होंगे। मंत्रिमंडल सचिवालय, चुनाव वाले राज्यों – तमिलनाडु, पश्चिम बंगाल, असम, केरल और केंद्र शासित प्रदेश पुडुचेरी के मुख्य सचिवों के साथ एक अलग बैठक करेगा। प्रधानमंत्री मोदी ने गत सोमवार को लोकसभा में कहा था कि पश्चिम एशिया में संघर्ष से पैदा हुए अप्रत्याशित संकट का प्रभाव लंबे समय तक रहने वाला है जिससे निपटने के लिए सरकार पूरी तरह तत्पर है। प्रधानमंत्री मोदी ने पश्चिम एशिया में जारी संघर्ष और इसके कारण भारत के सामने आई चुनौतियों पर वक्तव्य देते हुए यह भी कहा कि इस संकट का सामना देशवासियों को कोरोना संकट की तरह ही करना होगा। प्रधानमंत्री ने यह भी कहा कि पिछले तीन सप्ताह से अधिक समय से पश्चिम एशिया में जारी युद्ध के हालात ने भारत के सामने अप्रत्याशित चुनौतियां खड़ी कर दी हैं जो आर्थिक सुरक्षा, राष्ट्रीय सुरक्षा और मानवीय सुरक्षा से जुड़ी हैं। उन्होंने कहा, ''यह आवश्यक है कि भारत की संसद से इस संकट को लेकर एकमत और एकजुट आवाज में संदेश दुनिया में जाए।'' उसी दिन बाद में एक कार्यक्रम को संबोधित करते हुए प्रधानमंत्री ने कहा, ''कोविड–19 महामारी के बाद से चुनौतियां लगातार बढ़ती ही जा रही हैं। ऐसा कोई वर्ष नहीं बीता जिसने भारत और भारतीयों की परीक्षा न ली हो। लेकिन 1.4 अरब भारतीयों के एकजुट प्रयासों से भारत हर आपदा का सामना करते हुए आगे बढ़ रहा है।''

नए बिहार के लिए नीतीश कुमार का योगदान ऐतिहासिक, बिहार सदैव ऋणी रहेगा: नितिन नवीन

पटना, फोकस न्यूज, भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) के अध्यक्ष नितिन नवीन ने कहा कि नए बिहार के निर्माण के लिए मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने जो योगदान दिया है, उसके लिए राज्य सदैव उनका ऋणी रहेगा। उन्होंने कहा कि नीतीश कुमार ने नाउम्मीदी के दौर से निकालकर बिहार को विश्वास और विकास के मार्ग से जोड़ा तथा बिहारियों के सम्मान को लौटाने का काम किया है। यहां बापू सभागार में मुख्यमंत्री की 'समृद्धि यात्रा' के जनसंवाद कार्यक्रम को संबोधित करते हुए नितिन नवीन ने कहा कि नीतीश कुमार ने इसके जरिए बिहार में उत्सव का माहौल बनाया है और राज्य अब विकास के इस सफर में इसी उत्सव के वातावरण में आगे बढ़ेगा। उन्होंने कहा कि एक विधायक के तौर पर उन्हें मुख्यमंत्री के नेतृत्व में काफी कुछ सीखने का अवसर मिला है। उन्होंने कहा, "संभवतः एक विधायक के तौर पर यह मेरा आखिरी सरकारी कार्यक्रम हो, लेकिन पटना और बिहार के लोगों को विश्वास दिलाता हूं कि मुख्यमंत्री ने विकास को जो नया आयाम दिया है, उसे आने वाले दिनों में केंद्र सरकार की मदद से मैं और गति देने का काम करूंगा।" भाजपा नेता ने कहा कि 2005 में नीतीश कुमार ने बिहार में कार्य–संस्कृति स्थापित की। उन्होंने कहा कि उस समय सरकार के प्रतिनिधि जनता के प्रति कम जवाबदेह रहते थे और बिहार के हर घर में रोशनी पहुंचाने की कल्पना करना भी कठिन था। उन्होंने कहा कि आज लालटेन की जगह हर घर तक 'एलईडी' पहुंच चुकी है और सभी घरों में बिजली उपलब्ध है, जिसका श्रेय मुख्यमंत्री को जाता है। उन्होंने कहा कि पहले कहा जाता था कि सड़क है या गड्ढा। उन्होंने कहा कि नीतीश कुमार ने न केवल सड़कें बनाईं, बल्कि उनके रखरखाव की व्यवस्था भी की। उन्होंने कहा कि 2014 के बाद 'डबल इंजन' की सरकार बनने से बिहार को केंद्र का सहयोग मिला, जिसके लिए प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी का भी आभार है। भाजपा अध्यक्ष ने कहा कि पहले गंगा नदी पर एक ही पुल था, जबकि अब प्रधानमंत्री मोदी और मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के नेतृत्व में आधा दर्जन से अधिक पुल बने हैं, फलस्वरूप उत्तर और दक्षिण बिहार के बीच की दूरी कम हुई है और लोग राज्य के किसी भी हिस्से से कुछ घंटों में राजधानी पहुंच रहे हैं। नितिन नवीन ने कहा कि युवाओं को पहले शिक्षा और रोजगार के लिए बाहर जाना पड़ता था, लेकिन मुख्यमंत्री ने पिछले वर्षों में 50 लाख युवाओं को रोजगार देकर साबित किया है कि संकल्प को सिद्धि में बदला जा सकता है। उन्होंने कहा कि आज बिहार का युवा नौकरी लेने वाला नहीं, बल्कि देने वाला बन रहा है। उन्होंने कहा, "समृद्धि यात्रा का भले समापन हो रहा है, लेकिन मुख्यमंत्री ने विकास का जो रोडमैप दिया है, राजग सरकार उसी पर चलते हुए 2030 तक विकसित बिहार के सपने को साकार करेगी।" नितिन नवीन ने कहा कि पहले बिहार में 'जंगलराज' की चर्चा होती थी और लोगों को शर्मिंदगी का सामना करना पड़ता था, लेकिन अब परिस्थितियां बदल गई हैं और बिहार के लोगों को सम्मान मिल रहा है।

सिंहस्थ मेला: उज्जैन में घाट निर्माण कार्यों का मुख्यमंत्री मोहन यादव ने किया निरीक्षण

उज्जैन, मध्यप्रदेश के मुख्यमंत्री मोहन यादव ने उज्जैन में क्षिप्रा नदी के तट पर निर्माणाधीन घाटों का निरीक्षण किया और निर्देश दिए कि 2028 के सिंहस्थ कुंभ मेला से पहले श्रद्धालुओं के लिए सभी आवश्यक सुविधाएं विकसित की जाएं। आधिकारिक जानकारी के अनुसार, मुख्यमंत्री ने श्री अंगारेश्वर मंदिर से श्री सिद्धवट तक क्षेत्र का निरीक्षण किया। यहां स्नान और श्रद्धालुओं की सुविधाओं के लिए घाट तैयार किए जा रहे हैं। यादव ने निर्देश दिए कि नए घाटों से लगभग 200 मीटर के दायरे में कपड़े बदलने की सुविधा उपलब्ध कराई जाए और सुविधाजनक स्थानों पर शौचालय बनाए जाएं। मुख्यमंत्री ने यह भी कहा कि प्रमुख घाटों पर प्रत्येक 200 मीटर पर 'सुविधा घर' विकसित किए जाएं, जबकि सीढ़ियां और पहुंच मार्ग हर 500 मीटर पर बनाए जाएं।

बेटियों की शिक्षा और गौवंश संरक्षण राजस्थान सरकार की प्राथमिकता: सीएम भजनलाल शर्मा

जयपुर, फोकस न्यूज, राजस्थान के मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने कहा कि बेटियों की शिक्षा और गौवंश संरक्षण सरकार की प्राथमिकता है। उन्होंने कहा कि राज्य सरकार बाल विवाह उन्मूलन और बालिका शिक्षा के लिए प्रतिबद्धता के साथ काम कर रही है। मुख्यमंत्री जोधपुर के शिकारपुरा (लूणी) स्थित श्री राजाराम आंजणा आश्रम में आयोजित रामनवमी मेले तथा सिद्ध संत राजाराम जी महाराज के 144वें जन्मोत्सव को संबोधित कर रहे थे। उन्होंने कहा कि 'बेटी बचाओ, बेटी पढ़ाओ' योजना के अंतर्गत बालिकाओं का जन्मोत्सव मनाया जा रहा है। उन्होंने कहा कि राज्य में गौ संरक्षण का कार्य सर्वोच्च प्राथमिकता के साथ किया जा रहा है तथा राज्य की गौशालाओं को 3,400 करोड़ रुपये से अधिक का अनुदान दिया गया है। मुख्यमंत्री ने कहा कि एक लाख 37 हजार से अधिक निराश्रित गौवंश मवेशियों को अब सुरक्षित आवास में रखा जा रहा है। आधिकारिक बयान के अनुसार उन्होंने कहा कि धार्मिक स्थलों को सांस्कृतिक चेतना के केंद्र के रूप में विकसित किया जा रहा है। शर्मा ने कहा कि सनातन के गौरव भगवान श्रीराम मर्यादा के प्रतीक, सत्य के संवाहक, धर्म के रक्षक और सेवा के सर्वोच्च आदर्श हैं तथा उनका जीवन हमें सिखाता है कि चरित्र, कर्तव्य और करुणा का स्थान पद एवं प्रतिष्ठा से सदैव ऊंचा है।

रक्षा मंत्री डीआईबीईआर, डीएआरएल प्रयोगशालाओं को बंद करने की आशंकाएं दूर करें: अजय भट

पिथौरागढ़, (भाषा) नैनीताल के लोकसभा सदस्य अजय भट्ट ने रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह से उत्तराखंड और खास तौर से अपने निर्वाचन क्षेत्र के लोगों की यह आशंका दूर करने का अनुरोध किया है कि केंद्र सरकार हल्द्वानी में रक्षा जैव ऊर्जा अनुसंधान संस्थान (डीआईबीईआर) और भारत–चीन सीमा के अंदरूनी क्षेत्र में उससे संबंधित प्रयोगशालाओं को धीरे–धीरे बंद करने जा रही है। पूर्व केंद्रीय रक्षा राज्य मंत्री भट्ट ने कहा कि इन रक्षा अनुसंधान कृषि प्रयोगशालाओं (डीएआरएल) में फिलहाल कुछ कर्मचारी ही बचे हैं। उन्होंने बताया कि पिछले सप्ताह रक्षा मंत्री के हल्द्वानी भ्रमण के दौरान उन्होंने उन्हें इस संबंध में एक पत्र सौंपा है जिसमें उन्होंने कहा है कि डीआईबीईआर प्रयोगशालाओं को दिल्ली के तिमारपुर स्थित रक्षा शरीरक्रिया विज्ञान और संबद्ध विज्ञान संस्थान (डीआईपीएएस) से जोड़े जाने की चर्चाएं चल रही हैं और अगर ऐसा हुआ तो न केवल हिमालयी क्षेत्र के किसानों, स्थानीय बेरोजगार युवाओं और व्यापारियों के हित प्रभावित होंगे, बल्कि इससे क्षेत्र की शिक्षित प्रतिभाओं के इंटर्नशिप, जूनियर रिसर्च फैलोशिप एवं सीनियर रिसर्च फैलोशिप जैसे शैक्षणिक प्रयासों पर भी असर पड़ेगा। भट्ट ने कहा, ''डीएआरएल के स्थानांतरण से उच्च हिमालयी क्षेत्र के किसान उन बहुमूल्य कृषि सलाहों से वंचित हो जाएंगे जो उन्हें इन प्रयोगशालाओं में काम करने वाले वैज्ञानिकों से मिल रही हैं।'' भट्ट के मुताबिक, रक्षा अनुसंधान एवं विकास संस्थान (डीआरडीओ) के तहत स्थापित डीएआरएल के कई सेवानिवृत्त अधिकारियों से बातचीत करने के बाद उन्हें पता चला कि 1962 में चीन के साथ हुए युद्ध के बाद कृषि प्रयोगशालाओं की आवश्यकता महसूस की गई, ताकि सीमावर्ती क्षेत्र में अनाज और सब्जियों का उत्पादन बढ़ाया जा सके और वहां तैनात सैनिकों को खाद्य आपूर्ति के मामले में आत्मनिर्भर बनाया जा सके । नैनीताल के सांसद ने बताया कि डीएआरएल की प्रयोगशालाएं अल्मोड़ा, हल्द्वानी, पिथौरागढ़, औली और हर्षिल में हैं जहां स्थानीय भूभागों में अधिक उत्पादन प्राप्त करने के तरीकों पर शोध कार्य चल रहा है। पत्र में भट्ट ने सुझाव दिया कि इसकी बजाय तिमारपुर में स्थित डीआईपीएएस को पिथौरागढ़, औली और हर्षिल के भीतरी सीमावर्ती क्षेत्रों में स्थानांतरित कर दिया जाना चाहिए जिससे वह सीमावर्ती क्षेत्रों के लोगों की शरीरक्रिया का अध्ययन कर सके।

Share your Ideas & Suggestions with the PM's

mygov मेरी सरकार

Mann Ki Baat

on 29th March, 2026

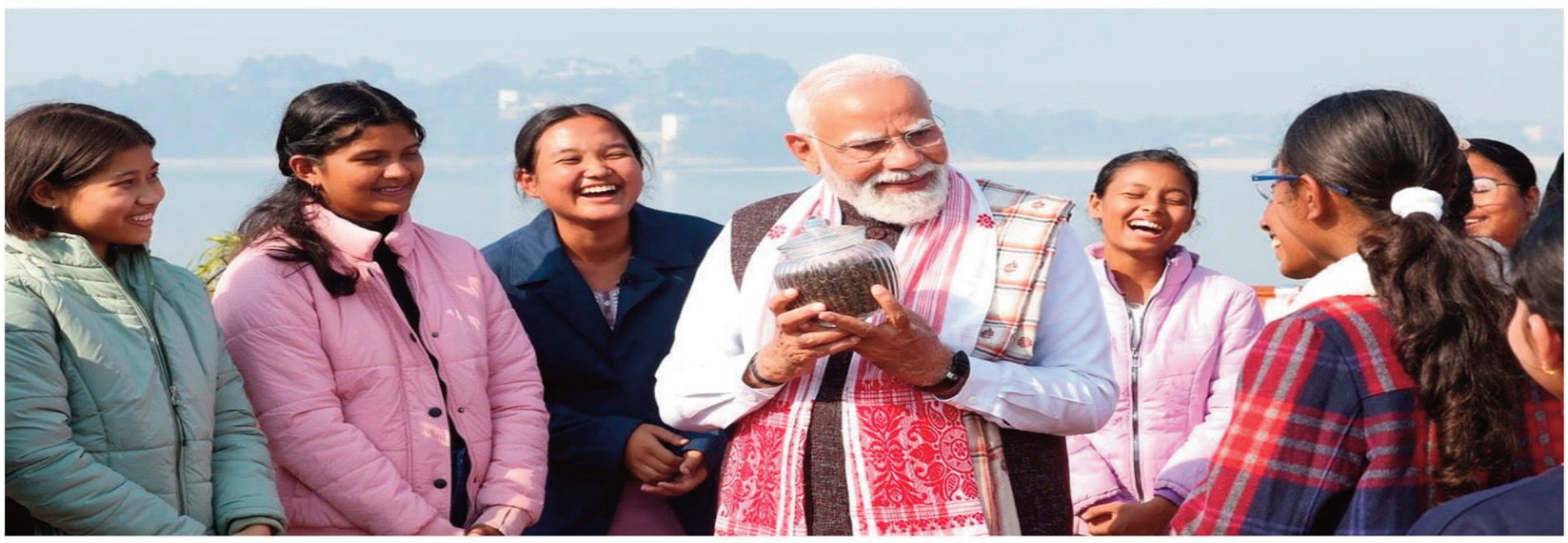

visit MyGov.in or

Dial 1800 11 7800 (Toll-Free)

The phone lines shall remain open from 3rd - 27th March 2026